सूर्योदय 6.10 सूर्यास्त 6:17

आज का तापमान

शिमला	15.6 न्यू	25.0 अधि
धर्मशाला	16.2 न्यू	30.1 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,529
निफ्टी	23,329

सोना 1,52,000 चांदी 2,33,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 7 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 149, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

बिहार में लड़की को बैड टच करने वाले का एनकाउंटर

एजेंसी, जमुई। बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव का पुलिस ने एनकाउंटर किया। उसने मंगलवार को पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो आरोपी उसी मड़वा पहाड़ी के आसपास छिपा हुआ था, जहां दोनों स्टूडेंट घूमने गए थे। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में लाल गमछा पहने दिख रहा युवक नंदन है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपियों की उम्र 35 से 40 साल हैं, जबकि तीन नाबालिग हैं। इसके अलावा वीडियो वायरल करने वाले 3 आरोपी हैं।

अमेरिकी चैनलों ने ट्रंप की लाइव कवरेज रोकी

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका के बड़े टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रमों की साझा लाइव कवरेज रोक दी है। यह फैसला व्हाइट हाउस की ओर से सीएनएन, एमएस नॉव और पॉलिटिको के पत्रकारों पर बैन के के बाद लिया गया। फॉक्स न्यूज के वॉशिंगटन ब्यूरो चीफ ब्रायन बॉटन ने सोमवार को बताया कि अब इस व्यवस्था के तहत आने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की वीडियो कवरेज नहीं की जाएगी। इसके बाद व्हाइट हाउस ने अपनी ऑनलाइन वीडियो फीड शुरू की, जिसका नाम 'ट्रंप टीवी' रखा गया है। इसमें ट्रंप के पुराने वीडियो, सरकार के ऐलान और ताजा अपडेट दिखाए जाएंगे। लोग व्हाइट हाउस के लाइव कार्यक्रम भी फोन और दूसरे इंटरनेट वाले डिवाइस पर देख सकेंगे।

त्योहारों में हवाई किरायों पर कैप नहीं लगाएगी सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली। त्योहार के इस मौसम में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए फ्लाइट बुक करते हैं। ऐसे में मांग बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फेस्टिव सीजन में हवाई किराये पर कोई प्राइस कैप यानी अधिकतम सीमा तय नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार एयरलाइंस से किराया उचित और यात्रियों की पहुंच में रखने की अपील जरूर करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है और त्योहारों के दौरान उचित किराया रखने के लिए उनसे बातचीत की जाएगी।

शरजील इमाम को 7 दिन की जमानत मिली

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे चार अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक के लिए राहत दी है। इससे पहले इस साल मार्च में भी इमाम को अंतरिम जमानत दी गई थी। उस समय दिल्ली की एक अदालत ने उसे अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

धार्मिक वजह से वंदेमातरम न गाना अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ता बोला- इसमें हिंदू देवताओं का जिक्र; कानून पर केंद्र से जवाब मांगा

एजेंसी, नई दिल्ली। वंदे मातरम गीत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, 'धार्मिक कारणों से राष्ट्रगीत न गाने वाले व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए।' कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने यह देखने पर सहमति दी कि वंदे मातरम न गाने को दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने यह तय करने से इनकार किया कि राष्ट्रगीत केवल दो अंतरों तक सीमित रहेगा या छह अंतरों तक होगा। कानून में वंदे मातरम के गायन को रोकने या गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय बनाया गया है।



◆ वंदे मातरम के दो या छह अंतरों पर फैसला करने से कोर्ट का इनकार

यह सुनवाई गायक टीएम कृष्णा की याचिका पर हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अंतिम चार पैरा हिंदू देवताओं के प्रति भक्ति का आह्वान करते हैं। वंदे मातरम को कानून के दायरे में लाने वाला संशोधन बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ था। इसके बाद 6 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून बन गया।

दिल्ली एसआईआर : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी यानी रिकॉर्ड में गड़बड़ी के तहत मतदाताओं को नोटिस देने का आधार पूछा। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 47 लाख नाम हटाए गए हैं। जबकि करीब 33 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में बने हुए हैं। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने आयोग से यह जांचने को कहा कि कहीं बिना पर्याप्त जांच के तो नोटिस नहीं भेजे जा रहे। नोटिस में वोटर्स को आपत्ति की सही वजह बताई जा रही है या नहीं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मतदाता को नोटिस में साफ बताया जाना चाहिए कि किस जानकारी या रिकॉर्ड में अंतर मिला है और उसे क्या स्पष्ट करना है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को अब तक उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, बिहार और पश्चिम बंगाल एसआईआर मामलों में दिए अंतरिम निर्देशों का पालन करने को कहा।

एशियन गेम्स : भारत को पहला गोल्ड, महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया



एजेंसी, आइची-नगोया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। टीम ने मंगलवार को फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। भारत ने 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रन बनाए। यह एशियन गेम्स में भारतीय विमेंस टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। 217 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई। थर्ड प्लेस के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 79, ऋचा घोष ने नाबाद 49 और शेफाली वर्मा ने 48 रन की पारी खेली। मंधाना और शेफाली के बीच पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी हुई। मंधाना ने इस पारी के दौरान विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 हजार रन भी पूरे किए।

दीप्ति ने झटके 3 विकेट

श्रीलंका की टीम 15.4 ओवर ही खेल सकी। चामरी अटापट्टू ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए, जबकि कौशिनी नुथ्यांगना ने 14 और कविशा दिलहारी ने 11 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी को भी 2-2 विकेट मिले। श्रीलंका के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।

जमानत मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने दें : हाईकोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि जमानत मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने की। मिलन प्रधान नंदीग्राम उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। प्रधान पर 11 केस दर्ज हैं। उन्हें 5 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वे जेल में हैं। हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर को 4 मामलों में 3 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये मामले 2007 के नंदीग्राम से जुड़े हैं। इसके बाद 21 सितंबर को कांथी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के करीब दो दशक पुराने मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नंदीग्राम उपचुनाव की वोटिंग 6 अक्तूबर को है, प्रचार 4 अक्तूबर को खत्म होगा और वोटों की गिनती 9 अक्तूबर को होगी। दोनों निचली अदालतों के आदेशों से प्रधान के लिए खुद प्रचार करने का मौका लगभग खत्म हो गया है।

देश से मादक पदार्थों के कारोबार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य : अमित शाह

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 31 दिसंबर 2029 तक देश से मादक पदार्थों के कारोबार को सामूहिक प्रयासों से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई करनी होगी।



शाह ने यहां मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में केवल जब्ती पर ध्यान देने के बजाय पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में लक्ष्य, समयसीमा और जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के कारोबार से निपटने के लिए 'बैठक से मिशन', 'रिपोर्टिंग से परिणाम', 'जब्ती से नेटवर्क के खात्मे' और 'मामले से दोषसिद्धि' की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने एएनटीएफ को 'एंटी-नार्को मिशन कमांड' के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया। शाह ने कहा कि जिले को मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की मूल इकाई बनाया जाना चाहिए। इसके तहत जिलों को मादक पदार्थों के उत्पादन एवं प्रवेश वाले क्षेत्रों, परिवहन गलियारों और उपभोग वाले क्षेत्रों के तीन समूहों में बांटकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वित्तीय और डिजिटल जांच को भी प्राथमिकता देने की बात कही।

◆ कहा- नशे के नेटवर्क पर प्रहार, जब्ती के बजाय पूरे तंत्र को ध्वस्त करने पर जोर

कार्तिक बेस्ट एक्टर, यामी को बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड





एजेंसी, गुजरात। कार्तिक आर्यन को 'चंदू चैंपियन' और ममूटी को 'ब्रह्मयुग' के लिए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया।

सेरेमनी गुजरात के एकता नगर (केवडिया) में मंगलवार को हुई। विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई को हुई थी। 'श्रीकांत' को बेस्ट हिंदी फिल्म और 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला। तमिल स्टार धनुष को दो कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड दिया गया। एक्टर अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड 2024 दिया गया। उन्होंने कन्नड़, तेलगु और हिंदी समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1954 में नेशनल फिल्म अवॉर्ड सिर्फ 7 पुरस्कारों से शुरू हुए थे, अब 72 साल बाद 45 पुरस्कार दिए गए। इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन-फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड शामिल है।

फेमस स्टार हानिकारक चीजों का प्रचार न करें : मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- मैं चाहूंगी कि प्रत्येक ज्यूरी पैनल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट न करें। स्टार वही है, जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं।

तेलंगाना के अस्पताल में आग से तीन नवजात की मौत, 27 बच्चे थे एडमिट



एजेंसी, हैदराबाद। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के सरकारी आरआईएमएस अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सोमवार रात करीब 11:50 बजे आग लग गई। हादसे में अब तक 3 नवजात की मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर है।

अधिकारियों के मुताबिक, यूनिट में 27 नवजात का इलाज चल रहा था। हादसे के बाद 24 बच्चों का अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी में एसी में खराबी के बाद धमाके की आशंका जताई गई है। हालांकि, सही वजह जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस साल अस्पतालों में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है। इनमें ओडिशा के कटक में 12 मरीज, बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 मरीज, महाराष्ट्र के अमरावती में 3 नवजात, तेलंगाना के आदिलाबाद में 3 नवजात, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1 नवजात और उत्तराखंड के देहरादून में एक मरीज शामिल है।

अधिकारियों के मुताबिक, आग में सबसे पहले एक 5 दिन के बच्चे की मौत हुई थी। दूसरे नवजात की मंगलवार सुबह निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीसरे बच्चे ने दोपहर में दम तोड़ा। अब 24 बच्चों का इलाज जारी है। इनमें एक की हालत गंभीर है। बाकी बच्चों की सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नवजात की मौत पर दुख जताया। उन्होंने इलाज करा रहे बच्चों को बेहतर और एडवांस मेडिकल केयर देने और उनकी हालत पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।

कार्यकर्ता सेवा संकल्प अभियान के जरिए सुशासन को घर-घर पहुंचाएं : सीएम सैनी

एजेंसी, पंचकूला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय 'पंचकमल' में मंगलवार को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुनील सेन का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे। वहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक ओबीसी समाज की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में दायित्व कोई पद नहीं, बल्कि जनसेवा और संगठन के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि



7 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में शासन के माध्यम से सेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कार्यकर्ता 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' में सक्रियता से भाग लें और पीएम मोदी के सुशासन को हर घर तक पहुंचाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए इस मोर्चे की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली, सांसद धर्मबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक विनोद, सुनील सांगवान, तेजपाल तंवर, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, प्रदेश महामंत्री संगठन फणीन्द्रनाथ शर्मा, गोपाल शर्मा और प्रदेश मंत्री मदन चौहान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ कॉल और एसएमएस वाले सस्ते रिचार्ज प्लान जारी करने के आदेश

एजेंसी, नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ताओं, खासकर कम आय वाले लोगों को राहत देते हुए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को केवल कॉल और एसएमएस सुविधाओं वाले सस्ते रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे, ताकि डेटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले ग्राहकों को भी अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प मिल सकें। दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। ट्राई ने पाया था कि पिछले संशोधन के बाद अधिकांश कंपनियां लंबी वैधता वाले वॉयस और एसएमएस पैक ही दे रही थीं, जिससे कम अवधि और कम कीमत वाले विकल्प सीमित हो गए थे।

अत्याचार प्रभावितों को समय पर न्याय और सहायता सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लंबित मामलों की समयबद्ध विवेचना और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अत्याचार से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय, सुरक्षा, सम्मान और उसके अधिकार मिलना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समिति की बैठक केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।



व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने वर्ष 2024 से अब तक लंबित विवेचनाओं के कारणों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करने को कहा। गंभीर और लंबे समय से लंबित मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग को समन्वय से कार्रवाई करने तथा विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। प्रभावी पैरवी के लिए जरूरत के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। धामी ने पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि के भुगतान में देरी नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और अन्य पात्र सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए। गंभीर मामलों में पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन में लिया हिस्सा

सीएम रेखा ने सम्मेलन में आध्यात्मिक संदेश सुना

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आठ दिवसीय 30वें विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सावन कृपाल रूहानी मिशन के प्रमुख संत राजिंदर सिंह जी महाराज से मुलाकात की। किरपाल बाग और संत दर्शन सिंह जी धाम बुराड़ी में आयोजित इस सम्मेलन में रूहानी मिशन के प्रमुख का 80वां जन्मदिवस भी मनाया गया।



तेरह सितंबर से शुरू इस आठ दिवसीय आयोजन में दो लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक अशोक गोयल, विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेता और 650 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में ध्यान और आध्यात्मिकता पर विचार-विमर्श के साथ 68वां रक्तदान शिविर, 43वां निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और 23वां वस्त्र वितरण शिविर आयोजित किया गया।

सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, कनाडा और कई अन्य देशों से 650 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। समापन अवसर पर संत राजिंदर सिंह जी महाराज ने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ने और ईश्वर से जुड़ने के लिए का मुख्य जरिया बताया। उन्होंने कहा कि भटकाने वाली चीजों से भरी इस दुनिया में हमें ईश्वर से जुड़ने और जीवन के सच्चे मकसद को जानने और ईश्वर को पाने को पूरा करने के लिए अपने भीतर झांकना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संत राजिंदर सिंह महाराज को जन्मदिन पर बधाई दी। साथ ही ध्यान, शांति व मानवता की सेवा के प्रति उनके दशकों लंबे समर्पण की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बारे में जितना ज्यादा वह जानती हैं, वह यह है कि इंजीनियरिंग से आध्यात्मिकता तक की उनकी अद्भुत यात्रा प्रभावित करती है।

आयोजन | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन हजार 567 चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

योग्य युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित तीन हजार 567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले आवेदन नहीं करने वाले भी पीछे के दरवाजे से नियुक्ति पत्र पा जाते थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। सैफई सिंडिकेट सरकारी नौकरियों पर डाका डालता था। अब उप्र बदल रहा है। यहां योग्य युवाओं को नौकरी मिल रही है।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तीन हजार 567 प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित



अभ्यर्थियों को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांकेतिक रूप से 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हमारे लिए विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आज यह केवल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं है, 3567 लोगों का चयन करके प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का अवसर है। योगी ने कहा कि अगर एक शिक्षक प्रति वर्ष 100 छात्रों के साथ इंटरैक्शन करता है तो तीन लाख से अधिक छात्रों से संपर्क हो जाएगा। तक्षशिला और नालंदा के जमाने में भारत विश्वगुरु था। भारत के पास वह धरोहर आज भी है। जरूरत है उसे समझने की।

सरकार व्यवस्था दे सकती है लेकिन उसे पूरा करने का कार्य आपके द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी ही करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले आवेदन नहीं करने वाले भी पीछे के दरवाजे से नियुक्ति पत्र पा जाते थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। सैफई सिंडिकेट सरकारी नौकरियों पर डाका डालता था। आज योग्य छात्र नौकरी पा रहे हैं। आज उप्र की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आप सब उसके साक्षी होने जा रहे हैं। बेसिक में जर्जर भवन थे। पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आपरेशन कायाकल्प से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब लोगों में यह भावना आ रही है कि स्कूल के पास खेल का मैदान भी हो।

यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में प्रोजक्ट अलंकार के तहत 2300 विद्यालयों में भवन ठीक किए गए हैं। डेढ़ हजार से अधिक सरकारी इंटर कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जा चुका है। यह काम 2017 के पहले भी हो सकता था। लेकिन उनकी रुचि नहीं थी। उनके पास विजन भी नहीं था। उनका अपना सीमित एजेंडा था। उन्हीं सीमित एजेंडे के साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया करते थे। आज यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। उप्र में असीम संभावनाएं हैं। उसे आगे बढ़ाने का दायित्व शिक्षकों पर है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवचयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग में कोई रुकावट न पैदा करे। अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पीएम मोदी के नेतृत्व में चंबा की सड़क परियोजना को मिला रणनीतिक दर्जा

हर्ष महाजन ने कहा- परियोजना से चुराह, पांगी और किलाड़ की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने चंबा-किलाड़ सड़क को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की सूची में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि इससे चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। परियोजना के विकास और रखरखाव की व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होगी।



महाजन के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 13 अगस्त 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की सूची जारी की है। इसमें देशभर की 11 सड़क परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें सात परियोजनाएं प्राथमिकता-एक और चार परियोजनाएं प्राथमिकता-दो श्रेणी में रखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश से संबंधित चंबा-किलाड़, खानागुंती-लामखागा दर्रा-हरसिल और वांगतु-मुड-अट्टरगू सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता-दो में स्थान दिया गया है।

उन्होंने बताया कि चंबा-किलाड़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रावधान किया गया है। ज्ञापन में नई सड़क के निर्माण पर विचार करने और किलाड़ तक निर्माणाधीन सड़क के साथ प्रस्तावित मार्ग का संरेखण निर्धारित करने का भी उल्लेख है। परियोजनाओं के विकास और रखरखाव की व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्ट्रैटेजिक रोड हेड फंड के माध्यम से किए जाने की बात कही गई है। संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सीमा सड़क संगठन की भी भूमिका रहेगी।

महाजन ने कहा कि चंबा-किलाड़ मार्ग चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण सड़क संपर्क प्रभावित होता रहता है। इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आवागमन में परेशानी होती है।

रणनीतिक सड़क परियोजना के रूप में शामिल होने के बाद इस मार्ग के विकास से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी सुविधा मिल सकती है। बेहतर सड़क संपर्क से आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को भी सुगम बनाने में मदद मिलने की संभावना है।

पेंशनर्स ने सरकार पर लंबित वित्तीय लाभों को लेकर गुमराह करने का लगाया आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर पेंशनर्स की मांगों को लेकर बार-बार घोषणाएं कर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया है। समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंदर पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने शिमला से जारी संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ बैठक की। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के माध्यम से पेंशनर्स को अलग-अलग समूहों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे संगठन स्वीकार नहीं करेगा।



पेंशनर्स नेताओं ने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 43 हजार पेंशनर्स संशोधित वित्तीय लाभों से वंचित हैं। उनके अनुसार इन पेंशनर्स को लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, वेतन एरियर और पेंशन एरियर सहित विभिन्न देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ है।

समिति ने कहा कि करीब पांच लाख पेंशनर्स और कर्मचारी लंबे समय से 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए पेंशनर्स को धरना-प्रदर्शन और रैलियां करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नेताओं ने सरकार की ओर से पेंशन एरियर के संबंध में जारी की जा रही अधिसूचनाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे पेंशनर्स में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

समिति नेताओं ने कहा कि सरकार पेंशनर्स के धैर्य की परीक्षा न ले। उन्होंने आने वाले दिनों में ब्लॉक और जिला स्तर पर जनजागरण अभियान चलाने की बात कही। उनका कहना है कि अभियान के माध्यम से पेंशनर्स की लंबित मांगों और समस्याओं को जनता के सामने रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और सभी लंबित देनदारियों का भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। समिति ने सरकार से पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने की मांग की। प्रेस वार्ता में गंगा राम शर्मा, बुद्धि राम जस्टा, सैन राम नेगी, लायक राम शर्मा, मोहन ठाकुर, मदन शर्मा, दीप राम शर्मा, गुलाब ठाकुर, नीलम चौहान, यशपाल ठाकुर और रमेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

शिमला में 480 ग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला के कनलोग क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 480 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर को विशेष सेल की टीम कनलोग एनएच क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर दो लोगों की जांच की गई। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से करीब 480 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान सुन्नी तहसील निवासी जटिलेंद्र ठाकुर (28) और मेहर चंद (35) के रूप में हुई है। बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यू शिमला थाने में मामला दर्ज किया। आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है।

लक्ष्य पार कर भाजयुमो ने जुटाया 1718 यूनिट रक्त, 2500 कार्यकर्ताओं ने लिया भाग



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) हिमाचल प्रदेश के प्रदेशव्यापी रक्तदान महाअभियान में निर्धारित लक्ष्य से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 'सेवा, समर्पण और संकल्प' अभियान के तहत आयोजित शिविरों में 1675 यूनिट के लक्ष्य के मुकाबले कुल 1718 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में 2500 से अधिक भाजयुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष सन्नी शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि अभियान में लक्ष्य से 43 यूनिट अधिक रक्त एकत्रित हुआ।

पीएम श्री स्कूलों के 90 बच्चे लखनऊ-अयोध्या की विरासत से होंगे रूबरू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कक्षा और किताबों से बाहर सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा के तहत हिमाचल प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों के 90 विद्यार्थियों को चार दिवसीय लखनऊ और अयोध्या भ्रमण पर भेजा गया है। शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों के विद्यार्थी चंडीगढ़ से हवाई यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचे।



लखनऊ पहुंचने के बाद विद्यार्थियों ने जूलॉजिकल गार्डन और साइंस सिटी का भ्रमण किया। जूलॉजिकल गार्डन में उन्होंने विभिन्न वन्यजीवों को करीब से देखा और जैव विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जानकारी हासिल की। साइंस सिटी में विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझा।

नवाबी वास्तुकला और विरासत से होंगे परिचित : लखनऊ प्रवास के दौरान विद्यार्थी रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा भी जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण से उन्हें लखनऊ की वास्तुकला, नवाबी दौर के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी स्थानीय पीएम श्री स्कूल का भी भ्रमण करेंगे और वहां की शैक्षणिक गतिविधियों, सुविधाओं तथा कार्यप्रणाली की जानकारी लेंगे।

कार्यक्रम में आनंदी मैजिक वर्ल्ड और हस्तशिल्प केंद्र का भ्रमण भी शामिल है। यहां विद्यार्थी मनोरंजक गतिविधियों के साथ पारंपरिक कला और शिल्प को करीब से देख सकेंगे।

अयोध्या में राम जन्मभूमि का करेंगे भ्रमण : लखनऊ के बाद विद्यार्थी अयोध्या जाएंगे, जहां राम जन्मभूमि का भ्रमण करेंगे। इस दौरान उन्हें देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रत्यक्ष रूप से जानने-समझने का अवसर मिलेगा। किताबों में पढ़े गए ऐतिहासिक स्थलों को सामने से देखना विद्यार्थियों के लिए सीखने का अलग अनुभव होगा।

समग्र शिक्षा के तहत अब तक पीएम श्री स्कूलों के 286 विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट का अवसर मिल चुका है। पहले बैच में ऊना, चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर के 84 विद्यार्थी 10 से 13 सितंबर तक लखनऊ-अयोध्या गए थे। दूसरे बैच में मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के 112 विद्यार्थियों ने 15 से 18 सितंबर तक भ्रमण किया। अब तीसरे बैच के 90 विद्यार्थी यात्रा पर हैं।

हिस्कागा के त्रैवार्षिक चुनाव में गिरीश जुयाल बने राष्ट्रीय अध्यक्ष



भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड्स के त्रैवार्षिक चुनाव में गिरीश जुयाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में देश के 17 राज्यों से आए राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने मतदान किया। करुणाकर प्रधान को राष्ट्रीय सभापति के रूप में लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी मिली, जबकि मधुसूदन गुप्ता राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त पद पर पुनर्निर्वाचित हुए।

जम्मू की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित चुनाव प्रक्रिया भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित निर्धारित नियमों के तहत संपन्न हुई। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जम्मू-कश्मीर के राज्य निदेशक एवं बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनील श्रीवास्तव मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता अतुल गौतम और रागिनी शर्मा ने मतदान प्रक्रिया में चुनाव अधिकारियों के रूप में भूमिका निभाई। राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयुक्त यतेंद्र कुमार सक्सेना ने चुनाव प्रक्रिया के संचालन में सहयोग किया।

चुनाव में अरोड़ा, वनिता शर्मा, डॉ. एम. रजनी, अवधेश शर्मा, दीपक कलिता और डॉ. ओम प्रकाश श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगामी तीन वर्षों में संस्था के विस्तार और गतिविधियों को गति देने की बात कही।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय सभापति डॉ. करुणाकर प्रधान ने अध्यक्ष गिरीश जुयाल की उपस्थिति में संगठन के आगामी कार्यों पर चर्चा की। बैठक में डॉ. वेद प्रकाश सिंह को महासचिव, डॉ. अतुल कुमार को वरिष्ठ संयुक्त सचिव तथा ममता चौहान को संयुक्त सचिव (गाइड्स) के रूप में अगले त्रैवार्षिक कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया।

शांकली में बच्ची पर कुत्तों के हमले के बाद नगर निगम को सौंपा ज्ञापन

सात दिन में मांगें पूरी नहीं हुईं तो नागरिक सभा ने आंदोलन की दी चेतावनी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शांकली में दो वर्षीय बच्ची पर कुत्तों के हमले की घटना को लेकर शिमला नागरिक सभा ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नागरिक सभा का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। सभा ने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा।



नागरिक सभा ने मांग की कि कुत्तों के हमले में घायल बच्ची के उपचार का पूरा खर्च नगर निगम अथवा प्रशासन वहन करे। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी की गई। सभा ने कहा कि शिमला शहर में आवारा कुत्तों के साथ बंदरों और लंगूरों की समस्या भी लगातार गंभीर होती जा रही है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को इनके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में शहर में विशेष नसबंदी एवं रेबीज टीकाकरण अभियान चलाने, कम से कम पांच प्रभावी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने और निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की मांग की गई। इसके अलावा आक्रामक कुत्तों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई, आपातकालीन हेल्पलाइन और वार्ड स्तर पर निगरानी समितियां गठित करने की मांग रखी गई।

नागरिक सभा ने नगर निगम की ओर से की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की। साथ ही कुत्तों, बंदरों और लंगूरों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम, वन विभाग, पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त उच्चस्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया।

शिमला के दिनेश भट्ट बने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला निवासी और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति हुई। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ग्रहण की।



न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट का जन्म वर्ष 1969 में शिमला में हुआ। उन्होंने सेंट एडवर्ड्स स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद संजौली कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से वर्ष 1993 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू की।

वर्ष 2008 में उनका चयन दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर हुआ। चयन परीक्षा में उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में करीब 16 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न अदालतों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं।

जुब्बल मंदिर से मूर्ति, दानपात्र और नकदी चोरी

पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपित की तलाश में जांच शुरू की

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में देवता खोड़ के मंदिर से अज्ञात व्यक्ति मूर्ति, दानपात्र और नकदी चोरी कर ले गया। घटना 17 से 20 सितंबर के बीच की बताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरी की गई मूर्ति और अन्य सामान की बरामदगी के साथ आरोपित की पहचान करने में जुटी है।



पुलिस के अनुसार जुब्बल थाना क्षेत्र के मंडल गांव निवासी नारायण सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि गांव में देवता खोड़ का मंदिर स्थित है। 17 सितंबर को गांव के लोगों ने मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। इसके बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था।

शिकायत के अनुसार 20 सितंबर को दिन के समय नारायण सिंह मंदिर के समीप अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर मंदिर के खुले दरवाजे पर पड़ी। संदेह होने पर वह मंदिर के अंदर गए तो वहां देवता खोड़ की मूर्ति और दानपात्र गायब मिला। दानपात्र में करीब 350 रुपये की नकदी रखी हुई थी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि चोरी 17 सितंबर को पूजा होने के बाद और 20 सितंबर के बीच किसी समय हुई होगी। चोरी हुई देवता खोड़ की मूर्ति पीतल जैसी धातु से बनी हुई बताई गई है। मूर्ति, दानपात्र और नकदी समेत चोरी हुए सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 35 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सरस्वती नगर पुलिस चौकी के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक प्यारे सिंह को सौंपी गई है।

पुलिस मंदिर के आसपास की गतिविधियों और घटना से जुड़े संभावित सुरागों की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के दौरान मंदिर के आसपास कौन-कौन लोग मौजूद थे। पुलिस ने चोरी की गई मूर्ति, दानपात्र और नकदी की बरामदगी के लिए जांच तेज कर दी है।

न्यायादेश कर्मचारी की शिकायतों को अभिव्यक्ति का अवसर देना संगठनात्मक सुधार में सहायक बताया गया

निजी वाट्सऐप संदेश पर बर्खास्त कंडक्टर को हाई कोर्ट से राहत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी के अनुबंध आधारित कंडक्टर सुनील कुमार की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को अपने संगठन या प्रबंधन से जुड़ी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है। किसी निजी वाट्सऐप समूह में की गई बातचीत को स्वत: इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक आलोचना नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने एचआरटीसी के 10 अक्टूबर 2023 के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को निरंतर सेवा में मानकर नियमानुसार सभी लाभ देने के आदेश दिए।

निजी वाट्सऐप समूह में भेजे थे दो संदेश: याचिकाकर्ता सुनील कुमार की वर्ष 2021 में एचआरटीसी में अनुबंध आधार पर कंडक्टर के पद पर नियुक्ति हुई थी। सितंबर 2023 में कुछ कंडक्टरों ने 'हिमाचल परिचालक एकता' नाम से एक निजी वाट्सऐप समूह बनाया था। सुनील कुमार भी इस समूह के सदस्य थे। उन्होंने समूह में दो संदेश साझा किए थे। इन संदेशों में निगम की ओर से लागू किए जा रहे नए नियमों तथा उनसे कर्मचारियों को होने वाले संभावित नुकसान और लाभ की समीक्षा करने की बात कही गई थी।



एचआरटीसी प्रबंधन ने इन संदेशों को इंटरनेट मीडिया संबंधी दिशा-निर्देशों और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना। इसके बाद प्रबंधन ने सुनील कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 10 अक्टूबर 2023 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

शिकायत व्यक्त करना संगठन के हित में : मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों को प्रबंधन से शिकायतें होना स्वाभाविक है। कर्मचारियों को अपनी शिकायतें या असंतोष व्यक्त करने का अवसर मिलना संगठन के हित में भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इससे सुधारात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।

न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी कर्मचारी की बातचीत से संगठन की छवि को सीधा नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक प्रबंधन को ऐसे मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि निजी वाट्सऐप समूह में हुई बातचीत को इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक आलोचना के समान नहीं माना जा सकता।

अनुशासनात्मक प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल : हाई कोर्ट ने एचआरटीसी की कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी टिप्पणी की। न्यायालय ने पाया कि कारण बताओ नोटिस जारी करते समय ही निगम ने यह धारणा बना ली थी कि कर्मचारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है। ऐसे में इसके बाद अपनाई गई अनुशासनात्मक प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई।

कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई से पहले निष्पक्ष तरीके से उसके पक्ष को सुना जाना जरूरी है। केवल किसी निजी समूह में नियमों या कर्मचारियों से जुड़े विषय पर विचार व्यक्त करने को आधार बनाकर सेवा समाप्ति जैसी कठोर कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती।

सेवा लाभ देने के निर्देश : हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एचआरटीसी के 10 अक्टूबर 2023 के सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सुनील कुमार को सेवा में निरंतर मानने और नियमों के अनुसार उन्हें मिलने वाले सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों की ओर से निजी मंच पर अपनी शिकायत या विचार व्यक्त करने के मामले में कार्रवाई करते समय उनके अधिकारों और संगठन के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

हिमाचल में हवाई संपर्क विस्तार को केंद्र-राज्य के बीच त्रिपक्षीय समझौता

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क और विमानन अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत किया गया है। इससे प्रदेश में मौजूदा और नई हवाई सेवाओं के विस्तार तथा पात्र विमानन अवसंरचना के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।



पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव संदीप कुमार ने बताया कि समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। समझौते के माध्यम से राज्य में हवाई सेवाओं और संबंधित अवसंरचना के विकास एवं संचालन के लिए सहयोग का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। यह समझौता 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

वर्तमान व्यवस्था के तहत हवाई सेवाओं के संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) में राज्य सरकार 20 प्रतिशत और केंद्र सरकार 80 प्रतिशत योगदान करेगी। हालांकि, हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के संचालन की अधिक लागत को देखते हुए राज्य सरकार ने वीजीएफ में संशोधित अनुपात की मांग की है।

संदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए 90:10 के वीजीएफ योगदान अनुपात को लागू करने का आग्रह किया है। प्रस्तावित व्यवस्था में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार का कहना है कि पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहां हवाई सेवाओं का संचालन मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण और खर्चीला है। उन्होंने कहा कि समझौते से हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क के विस्तार के लिए दीर्घकालिक आधार तैयार होगा।

15 अक्टूबर तक चमोली की सभी सड़कें होंगी गड्ढामुक्त

उदित नैनवाल, चमोली। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीसी हॉल में जनपद में चल रहे गड्ढामुक्त अभियान की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण एजेंसियों को 15 अक्टूबर तक जिले की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग को सभी एजेंसियों के साथ नियमित रूप से अभियान की प्रगति की निगरानी करने और आपसी समन्वय से कार्य कराने को कहा। बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 75 आरसीसी, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचआईडीसीएल, 123 आरसीसी और 66 आरसीसी के अंतर्गत आने वाली सड़कों की स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने उपलब्ध मानव संसाधन, मशीनरी और अन्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख संपर्क मार्गों, बाजारों और अधिक यातायात वाले मार्गों को प्राथमिकता देने को कहा। नगर निकायों को भी अपने क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने सड़क मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

राज्यपाल से मिले नवनियुक्त निदेशक सैनिक कल्याण

पूर्व सैनिकों की सुविधाओं पर राज्यपाल ने किया मंथन

अनिल थपलियाल

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) से मंगलवार को नवनियुक्त निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर बीएस बसेड़ा (सेनि.) ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह बसेड़ा तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के भंडारी गांव, देवलथल निवासी ब्रिगेडियर बसेड़ा ने 34 वर्षों का गौरवपूर्ण सैन्य करियर पूरा किया है। वह इससे पूर्व केंद्रीय सैनिक बोर्ड में सचिव के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। राज्यपाल ने उनके अनुभव का उल्लेख करते हुए पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।



ईसीएचएस समेत चिकित्सा सुविधाएं होंगी सरल

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र पूर्व सैनिकों को समयबद्ध तरीके से मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूर्व सैनिकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल माध्यमों के विस्तार से आवेदन, सत्यापन और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए ईसीएचएस सहित चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाने पर भी जोर दिया।

घर के पास सीएसडी सुविधा देने पर विचार

उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्ग पूर्व सैनिकों के लिए उनके घर के नजदीक या संभव हो तो घर तक सीएसडी सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय करने और कैंटीन में भीड़ के बीच इंतजार करने से राहत मिल सके। भेंट के दौरान राज्यपाल ने निर्माणाधीन सैन्य धाम के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आस्था, सम्मान और गौरव का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके संचालन और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

एमबीबीएस-बीडीएस प्रवेश में प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच हो: धस्माना



अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड में नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश में राज्य कोटे के तहत विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के प्रमाणपत्रों में कथित फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जांच केवल प्रमाणपत्रों के सत्यापन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके संभावित अंतरराज्यीय नेटवर्क और नीट परीक्षा से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल होनी चाहिए।

◆आरक्षण प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप बहुगुणा की ओर से मामला उठाए जाने के बाद यह सामने आया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जांच के आदेश का स्वागत किया। धस्माना ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और पूर्व सैनिक सहित विभिन्न श्रेणियों का आरक्षण लाभ लेने के लिए कथित फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए।

यदि जांच में किसी बड़े नेटवर्क की बात सामने आती है तो मामले को सीबीआई को सौंपने पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश मिलने की पुष्टि होती है तो इससे पात्र विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी भी मौजूद रहीं।

थराली की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दिया धरना



अनिल थपलियाल

थराली। थराली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। पूर्व विधायक डॉ. जीतराम के नेतृत्व में थराली, नारायणबगड़ और देवाल क्षेत्र से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबे समय से प्रतीक्षित कसबीनगर-विनायकधार-गैरसैंण मोटरमार्ग के निर्माण की मांग उठाई गई।

पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं और अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप पटवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को उपचार के लिए दूर जाना पड़ रहा है।

4732 श्रद्धालुओं ने मिलकर केदारनाथ से लौटाया 12 टन कूड़ा

उदित नैनवाल, चमोली। केदारनाथ धाम को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की 'केरी मी बैक पॉलिसी' प्रभावी साबित हो रही है। अभियान के तहत अब तक 4732 श्रद्धालुओं की सहभागिता से 12 टन सूखा कूड़ा केदारनाथ से गौरीकुंड पहुंचाया जा चुका है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को विशेष बैग दिए जाते हैं, जिनमें वे प्लास्टिक बोतल, रैपर और पैकेजिंग सामग्री समेत चार से पांच किलोग्राम सूखा कूड़ा एकत्र कर गौरीकुंड तक लाते हैं। यहां कूड़े का सुरक्षित संग्रहण कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाता है।

यमुनोत्री धाम में स्वच्छता व्यवस्था हुई मजबूत

प्रशासन ने धाम और पैदल मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के दिए निर्देश

शिव सिंह थलवाल

उत्तरकाशी। यमुनोत्री धाम में देश-विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने अधिकृत कार्यदायी संस्था सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सफाई और कचरा निस्तारण का अभियान तेज कर दिया है। जानकीचट्टी बैरियर से मुख्य मंदिर परिसर तक 40 पर्यावरण मित्र और चार सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।

टीम नियमित रूप से पैदल मार्ग की सफाई, ठोस अपशिष्ट एकत्र करने और उसे जानकीचट्टी स्थित डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। धाम की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए धार्मिक अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।



◆यमुनोत्री में 15 अतिरिक्त खच्चरों से हटेगा कूड़ा

सुलभ इंटरनेशनल के अनुसार, पूर्व में संचालित एक माह के अभियान में प्रतिदिन करीब 15 खच्चरों के माध्यम से 30 कट्टों में पूजन सामग्री और अन्य अवशेष जानकीचट्टी पहुंचाए गए। अब 18 सितंबर से 15 अतिरिक्त खच्चरों की टोली भी तैनात की गई है। इनके माध्यम से मंदिर क्षेत्र में जमा पूजन सामग्री को नियमित रूप से नीचे प्रसंस्करण स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने संस्था को यात्रा सत्र समाप्त होने तक सफाई, कचरा संग्रहण और परिवहन की व्यवस्था निरंतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

टिहरी में कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था होगी मजबूत

अनिल थपलियाल



नई टिहरी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने नगर निकायों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले के 11 नगर निकायों में प्रतिदिन करीब 58 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, जिसमें 28.8 मीट्रिक टन गीला और 24.75 मीट्रिक टन सूखा कूड़ा शामिल है। जिले में 10 एमआरएफ सेंटर, 72 कंपोस्ट पिट, आठ कंपोस्टर और 10 कॉम्पैक्टर मशीनें उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने सभी निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप कार्य करने और कूड़े का स्रोत पर ही पृथक्करण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कूड़ा उठान के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध नहीं होने वाले निकायों से आवश्यक पत्रावली प्रस्तुत करने को कहा। कूड़ा फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बल्क वेस्ट जनरेटरों के पंजीकरण, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।

भारतीय वन्यजीव संस्थान की 37वीं वार्षिक शोध संगोष्ठी का शुभारंभ

◆वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और मानव-वन्यजीव संघर्ष पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

विकास बलोनी

देहरादून। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित दो दिवसीय वन्यजीव अनुसंधान सेमिनार 2026 मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सेमिनार में शोधकर्ताओं, वन्यजीव पेशेवरों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, संरक्षण विशेषज्ञों, छात्रों एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया और वन्यजीव विज्ञान तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों एवं प्रगति पर विचार-विमर्श किया।

वर्ष 1986 से आयोजित की जा रही वार्षिक शोध संगोष्ठी वन्यजीव अनुसंधान, वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान और संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच रही है। संगोष्ठी में भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, नवीन तकनीकों और जमीनी स्तर पर लागू किए जा सकने वाले संरक्षण उपायों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

शोध और संरक्षण के बीच सेतु

संगोष्ठी के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण की वर्तमान चुनौतियों, बदलते पर्यावास, मानव-वन्यजीव संघर्ष और जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा की जा रही है। संस्थान के निदेशक डॉ. जी.एस. भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शोध को अधिक प्रभावी, प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत डीन, फैकल्टी ऑफ वाइल्डलाइफ साइंसेज, डॉ. रुचि बडोला और डब्ल्यूआईआई निदेशक डॉ. जी.एस. भारद्वाज के स्वागत संबोधन से हुई। इसके बाद भारत सरकार के इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के महानिदेशक डॉ. एस.पी. यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।



मानव-वन्यजीव संघर्ष और पर्यावास संरक्षण बड़ी चुनौती

डॉ. जी.एस. भारद्वाज ने कहा कि वार्षिक शोध संगोष्ठी संस्थान में चल रहे विविध शोध कार्यों को सामने लाने के साथ-साथ विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि पर्यावास में कमी और बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष देश के सामने प्रमुख संरक्षण चुनौतियां हैं।

उन्होंने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान देश के विभिन्न क्षेत्रों में वन्यजीव अनुसंधान एवं संरक्षण से जुड़े अनेक विषयों पर कार्य कर रहा है। संस्थान का शोध क्षेत्र-केंद्रित और व्यवहारिक है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संरक्षण की चुनौतियों के समाधान में योगदान देना है।

मुख्य अतिथि डॉ. एस.पी. यादव ने कहा कि भारत के लिए 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य में वन्यजीव संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों के बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष, पर्यावास में गिरावट और संरक्षण की अन्य चुनौतियों पर चर्चा की।

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय

डब्ल्यूआईआई के रिसर्च कोऑर्डिनेटर डॉ. बिवाश पांडव ने कहा कि संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध संस्थान के वैज्ञानिक एवं अकादमिक समुदाय की विविधता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने तथा उभरती तकनीकों के प्रभावी उपयोग को वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

◆भारतीय वन्यजीव संस्थान का 37वां वार्षिक अनुसंधान सेमिनार देहरादून में संपन्न

संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध-पत्र, पोस्टर और वैज्ञानिक संवाद वन्यजीव संरक्षण की बदलती चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वर्ष 1982 में हुई थी की स्थापना

भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में देहरादून में हुई थी। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। संस्थान वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अकादमिक पाठ्यक्रम और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत के साथ-साथ दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मोहब्बेवाला में हादसों का सिलसिला कब थमेगा?

विकास बलोनी



देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसे अब महज दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक गंभीर सवाल बन चुके हैं। दिनांक 21 सितंबर 2026 को जिलाधिकारी देहरादून तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से मोहब्बेवाला में राजमार्ग और घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासनिक स्तर पर घटनास्थल का निरीक्षण निश्चित रूप से आवश्यक कदम है, लेकिन निरीक्षण के 24 घंटे बाद भी यदि किसी ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में स्पष्ट कदम दिखाई नहीं देता, तो चिंता स्वाभाविक है।

हर दिन सड़क पर कोई न कोई परिवार उजड़ जाता है और हर हादसा व्यवस्था से एक नया सवाल पूछकर चला जाता है—आखिर कब तक?

स्थानीय लोगों ने आशारोड़ी की ओर से देहरादून आने वाली ढलान और भारी वाहनों की रफ्तार को लेकर चिंता जताई है। ढलान, भारी वाहनों की गति, शहर में प्रवेश करते ही बढ़ता यातायात दबाव और कई स्थानों पर सीमित सड़क चौड़ाई—इन सभी परिस्थितियों का संयोजन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

सवाल यह है कि क्या यहां गति नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम हैं? क्या भारी वाहनों की गति और आवाजाही की नियमित निगरानी होती है? क्या सड़क की इंजीनियरिंग, ढलान, मोड़, बैरिकेडिंग और दुर्घटना-प्रवण स्थानों का तकनीकी परीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है?

सिर्फ हादसे के बाद पुलिस, क्रेन और राहत-बचाव दल की सक्रियता पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब होगी, जब हादसा होने से पहले उसे रोकने की व्यवस्था जमीन पर दिखाई दे।

बड़ी आस से मैं घर से निकलता हूँ, शाम को अपनों के बीच लौटने की उम्मीद रखता हूँ। सड़क सफर की सहूलियत होनी चाहिए, किसी परिवार के बिछड़ने की वजह नहीं होनी चाहिए। सरकार और संबंधित विभागों से आग्रह है कि मोहब्बेवाला को केवल एक दुर्घटना स्थल मानकर कार्रवाई न की जाए, बल्कि यहां व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। जरूरत के अनुसार भारी वाहनों के लिए गति नियंत्रण, स्पीड कैमरा या अन्य निगरानी व्यवस्था, चेतावनी संकेत, पर्याप्त बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सड़क डिजाइन की समीक्षा और यातायात प्रबंधन जैसे उपायों पर समयबद्ध निर्णय लिया जाए।

साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि सड़क की किसी खामी या सुरक्षा व्यवस्था में कमी की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी है और सुधार कब तक होगा।

मोहब्बेवाला को किसी 'अभिशाप' के रूप में देखने के बजाय इसे एक ऐसी सड़क-सुरक्षा चुनौती के रूप में देखना होगा, जिसका समाधान इंतजार से नहीं, ठोस योजना और समयबद्ध कार्रवाई से निकलेगा।

बहुत आँधियारा है, अब सूरज निकलना चाहिए, हादसों का यह दौर अब हर हाल में थमना चाहिए। आज सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर उस परिवार का है जिसका कोई सदस्य रोज इस सड़क से गुजरता है। सरकार से यही आग्रह है—अब निरीक्षण से आगे बढ़कर समाधान दिखाई देना चाहिए। क्योंकि सड़क पर निकलने वाला हर इंसान सुरक्षित घर लौटे, इससे बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती।

पत्रकारों की समस्याओं पर डीएम ने किया मंथन

अनिल थपलियाल

नई टिहरी। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में जिला पत्रकार स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें पत्रकारों से जुड़े विभिन्न विषयों और समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। प्रेस क्लब अध्यक्ष अनुराग उनियाल ने दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में समाचार कवरेज के दौरान आने वाली परिवहन संबंधी दिक्कतों को उठाया।

जिलाधिकारी ने बड़े आयोजनों से एक दिन पहले संबंधित विभागों से समन्वय कर पत्रकारों के लिए विभागीय वाहन की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में सफलता की कहानी तैयार करने वाले पत्रकार पूर्व सूचना जिला सूचना कार्यालय को दे सकते हैं, जिसके आधार पर उपलब्ध संसाधनों से आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

प्रेस क्लब महासचिव विजय गुसाईं ने टिहरी डैम टॉप से रात में आवाजाही बंद होने से फील्ड कवरेज से लौटने वाले पत्रकारों की परेशानी बताई। डीएम ने समाधान के लिए संबंधित स्तर पर समन्वय का भरोसा दिया। बैठक में पत्रकार आवासों के रखरखाव, प्रेस मान्यता नियमों में शिथिलीकरण और घनसाली में मीडिया सेंटर के लिए भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे भी उठे।

मसूरी में 70 वाहनों पर कार्रवाई, नाबालिगों की स्कूटी भी सीज

सुनील सोनकर

मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, मसूरी पुलिस और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने गांधी चौक, स्प्रिंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग और प्रतापगढ़ चौक समेत विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 70 वाहनों के चालान किए गए, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों को सीज कर नगर पालिका के सुपुर्द किया गया।

टीटीओ प्रज्ञा पंत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में अनधिकृत रूप से संचालित टैक्सी-स्कूटी, निर्धारित स्थान के बजाय सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कुछ नाबालिग भी स्कूटी चलाते मिले। उनके चालान करने के साथ संबंधित स्कूटी को भी सीज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई वाहन चालक सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा कर यातायात प्रभावित कर रहे थे। निर्धारित स्थान के बजाय अन्य जगहों से संचालित वाहनों के खिलाफ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई भी शुरू की गई है।



◆मसूरी में परिवहन विभाग, पुलिस, प्रशासन और पालिका की संयुक्त कार्रवाई, सड़क किनारे खड़े वाहनों पर भी शिकंजा

नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अनधिकृत रूप से संचालित स्कूटी और टैक्सियों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने कहा कि स्प्रिंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग और प्रतापगढ़ चौक में सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े करने और स्कूटी संचालन से यातायात प्रभावित हो रहा था। उन्होंने प्रशासन से अभियान नियमित रूप से चलाने की मांग की, ताकि प्रमुख बाजार और संपर्क मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

एनएमएचएस भर्ती में पारदर्शिता की उठी मांग

डी एस सिजवाली, अल्मोड़ा। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के अधीन संचालित राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन की भर्ती और पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है। मिशन से जुड़े रहे पुराने परियोजना कर्मचारियों ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर चयन प्रक्रिया और शोध परियोजनाओं के संचालन में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मिशन में कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उन्होंने भर्ती में निर्धारित पात्रताओं, नियमों और हिमालयी क्षेत्र से जुड़े अनुभव को पर्याप्त महत्व दिए जाने पर भी सवाल उठाए। वक्ताओं ने शोध परियोजनाओं में उपलब्ध धन के इस्तेमाल, कार्यों और परिणामों की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। कुछ कर्मचारियों के न्यायालय और आयोग में शिकायत करने की जानकारी भी दी गई।



पाकिस्तान में बन रहीं विदेशी पिस्टलों की नकल, ड्रोन से पंजाब पहुंच रहे हथियार

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली



मोहाली और चंडीगढ़ में आपराधिक वारदातों में इस्तेमाल किए जा रहे अत्याधुनिक हथियारों को लेकर पुलिस जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच के अनुसार जिगाना, पीएक्स-3, पीएक्स-5, बेरेटा और ग्लॉक जैसी विदेशी पिस्टल की हूबहू नकल पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। इन हथियारों को ड्रोन के जरिये सीमा पार से पंजाब में भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार इनकी कीमत दो से पांच लाख रुपये तक बताई जा रही है।

मोहाली में रंगदारी के लिए तीन कारोबारियों के घरों पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के दौरान हथियारों की सप्लाई से जुड़ी जानकारी मिली है। खरड़ सीआइए प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप बाजवा के अनुसार, मामले में शूटर रविंदर उर्फ काली ने हथियारों की व्यवस्था करवाई थी। जांच में पुलिस को आशंका है कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों के नेटवर्क के जरिये पाकिस्तान से हथियार मंगवाए गए।

सात पिस्टल बरामद : मोहाली फायरिंग मामले में पुलिस अब तक सात हथियार बरामद कर चुकी है। इनमें दो पीएक्स-5, दो जिगाना और तीन .30 बोर पिस्टल शामिल हैं। पुलिस इन हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि सीमा पार से हथियारों की खेप पंजाब तक किस तरह पहुंचाई गई।

पुलिस को आशंका है कि विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गे कुलवीर सिद्धू के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार मंगवाए गए। हालांकि, इस नेटवर्क की भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

चंडीगढ़ की वारदातों में भी इस्तेमाल : पुलिस जांच में सामने आया है कि जिगाना और पीएक्स-5 जैसी पिस्टलों का इस्तेमाल चंडीगढ़ और आसपास की कई आपराधिक वारदातों में हुआ है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की एजीटीएफ ने गैंगस्टर दीपक नांदल गिरोह के कुछ शूटरों को गिरफ्तार किया था।

गुरु रविदास प्रकाश पर्व पर पंजाब से निकलेंगी चार भव्य यात्राएं

वाराणसी और जम्मू समेत चार स्थानों से यात्राएं निकलकर खुरालगढ़ साहिब में होंगी संपन्न, उमड़ेगी संगत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर पंजाब सरकार ने चार प्रमुख शोभायात्राओं का कार्यक्रम घोषित किया है। ये यात्राएं वाराणसी, जम्मू, बठिंडा और फरीदकोट से रवाना होकर खुरालगढ़ साहिब में संपन्न होंगी। सरकार के अनुसार, यात्राओं के माध्यम से गुरु रविदास जी की बाणी, जीवन और समानता, सामाजिक सद्भाव तथा मानवता के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वाराणसी और जम्मू से यात्राएं 30 नवंबर को शुरू होंगी, जबकि बठिंडा से एक दिसंबर और फरीदकोट से दो दिसंबर को शोभायात्रा निकलेगी। चारों यात्राएं तीन दिसंबर को खुरालगढ़ साहिब पहुंचेंगी। वाराणसी से निकलने वाली यात्रा का मार्ग कानपुर, दिल्ली, अंबाला, मोहाली और रूपनगर होते हुए खुरालगढ़ साहिब तक रहेगा। जम्मू वाली यात्रा पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और होशियारपुर से होकर पहुंचेगी।

बठिंडा से निकलने वाली यात्रा बरनाला, मानसा, लहरागागा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोरिंडा और रूपनगर से होकर खुरालगढ़ पहुंचेगी। वहीं फरीदकोट से शुरू होने वाली यात्रा फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, नवांशहर और गढ़शंकर होते हुए खुरालगढ़ साहिब पहुंचेगी। इन यात्राओं के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संगत को गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं से जोड़ने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सरकार ने 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में वर्षभर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इनमें कीर्तन दरबार, संगोष्ठियां, स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताएं, वृत्तचित्र प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी की बाणी और जीवन से युवाओं को जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।

इसी कड़ी में राज्यभर में 92 विशेष ड्रोन शो आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक शो में 500 से अधिक ड्रोन के माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन, बाणी और शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक प्रस्तुति करीब 25 से 30 मिनट की होगी। अधिकारियों को कार्यक्रम स्थलों की पहचान करने और लोगों को पहले से समय व स्थान की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार के अनुसार, पंजाब के करीब 3500 गांवों में गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित वृत्तचित्र भी दिखाया जा चुका है। इसके लिए 50 वाहनों के माध्यम से गांव-गांव प्रचार किया जा रहा है।

खुरालगढ़ साहिब में इन आयोजनों का विशेष समापन कार्यक्रम प्रस्तावित है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार यहां धार्मिक सभाओं, कथा-कीर्तन दरबार, संत समागम और गुरु रविदास जी की बाणी पर चर्चा जैसे आयोजन किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु रविदास जी के समानता, सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है।

न्यूज ब्रीफ

फ्री आईफोन के लिए हुआ अनोखा ड्रॉ, 15 महिलाओं के निकले नाम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कारोबारी राकेश त्रेहन की ओर से महिलाओं को आईफोन बांटने की घोषणा मंगलवार को चर्चा का विषय रही। सेक्टर-10 स्थित उनकी कोठी पर मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के नाम से ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ में 15 नामों का चयन किया गया, लेकिन मौके पर कोई भी महिला आईफोन लेने नहीं पहुंची। कारोबारी ने कहा कि चयनित 10 महिलाओं के घर तक आईफोन पहुंचाए जाएंगे। त्रेहन ने बताया कि वह महिलाओं को आईफोन-17 या उससे ऊपर के मॉडल देने की योजना बना रहे थे। इसके लिए चंडीगढ़ और मोहाली की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का एक व्हाट्सएप समूह बनाया गया था। समूह में शामिल महिलाओं को प्रतिदिन 'जय माता दी' लिखना होता था। ऐसा नहीं करने वाली महिला को समूह से हटाने की बात कही गई थी।

जालंधर में अवैध फ्लेक्स से निगम के करोड़ों के राजस्व पर गहराया संकट

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। शहर में लगे अवैध धार्मिक और राजनीतिक फ्लेक्स अब नगर निगम जालंधर के लिए वित्तीय परेशानी का कारण बन सकते हैं। आउटडोर विज्ञापन का ठेका करीब 13.71 करोड़ रुपये में लेने वाली क्रिएटिव ओओएच कंपनी ने मेयर और कमिश्नर को अंतिम रिमाइंडर भेजा है। कंपनी का दावा है कि उसके निर्धारित यूनिपोल और होर्डिंग स्थलों पर 100 से अधिक अवैध फ्लेक्स लगाए गए हैं। कई स्थानों पर भुगतान करने वाले ग्राहकों के विज्ञापन ढक दिए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि उसने 22 सितंबर तक की लाइसेंस फीस जमा कर दी है, लेकिन यदि अवैध फ्लेक्स नहीं हटाए गए तो 23 सितंबर से शुरू होने वाली अगली अवधि की फीस रोकने पर विचार किया जाएगा। कंपनी के अनुसार वह हर महीने कर समेत करीब 1.40 करोड़ रुपये निगम को देती है।

लुधियाना में बिजली बिल के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर में साइबर ठग अब बिजली विभाग के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट और साइबर सेल ने नागरिकों को सतर्क करते हुए एडवाइजरी जारी की है। ठग खुद को पावरकॉम या बिजली विभाग का अधिकारी बताकर उपभोक्ताओं को फोन करते हैं और बिल में गड़बड़ी, छूट या कनेक्शन काटने का डर दिखाते हैं। ठग बिल कम या ठीक कराने के नाम पर मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी मांगते हैं। ओटीपी मिलते ही वे बैंक खाते या यूपीआइ से रकम निकाल सकते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिजली विभाग का कोई अधिकारी फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी नहीं मांगता। पुलिस ने लोगों से अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल पर भरोसा नहीं करने और बिजली बिल से जुड़ी समस्या के लिए केवल अधिकृत माध्यमों का इस्तेमाल करने की अपील की है। ठगी होने या संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी गई है।

फिरोजपुर में चरणजीत सिंह के स्टॉल से पांच लाख की लॉटरी चोरी

भारतेन्दु संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर कैंट के पायलट चौक स्थित कुक्कू लॉटरी स्टॉल से बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। बैग में करीब पांच लाख रुपये की लॉटरी होने की बात सामने आई है। घटना सुबह करीब आठ बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। स्टॉल संचालक चरणजीत सिंह ने बताया कि वह करीब 50 वर्षों से लॉटरी स्टॉल चला रहे हैं। रोजाना की तरह वह सुबह स्टॉल पर पहुंचे और बैग काउंटर के नीचे रख दिया। इसके बाद वह स्टॉल के पीछे लाइट लगाने चले गए। करीब पांच मिनट बाद लौटे तो काउंटर के नीचे रखा बैग गायब था। चरणजीत सिंह के अनुसार, बैग में करीब पांच लाख रुपये की लॉटरी थी और स्टॉल पर एक हजार रुपये तक की लॉटरी उपलब्ध थी। बैग गायब होने का पता चलते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास की जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

पंजाब फंड कटौती के आरोपों पर सीतारमण का पलटवार, बोलीं- राज्यों से नहीं होता भेदभाव

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी की 15 सीटों के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 20 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों ने डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 के प्रोफेसर डॉ. अमरेंद्र मान के समर्थन में डिजिटल संदेश जारी कर मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील की है।

शूटर मनु भाकर, अर्जुन अवॉर्डी अंजुम मोदगिल, जिम्नास्ट पलक गुलिया और समीरा खान तथा फुटबॉलर देवांश देवास ने डॉ. मान के समर्थन में अपने संदेश साझा किए हैं। ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी से कुल 51 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चंडीगढ़ से डॉ. अमरेंद्र मान के अलावा सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. जगवंत सिंह, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बीपी यादव, शिक्षक प्रवीण कौर मान सहित कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

डॉ. अमरेंद्र मान डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 में करीब 20 वर्षों से प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वह डीएवी प्रबंधन की ओर से चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि सीनेट में चुने जाने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

विद्यार्थियों और शिक्षकों के मुद्दों पर जोर : डॉ. मान के अनुसार, विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, आधुनिक खेल सुविधाएं और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की जरूरत है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर और संबद्ध कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच पर उठाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। शिक्षकों के लिए अकादमिक विकास के अवसर और बेहतर कार्य परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं।

मोहाली गमाडा कार्यालय पर ईडी छापा मजीठिया ने भ्रष्टाचार जांच की मांग की

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब के मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) के कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से प्रदेश की सियासत गरमा गई है। गमाडा कार्यालय के अलावा पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर भी ईडी की कार्रवाई किए जाने की सूचना है। हालांकि, छापेमारी के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

ईडी की कार्रवाई के बाद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। मजीठिया ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर गमाडा से जुड़े मामलों की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि गमाडा में भ्रष्टाचार और अधिकारियों तथा आप नेताओं के कथित गठजोड़ की गहन जांच होनी चाहिए।

मजीठिया ने कहा कि गमाडा कार्यालय में ईडी की कार्रवाई ने पंजाब सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के सरकारी खजाने, कीमती जमीनों और सरकारी संसाधनों से जुड़े मामलों में एक बड़ा गठजोड़ काम कर रहा है। मजीठिया ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

अकाली नेता ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों को सरकार के लिए कमाई करने वाला बताया जा रहा है, जबकि कुछ आप नेताओं के नाम भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी अधिकारियों और नेताओं की भूमिका की निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। मजीठिया ने यह भी कहा कि जांच किसी राजनीतिक दबाव के बिना होनी चाहिए, ताकि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो सके।

मजीठिया के आरोपों के बाद पंजाब में गमाडा की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े मामलों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं।

राज्य सरकार ने आदेश के खिलाफ अपील दायर कर अतिरिक्त समय की मांग की

डीए-डीआर भुगतान में देरी पर हाई कोर्ट सख्त मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से किया तलब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पूर्व आदेशों का पालन नहीं होने और अनुपालन शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि, यदि राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई संरक्षण मिल जाता है तो मुख्य सचिव की व्यक्तिगत पेशी से छूट रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ डीए-डीआर के लंबित भुगतान से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि तीन अगस्त को दिए गए आदेश के बावजूद मुख्य सचिव की ओर से अनुपालन शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को अपने आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन कानूनी उपाय का इस्तेमाल आदेश के अनुपालन को अनिश्चितकाल तक टालने के लिए नहीं किया जा सकता।

तीन अगस्त को दिए थे भुगतान के निर्देश : हाई कोर्ट ने तीन अगस्त को पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड को कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित डीए-डीआर की अद्यतन किस्तें जारी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि भुगतान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिए जा रहे केंद्रीय दर के अनुरूप किया जाए। इसके लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया गया था।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि तय अवधि में भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। साथ ही मुख्य सचिव को आदेश के अनुपालन से संबंधित शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था।

राज्य ने दायर की अपील : सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने एक सितंबर को आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन रजिस्ट्री की ओर से बताई गई आपत्तियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। राज्य सरकार की ओर से अदालत से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया और कहा गया कि मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

खंडपीठ ने कहा कि मामला बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से जुड़ा है। ऐसे में राज्य सरकार से अपेक्षा थी कि वह उपलब्ध कानूनी उपायों का तेजी से इस्तेमाल करती। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि एकल पीठ पहले ही बकाया भुगतान के लिए तीन महीने का समय दे चुकी थी और वह अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

अमृतसर एएसआइ हत्या के बाद वर्दी एडवाइजरी से गरमाई पंजाब की सियासत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। अमृतसर में एएसआइ की हत्या के बाद पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी न पहनने की कथित एडवाइजरी का ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि पंजाब पुलिस और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ऐसी किसी आधिकारिक एडवाइजरी जारी होने से साफ इनकार किया है।

वायरल ऑडियो में एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है, जो खुद को पुलिस कर्मचारी बता रही है। ऑडियो में अमृतसर देहात, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट में तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर कथित तौर पर कई निर्देश दिए जाने का दावा किया गया है। इसमें कर्मचारियों से वर्दी, बेल्ट, पहचान चिन्ह और पुलिस उपकरण प्रदर्शित नहीं करने तथा अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की बात कही गई है।

मामला सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी मामले को लेकर सवाल उठाए।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस की ओर से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। उन्होंने वायरल संदेशों को गलत बताते हुए कहा कि विपक्षी दल पुलिस और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



◆ हत्या के बाद वायरल ऑडियो को पुलिस ने फर्जी बताया, विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

पंजाब को बदनाम करने की साजिश, संजय सिंह का विपक्ष पर हमला

संजय सिंह ने जग्गा, मोहनजीत और गुलजार के मामलों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को आप मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की नशा विरोधी मुहिम को कमजोर करने और पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, ये सभी आरोप संजय सिंह और आप की ओर से लगाए गए हैं।

संजय सिंह ने तीन लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दल इन मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने जग्गा सिंह के संबंध में दावा किया कि उसके खिलाफ नौ मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल हैं। संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि इनमें से चार मामलों में जग्गा सिंह को दोषी ठहराया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और नशा तस्करी से जुड़े मामले भी दर्ज हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है।

मोहनजीत सिंह और गुलजार का भी किया जिक्र : संजय सिंह ने मोहनजीत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आठ प्राथमिकी दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को काला झंडा दिखाने की घटना को विपक्षी दलों ने अलग तरीके से पेश किया और इसे नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई के रूप में प्रचारित किया।

उन्होंने गुलजार सिंह के मामले पर भी विपक्ष पर सवाल उठाए। संजय सिंह का दावा है कि गुलजार ने अपने पहले वीडियो में न तो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और न ही आम आदमी पार्टी का नाम लिया था, जबकि बाद के वीडियो में उनका नाम आया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने गुलजार



पर दबाव बनाकर बयान दिलवाया। दूसरी ओर, गुलजार सिंह की मौत को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हरपाल सिंह चीमा की भूमिका को लेकर आरोप लगाए गए हैं, जबकि अदालत ने प्राथमिकी में चीमा को शामिल करने के आधार पर सवाल भी उठाए हैं।

पुराने शासन पर भी साधा निशाना: संजय सिंह ने अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के पूर्व शासन पर पंजाब में नशे की समस्या बढ़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और विपक्ष इस अभियान को रोकने के लिए एकजुट हो गया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी।

संजय सिंह ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर वर्ष 2021 में पकड़ी गई हेरोइन की खेप का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि करीब 20 हजार करोड़ रुपये की नशीली सामग्री पकड़े जाने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कार्रवाई की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर डीआरआई ने 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी और बाद में मामले की जांच एनआईए ने संभाली थी।

नशे के मुद्दे पर तेज हुई सियासी बयानबाजी : संजय सिंह ने गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों और अन्य राज्यों में नशे से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए भाजपा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पंजाब को बदनाम करने के बजाय नशे के मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर चर्चा करनी चाहिए।

पंजाब में नशे को लेकर सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। भाजपा ने हाल ही में नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की है, जबकि विपक्षी दल सरकार से नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जवाब मांग रहे हैं।

जिला अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को दिए कड़े निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सरकार को निर्देशों के अनुपालन की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।

खंडपीठ ने कहा कि नागरिकों को उचित चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए जिला अस्पतालों में जरूरी संसाधनों और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अस्पतालों में भवन और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। इन सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी जरूरी है।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मलेरकोटला सिविल अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। भिशम किंगर की ओर से दायर याचिका में अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक जांच सुविधाओं की उपलब्धता का मुद्दा भी उठा।

हाई कोर्ट ने कहा कि जिला और उपमंडल स्तर के अस्पतालों में मरीजों को जरूरी जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अस्पतालों में वास्तव में कार्यशील होनी चाहिए। यदि किसी अस्पताल में मशीनें उपलब्ध हैं, तो उन्हें संचालित करने के लिए तकनीकी और चिकित्सा कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में सहकारी समितियों पर नियम, निगरानी और जुर्माना होगा सख्त

नई व्यवस्था में पंजीकरण से लेकर लेखा परीक्षण तक कई स्तरों पर तय की गई जवाबदेही

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर में सहकारी समितियों के नियामकीय ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विधानसभा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। विधेयक के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिनियम, 1999 को निरस्त करने और उसके तहत पंजीकृत समितियों को जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां अधिनियम, 1989 के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षण और वित्तीय निगरानी से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना है।

विधेयक को सहकारिता मंत्री जावेद अहमद डार ने विधानसभा के शरदकालीन सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया। प्रस्तावित संशोधनों के तहत 1999 के अधिनियम को समाप्त करने के साथ उसके तहत पंजीकृत समितियों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था भी की गई है। कानून लागू होने से ठीक पहले 1999 के अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वावलंबी सहकारी समितियों को 1989 के अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा। हालांकि, आगे इन समितियों को संशोधित कानून और उसके तहत बनाए जाने वाले नियमों का पालन करना होगा।

पुराने आदेश और नियम फिलहाल रहेंगे प्रभावी : विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि 1999 के कानून के तहत पहले किए गए कार्य, जारी आदेश तथा बनाए गए नियम और उप-नियम तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक वे नए संशोधित कानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं। इससे मौजूदा समितियों के कामकाज में अचानक कानूनी शून्य पैदा होने की स्थिति से बचने की व्यवस्था की गई है।

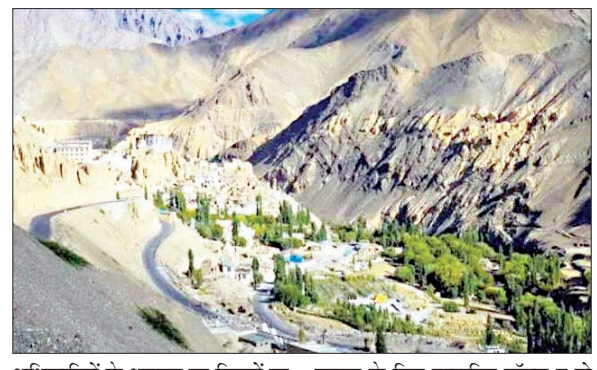
पंजीकरण प्रक्रिया होगी अधिक दस्तावेज आधारित : नई सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में भी बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। पंजीकरण आवेदन के साथ प्रस्तावित उप-नियम की प्रति देना जरूरी होगा। प्राथमिक कृषि और गैर-कृषि सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों का प्रावधान रखा गया है। सहकारी बैंकों के मामले में स्थायी पंजीकरण से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित सहमति आवश्यक होगी। इससे बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं के नियमन को संबंधित केंद्रीय नियमों के अनुरूप रखने की कोशिश की गई है।

आवासीय समितियों के लिए जमीन का प्रमाण जरूरी : सहकारी आवासीय समितियों के पंजीकरण में भूमि संबंधी दस्तावेजों को भी अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित गतिविधियों के लिए समिति के पास भूमि उपलब्ध हो और उस पर उसका वैध कब्जा हो। इसके लिए स्वामित्व विलेख, आवंटन पत्र या सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।

पेशेवर या तकनीकी संस्थानों से जुड़ी सहकारी समितियों के लिए संबंधित नियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकरण की पूर्व लिखित मंजूरी अथवा लाइसेंस जरूरी होगा। दवाइयों, उर्वरकों, मुर्गीपालन और अन्य विनियमित क्षेत्रों में काम करने वाली समितियों को संबंधित विभाग या एजेंसी से वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र या लाइसेंस लेना होगा।

लेखा परीक्षण और वित्तीय निगरानी पर जोर : विधेयक में सहकारी समितियों की वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित समय के भीतर खातों का लेखा परीक्षण नहीं कराने को कार्रवाई का आधार बनाया जा सकेगा। कुछ प्रावधानों में निर्धारित समयसीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है। सहकारी बैंकों के लेखा परीक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है।

लद्दाख को अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा पर अक्टूबर में होगी व्यापक चर्चा



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। लद्दाख को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने की दिशा में केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के अनुसार, क्षेत्र की जमीन, रोजगार, संस्कृति, विरासत, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान तैयार करने पर काम चल रहा है। केंद्र ने लद्दाख के लिए नए अनुच्छेद 371(के) का प्रस्ताव रखा है।

कुंद्रा ने बताया कि लद्दाख के लिए तैयार किया जा रहा मॉडल देश के अन्य हिस्सों में लागू व्यवस्थाओं से अलग और क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप होगा। प्रस्ताव के तहत केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एक निर्वाचित निकाय गठित करने की बात सामने आई है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सीधे निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से कराने पर लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी है।

इस प्रस्तावित व्यवस्था में भूमि, संस्कृति, भाषा, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और रोजगार जैसे विषयों से संबंधित अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा देने पर चर्चा हो रही है। हालांकि प्रस्तावित निकाय की विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और नियोजन शक्तियों से जुड़े कई बिंदुओं पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। अधिकारियों के अनुसार इन विषयों पर आगे की बातचीत में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

लद्दाख प्रशासन के अनुसार केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच अगली दौर की बातचीत अक्टूबर में होने की उम्मीद है। इसके लिए लद्दाख के प्रतिनिधियों से प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश स्तर के निकाय और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के बंटवारे से संबंधित मसौदा तैयार करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक सुरक्षा लागू करने के लिए विस्तृत कानूनी और संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी और इसे संसद की मंजूरी लेनी होगी। रिपोर्टों के अनुसार केंद्र की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि लद्दाख के लिए प्रस्तावित मॉडल न तो राज्य का दर्जा होगा और न ही विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था।

लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा की मांग के केंद्र में जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे रहे हैं। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद स्थानीय समूहों ने क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संवैधानिक संरक्षण की मांग उठाई। केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में भूमि अधिकार, स्थानीय रोजगार, संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई है।

राजौरी में आपदा के जख्म भरने को 185 करोड़ की पुनर्बहाली योजना हुई तैयार

राहत राशि के साथ बिजली, सड़क और पुलों की स्थायी बहाली पर जोर



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। राजौरी में हालिया फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से हुए नुकसान के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने राहत और पुनर्बहाली के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी विधानसभा में दी। सरकार के अनुसार, प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने के साथ क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, बिजली और जलापूर्ति ढांचे की स्थायी बहाली की योजना पर भी काम चल रहा है।

राजौरी विधायक इफ्तिकार अहमद के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि राजौरी विधानसभा क्षेत्र में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से प्रभावित 149 परिवारों के राहत मामले प्राप्त हुए थे। निर्धारित एसडीआरएफ मानकों के तहत इन परिवारों को कुल 40.61 लाख रुपये की सहायता वितरित की गई है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2.81 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई।

403 सड़क-पुलों की स्थायी बहाली की तैयारी : आपदा से राजौरी के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक आकलन के आधार पर 403 सड़कों और पुलों की स्थायी बहाली के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन कार्यों पर करीब 185 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़क, पुल और जलापूर्ति योजनाओं को एक महीने के भीतर अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया था। अब स्थायी पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

बिजली ढांचे को 27.99 करोड़ का नुकसान : पावर डेवलपमेंट विभाग के आकलन के मुताबिक पूरे राजौरी जिले में बिजली ढांचे को 2,799.16 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें राजौरी विधानसभा क्षेत्र में 939.24 लाख रुपये का नुकसान दर्ज किया गया। क्षतिग्रस्त बिजली ढांचे की स्थायी बहाली के लिए भी कार्यवाही जारी है।

सरकार ने बताया कि 132 केवी राजौरी-द्राबा ट्रांसमिशन लाइन की स्थायी बहाली के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मेंढर में मिलीं तीन जंग लगी बारूदी सुरंगें, बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में मंगलवार को तीन जंग लगी बारूदी सुरंगें मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सेना के जवानों ने सीमावर्ती गांव धरणा बसोनी के पास फागवारी गली इलाके में काम के दौरान इन सुरंगों को बरामद किया। इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। अधिकारियों के अनुसार, बम निरोधक टीम ने बरामद तीनों बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती गई और किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। सुरंगों को निष्क्रिय किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की दोबारा जांच भी की। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए पहले से लगाए गए कुछ बारूदी सुरंग और अन्य विस्फोटक उपकरण लंबे समय तक जमीन में दबे रहते हैं। बारिश और मौसम की वजह से कई बार ऐसे उपकरण अपनी मूल जगह से खिसक जाते हैं और बाद में दिखाई देने लगते हैं। इससे स्थानीय लोगों तथा सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

जम्मू बस स्टैंड की जर्जर इमारत पर मंडरा रहा खतरा

नवंबर 2022 से असुरक्षित घोषित भवन में अब भी दुकानें और परिवहन कार्यालय हैं संचालित



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू का 56 वर्ष पुराना जनरल बस स्टैंड भवन जर्जर हालत के कारण गंभीर खतरे की जद में है। जम्मू विकास प्राधिकरण ने नवंबर 2022 में इसे असुरक्षित घोषित किया था। इसके बावजूद भवन में दुकानें, कार्यालय और अन्य गतिविधियां जारी हैं और रोजाना सैकड़ों दुकानदारों के साथ हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है। भवन की हालत ऐसी है कि छत और दीवारों का प्लास्टर कई जगह से झड़ चुका है। पिलरों का कंक्रीट टूटने से सरिया बाहर निकल आया है और जल निकासी व्यवस्था भी बदहाल है।

बरसात के दौरान छतों और दीवारों से पानी रिसने के कारण दुकानदारों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश थमने के बाद भी भवन की जर्जर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इमारत के कुछ हिस्सों में टूट-फूट साफ दिखाई देती है। संभावित खतरे को देखते हुए यहां संचालित पुलिस चौकी और सुरक्षा जवानों को हटाया जा चुका है। जेडीए ने भवन के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाया है, लेकिन यात्रियों की आवाजाही वाले हिस्से में सुरक्षा के लिए ठोस घेराबंदी नहीं की गई है।

120 दुकानें और कई कार्यालय संचालित : वर्ष 1970 में निर्मित इस भवन में करीब 120 दुकानें, 21 कमरे और पांच हाल हैं। यहां जम्मू-कश्मीर बैंक का एटीएम भी है। बनिहाल, पुंछ और छंब ग्रुप के परिवहन कार्यालयों के अलावा डिस्पेंसरी और आरटीसी कार्यालय भी संचालित हो रहे हैं। भवन और इसके आसपास करीब 150 से 200 दुकानदार और रेहड़ी-फड़ी वाले रोजाना काम करते हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों के लिए बस पकड़ने वाले हजारों यात्री यहां पहुंचते हैं।

यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता: बस का इंतजार करने वाले यात्रियों का कहना है कि जर्जर भवन के नीचे खड़े रहते समय हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। ऊपर से प्लास्टर या कंक्रीट का हिस्सा गिरने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। यात्रियों के अनुसार जेडीए ने खतरे का बोर्ड तो लगाया है, लेकिन लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं।

दुकानदार बोले, मरम्मत से सुधर सकती है इमारत : ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रमेश कुमार टाक ने भवन को असुरक्षित घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि दुकानदारों ने नए बस स्टैंड के निर्माण में सरकार का सहयोग किया है। उनके अनुसार भवन को खाली कराने के बजाय इसकी उचित मरम्मत, सफाई और नई पाइपलाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका दावा है कि इमारत में आवश्यक मरम्मत के बाद कामकाज जारी रखा जा सकता है।

एसोसिएशन के महासचिव राजन गुप्ता और दुकानदार पंकज गुप्ता ने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों से लोक निर्माण विभाग और जेडीए ने भवन के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

अखनूर में सड़क पर भैंसों के झुंड से यातायात व्यवस्था हो रही प्रभावित



भारतेंदु संवाददाता, अखनूर। अखनूर कस्बे में सड़कों पर खुले में घूम रही भैंसें लोगों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। रोजाना सुबह स्कूल खुलने और दोपहर छुट्टी के समय भैंसों के झुंड मुख्य सड़क पर पहुंच जाते हैं। इससे पन्नू चौक से अखनूर तक यातायात प्रभावित होने के साथ कई बार जाम जैसे हालात बन जाते हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह स्कूल जाने के समय बड़ी संख्या में भैंसों को सड़क की ओर छोड़ दिया जाता है। ये पशु बिना किसी देखरेख के बाजार और मुख्य मार्ग पर घूमते रहते हैं। इनके साथ अक्सर कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं होता। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय जब सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ता है, तब भैंसों के झुंड वापस लौटते दिखाई देते हैं। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है।

लोगों का कहना है कि कई बार भैंसों के वाहनों के बीच आने से गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इस समस्या को लेकर पहले भी संबंधित विभागों के समक्ष शिकायतें की जा चुकी हैं और समाचार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि स्कूलों के समय मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही पशु मालिकों की पहचान कर उन्हें जिम्मेदार बनाया जाए, ताकि यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके।

शुरुआती जांच, विशेषज्ञ उपचार और आर्थिक सहायता पर सरकार का जोर

जम्मू-कश्मीर में कैंसर जांच और उपचार व्यवस्था को मिलेगा विस्तार



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कैंसर मरीजों की संख्या को लेकर विधानसभा में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सरकारी रिकार्ड के आधार पर करीब 51 हजार कैंसर मरीज होने की जानकारी दी। वहीं, विधायक मीर सैफुल्लाह ने 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए करीब 71 हजार मरीज होने का दावा किया था।

मंत्री ने बताया कि सरकार कैंसर की जल्द पहचान और समय पर उपचार के लिए घर-घर स्क्रीनिंग अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान कर मरीजों को उपचार उपलब्ध कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान सौरा और सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में राज्य कैंसर संस्थानों को मजबूत किया जा रहा है। यहां कैंसर की जांच, उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण, आधारभूत ढांचा और मानव संसाधन विकसित किए जा रहे हैं।

विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, फेफड़ों और स्तन कैंसर के मामले प्रमुख हैं। रोकथाम, जांच और उपचार के लिए शीर्ष समिति भी गठित की गई है।

पात्र मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के अनुसार कैशलेस या मुफ्त उपचार मिलेगा।

रीडिंग बिना बिजली बिल पर विधायक मेहराज मलिक ने विधानसभा में उठाए सवाल

भारतेंदु संवाददाता, डोडा । डोडा के विधायक मेहराज मलिक ने मंगलवार को विधानसभा में अपने क्षेत्र की बिजली बिलिंग और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में बिजली मीटरों की रीडिंग किए बिना ही उपभोक्ताओं के बिल बनाए जा रहे हैं। साथ ही, कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या के बावजूद लोगों पर बिलों का बोझ डाला जा रहा है। मलिक ने कहा कि कुछ इलाकों में आज तक बिजली मीटर की रीडिंग नहीं हुई, जबकि वहां बिजली आपूर्ति भी नहीं पहुंची है। इसके बावजूद बिजली के बिल जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने दावा किया कि कुछ लोगों ने बिजली से जुड़े शुल्क के रूप में करीब 60 हजार रुपये तक का भुगतान किया है।

एम्स जम्मू की डॉ. मुस्कान ने रोहतक में जीता दूसरा पुरस्कार



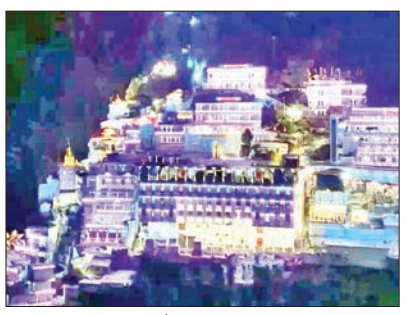
भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर के सेब किसानों ने अब पारंपरिक मंडी व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल माध्यमों से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनानी शुरू कर दी है। शोपियां और बडगाम के कई युवा किसान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए देशभर में अपने बागों का सेब बेच रहे हैं। इससे उन्हें बिचौलियों और कमीशन की लंबी श्रृंखला से राहत मिल रही है।

शोपियां में बड़ी संख्या में परिवार सेब की खेती पर निर्भर हैं, जबकि सोपोर की मंडी देश की प्रमुख फल मंडियों में शामिल है। पारंपरिक व्यवस्था में किसान की फसल कई हाथों से गुजरती है और हर स्तर पर कमीशन कटता है। सीधे बिक्री शुरू होने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है, वहीं ग्राहकों को भी बाजार कीमत की तुलना में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक सस्ता और ताजा सेब उपलब्ध हो रहा है।

शोपियां के युवा किसान इरशाद डार ने कोरोना काल में 'कश्मीरी एपल' नाम से सोशल मीडिया पेज शुरू किया था। शुरुआत में सीमित ऑर्डर मिले, लेकिन धीरे-धीरे मांग बढ़ती गई। अब वह सीजन में हजारों पेटियां सीधे देश के विभिन्न शहरों में भेजते हैं। बडगाम के किसान भी इसी मॉडल को अपनाकर सेब के साथ बादाम और अखरोट बेच रहे हैं।

कृषि विशेषज्ञ इस बदलाव को 'फार्म-टू-फोन' मॉडल बता रहे हैं। स्मार्टफोन के जरिए किसान अब उत्पादक के साथ-साथ मार्केटिंग और बिक्री की भूमिका भी निभा रहे हैं। इससे कश्मीर के सेब को स्थानीय मंडियों से आगे राष्ट्रीय बाजार में सीधे पहचान बनाने का अवसर मिल रहा है।

मां वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ता श्रद्धा का सैलाब, यात्रा सुचारु रूप से जारी



भारतेंदु संवाददाता, उधमपुर। मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह सुचारु रूप से जारी है। यात्रा के सभी मार्ग खुले हैं और श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, घोड़ा-पिट्ठू और पालकी जैसी सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मां वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहे हैं।

मंगलवार को दिनभर मौसम साफ रहा। हालांकि दोपहर के समय तेज धूप और उमस के कारण भवन मार्ग पर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को कुछ परेशानी हुई। श्रद्धालु रास्ते में बनाए गए विश्राम स्थलों पर कुछ देर रुककर आराम करते रहे। इसके बाद जयकारे लगाते हुए फिर भवन की ओर रवाना हुए। सुबह और रात के समय मौसम में हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जिससे इन समय यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मौसम में बदलाव का एहसास हो रहा है।

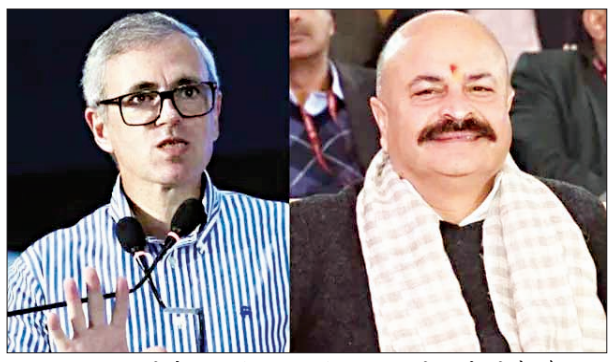
सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर : श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग के विभिन्न हिस्सों में आपदा प्रबंधन दल, प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। संबंधित टीमें लगातार मार्ग की निगरानी कर रही हैं। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को सक्रिय रखा गया है।

भवन के साथ भैरव घाटी में भी पहुंच रहे श्रद्धालु : भवन पहुंचकर श्रद्धालु मां के दिव्य दर्शन कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दर्शन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में भी शीश नवाते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा बाजार में प्रसाद और अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इससे बाजारों में भी श्रद्धालुओं की हल्की रौनक बनी हुई है।

दोपहर तक 13 हजार श्रद्धालुओं का पंजीकरण : मंगलवार को श्रद्धालु पंजीकरण करवाने के बाद परिवार और मित्रों के साथ जयकारे लगाते हुए भवन की ओर रवाना होते रहे। सोमवार को करीब 22 हजार श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। मंगलवार दोपहर दो बजे तक करीब 13 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी रहा।

विधानसभा मुख्यमंत्री ने जनहित के मुद्दे उठाने पर भाजपा विधायक की सदन में मौजूदगी की सराहना की

शेख अब्दुल्ला अवकाश पर भाजपा का वॉकआउट, सदन में डटे रहे युधवीर सेठी



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेख अब्दुल्ला की जयंती पर सरकारी अवकाश बहाल करने की मांग को लेकर सदन में राजनीतिक मतभेद सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों की ओर से शेख अब्दुल्ला की जयंती पर अवकाश की मांग उठाए जाने के विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। हालांकि, भाजपा विधायक युधवीर सेठी सदन में ही मौजूद रहे और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कार्यवाही में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सेठी के इस रुख का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की।

विधानसभा में शेख अब्दुल्ला की जयंती पर सरकारी अवकाश बहाल करने की मांग पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद भाजपा के सदस्य सदन से बाहर चले गए। बाहर निकलते समय उन्होंने महाराजा हरि सिंह के समर्थन में नारे लगाए। वहीं, युधवीर सेठी सदन में बैठे रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल उठाया और संबंधित मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।

उमर ने सदन में सेठी की सराहना की : युधवीर सेठी के सवाल का जवाब देने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके सदन में मौजूद रहने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेठी ने पार्टी के अन्य विधायकों के सदन से बाहर जाने के बावजूद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि विधायक ने सदन का इस्तेमाल जनता से संबंधित विषयों को उठाने के लिए किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विधायक की सराहना करते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के बीच सदन में रहकर लोगों के मुद्दे उठाए। इसके बाद उन्होंने सेठी द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल का जवाब दिया।

जयंती पर अवकाश की मांग का भाजपा ने किया विरोध : विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों की ओर से शेख अब्दुल्ला की जयंती पर सरकारी अवकाश बहाल करने की मांग उठाई गई। भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर सदन में राजनीतिक मतभेद देखने को मिले। भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट कर अपना विरोध दर्ज कराया।

शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। उनकी जयंती पर सरकारी अवकाश को लेकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मत रहे हैं। विधानसभा में मंगलवार को इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक बहस का रूप लिया।

अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाते रहे सेठी: भाजपा विधायकों के सदन से बाहर जाने के बावजूद युधवीर सेठी कार्यवाही में शामिल रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विषय विधानसभा में उठाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके सवाल का जवाब दिया और इस दौरान सेठी के सदन में बने रहने का उल्लेख किया।

सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़, सूचना प्रदूषण से कमजोर हो रहा सामाजिक विश्वास





डॉ. अवधेश कुमार यादव
सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार, कुल्लू कॉलेज

डिजिटल युग सूचना की बाढ़ लेकर आया है। हर सेकंड में लाखों-करोड़ों की संख्या में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेज पोस्ट दुनियाभर में फैल रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अभूतपूर्व रूप से सूचना की पहुंच को सुलभ बनाया है।

इस अभूतपूर्व तेजी ने 'सूचना प्रदूषण' के गंभीर खतरे को भी जन्म दिया है, क्योंकि मौजूदा समय में सत्य के साथ-साथ झूठी, आधी-अधूरी और गैर-जरूरी सूचनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सत्य और असत्य को पहचानना लगभग असंभव हो गया है। इसे मिसइनफार्मेशन (अनजाने में फैलाई गई भ्रामक सूचना), डिसइनफार्मेशन (जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना) और मालइनफॉर्मेशन (सही लेकिन दुरुपयोग की जा सकने वाली सूचना) के रूप में समझा जाता है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार- मिसइनफॉर्मेशन और डिसइनफॉर्मेशन के मामले में लगातार दूसरे वर्ष शॉर्ट-टर्म वैश्विक जोखिमों में सबसे ऊपर हैं। रिपोर्ट बताती है कि यह जोखिम समाज की एकता, शासन व्यवस्था और लोगों के आपसी विश्वास को गहराई से कमजोर कर रहा है। वैश्विक स्तर पर यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई विशेषज्ञ इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं।

इस संदर्भ में वैश्विक आंकड़े भयावह तस्वीर दिखाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, दुनियाभर में 86 प्रतिशत लोग कभी न कभी गलत सूचना के संपर्क में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर साझा होने वाली सामग्री में से 40 प्रतिशत फर्जी मानी जाती है। ऑनलाइन उपलब्ध कुल सामग्री में से 62 प्रतिशत के अविश्वसनीय या झूठी होने की संभावना होती है। एआई के उदय ने इस समस्या को और तेज कर दिया है। नकली वीडियो और नकली आवाज में 2019 से अब तक 550 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, 2025 में लगभग 80 लाख नकली वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए।

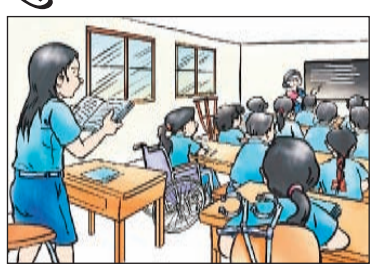
भारत इस समस्या का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। विश्व आर्थिक मंच की 2024 और 2025 की रिपोर्टों में भारत को गलत सूचना और जानबूझकर झूठी सूचना के सबसे ज्यादा जोखिम वाले देश के रूप में लगातार शीर्ष पर रखा गया है। 2025 की शुरुआत में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 80.6 करोड़ थी, जो वर्ष के अंत तक 90 करोड़ से अधिक हो गई।

इतनी बड़ी डिजिटल आबादी के साथ 'सूचना प्रदूषण' एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। इसका सबसे बड़ा स्रोत सोशल मीडिया है, जहां व्हाट्सऐप, फेसबुक और एक्स पर बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें फैलती हैं। फर्जी सूचनाओं का अधिकांश हिस्सा राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों से जुड़ा होता है, जो चुनावों और सामाजिक सद्भाव को सीधे प्रभावित करता है।

2024 के लोकसभा चुनावों और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एआई से बनी नकली ऑडियो, वीडियो और संदेशों का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे मतदाताओं को गुमराह किया गया। चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद अधिकांश फर्जी सामग्री पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी। सूचना प्रदूषण के दुष्प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी दिखाई देते हैं। इससे दंगे भड़कते हैं, विश्वास कमजोर होता है। इस समस्या का समाधान बहुस्तरीय होना चाहिए। डिजिटल साक्षरता, मजबूत फैक्ट-चेक व्यवस्था, तकनीकी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और नियमों का संतुलित क्रियान्वयन आवश्यक है। सही सूचना ही स्वस्थ समाज और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

जमाना बदल गया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी पुराने सवालों में उलझी हुई





रजनीश रांगड़ा, प्रधानाचार्य
स्वर्ण जयंती राजकीय (उत्कृष्ट) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, टौणी देवी

'कितना बदल गया जमाना' यह वाक्य अब केवल एक साधारण टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, छात्र जीवन और सामाजिक सोच पर खड़ा एक गहरा प्रश्न बन चुका है।

आज के विद्यार्थियों की आंखों में सपनों के साथ-साथ थकान है, उनके कंधों पर बस्तों से ज्यादा अपेक्षाओं का बोझ है और मन में सीखने से अधिक खुद को साबित करने की बेचैनी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम शिक्षा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे छात्र जीवन की शुरुआत सादगी से होती थी। स्लेट, खड़िया और लकड़ी की पटरी ही हमारी दुनिया थी। स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटना, मोरपंख किताब में रखना या पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर परीक्षा का तनाव कम करना-आज ये बातें हास्यास्पद लग सकती हैं, लेकिन उस मासूम विश्वास में सीखने का आनंद छिपा था। संसाधन कम थे, पर भरोसा बहुत था।

आज का छात्र स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड और अनंत ऑनलाइन सामग्री के बीच घिरा है। जानकारी की कमी नहीं, बल्कि इतनी अधिकता है कि सही दिशा ही खोती जा रही है। तकनीक ने शिक्षा को तेज और सुलभ बनाया है, लेकिन क्या उसने उसे संवेदनशील और मानवीय भी बनाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सीखने की रफ़्तार बढ़ा दी, लेकिन समझने की क्षमता घटा दी?

भटूरे में ईनो डालकर उसे फुलाना और फिर उसी ईनो से पेट की समस्या ठीक करना केवल खानपान का व्यंग्य नहीं, बल्कि हमारी पूरी आधुनिक जीवनशैली का प्रतीक है। पहले समस्या रची जाती है, फिर समाधान परोसा जाता है, और जब वही समाधान नई समस्या पैदा करता है तो उस पर नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी जाती है। यही स्थिति शिक्षा व्यवस्था में भी दिखती है। बच्चों पर भारी पाठ्यक्रम, अंकों की होड़ और रैंकिंग का दबाव डाल दिया जाता है, फिर उसी से पैदा हुए तनाव के लिए काउंसलिंग और वेलनेस प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। यह अंतहीन चक्र हमारी सामूहिक विफलता की ओर इशारा करता है। पहले पढ़ाई जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थी, कोई थोप दी गई शर्त नहीं। माता-पिता को न ट्यूशन की चिंता थी, न कोचिंग की दौड़। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते थे, संस्कार भी देते थे। आज के विद्यार्थी पिटते नहीं, पर टूटते जरूर हैं-तुलना, रैंक, सोशल मीडिया और 'टॉपर बनो' की सोच से। किताबों से रिश्ता था, उन्हें छूने और पलटने का आनंद था। आज ज्ञान स्क्रीन पर है, लेकिन धैर्य और जिज्ञासा संकट में हैं।

स्कूल का रास्ता भी सीखने का हिस्सा था। साइकिल पर दोस्तों के साथ जाना, नियम तोड़ना, लेकिन दोस्ती निभाना—ये सब जीवन का पाठ थे। आज बच्चे गाड़ियों में अकेले, हेडफोन लगाए चलते हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं, पर संवाद घटा है। शिक्षक-छात्र संबंध भी बदल गया है। शिक्षक अब मार्गदर्शक से अधिक 'रिजल्ट' से आंके जाते हैं और छात्र 'विद्यार्थी' से अधिक 'स्कोर' बनते जा रहे हैं। माता-पिता भी इस दबाव से अछूते नहीं हैं। पहले वे अच्छे इंसान बनने की उम्मीद रखते थे, आज करियर पैकेज और भविष्य की असुरक्षा में उलझे हैं। नतीजा यह है कि छात्र कम उम्र में ही थक जाता है। एक असफलता आज कई बच्चों को भीतर तक तोड़ देती है।

शिक्षा को फिर से मानवीय बनाना होगा। छात्र को केवल प्रतियोगी नहीं, जिज्ञासु बनाना होगा। तकनीक को साधन बनाना होगा, लक्ष्य नहीं। स्कूल को ऐसा स्थान बनाना होगा जहां बच्चा डर से नहीं, विश्वास से सीखे। तभी हम ईमानदारी से यह कह पाएंगे कि हम न केवल यह समझते हैं कि ज़माना कितना बदल गया है, बल्कि यह भी जानते हैं कि हमें अपने बच्चों और अपनी शिक्षा को किस दिशा में ले जाना है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

साइबर ठगी पर सख्ती जरूरी

साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग की ओर से सिम कार्ड के दुरुपयोग को लेकर जारी चेतावनी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल करने पर तीन वर्ष तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, केवल इस तरह की चेतावनी से साइबर धोखाधड़ी पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा, इसमें संदेह है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दूसरों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड हासिल करने या उन्हें उपलब्ध कराने का काम सामान्य उपभोक्ता नहीं, बल्कि साइबर अपराध से जुड़े लोग और उनके संपर्क में रहने वाले सिम विक्रेता करते हैं।

दूरसंचार विभाग को यह चेतावनी इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक प्वाइंट आफ सेल एजेंट ने कुछ नागरिकों के पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर 25 सिम कार्ड सक्रिय कर दिए थे। संबंधित नागरिकों को इसकी जानकारी तक नहीं थी और न ही उनकी सहमति ली गई थी। इससे स्पष्ट है कि उनके पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। यह घटना केवल एक व्यक्ति या एक स्थान की समस्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें लोगों की जानकारी के बिना उनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन जारी किए गए।

ऐसे मामलों को देखते हुए दूरसंचार विभाग को केवल चेतावनी जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सिम कार्ड जारी करने और बेचने की पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल उसकी जानकारी और सहमति के बिना मोबाइल कनेक्शन लेने में न हो सके। इसके लिए प्वाइंट आफ सेल एजेंटों की निगरानी, पहचान सत्यापन की प्रक्रिया और नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई को प्रभावी बनाना होगा। साथ ही, जिन लोगों के नाम पर संदिग्ध कनेक्शन जारी हुए हैं, उन्हें समय रहते इसकी जानकारी देने की व्यवस्था भी मजबूत की जानी चाहिए।

साइबर धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में मोबाइल नंबर और डिजिटल पहचान की भूमिका सामने आती है। फर्जी या गलत तरीके से हासिल किए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल लोगों को फोन करने, संदेश भेजने, बैंक संबंधी जानकारी हासिल करने और अन्य प्रकार की ठगी के लिए किया जाता है। इसलिए सिम कार्ड की बिक्री और सक्रियण से जुड़े नियमों को मजबूत करना साइबर अपराध की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उन रास्तों को बंद करना अधिक प्रभावी होगा, जिनका इस्तेमाल अपराधी ठगी को अंजाम देने के लिए करते हैं।

साइबर ठगी के साथ म्यूल खातों का इस्तेमाल भी एक गंभीर चुनौती है। ठगी की रकम को दूसरे खातों में पहुंचाने और फिर अलग-अलग माध्यमों से आगे भेजने के लिए ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका वास्तविक लाभार्थी कोई और होता है। ऐसे खातों की पहचान और निगरानी में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैंकिंग व्यवस्था में संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने, असामान्य गतिविधियों पर तत्काल निगरानी रखने और संबंधित एजेंसियों को सूचना देने की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।

यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में बैंक कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की जांच हुई है और कुछ कर्मचारी गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटल वित्तीय व्यवस्था में अंदरूनी स्तर पर होने वाली किसी भी लापरवाही या मिलीभगत से अपराधियों को लाभ मिल सकता है। बैंकिंग संस्थानों को अपने कर्मचारियों की निगरानी, पहुंच नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करनी होगी।

साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली लगातार बदल रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां किसी एक तरीके से अपराध रोकने का प्रयास करती हैं तो अपराधी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर नए रास्ते तलाश लेते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा की व्यवस्था भी लगातार बदलती तकनीक के अनुरूप विकसित करनी होगी। केवल अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं होगा। मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग व्यवस्था, डिजिटल पहचान और ऑनलाइन लेनदेन की उन कमजोरियों की पहचान करनी होगी, जिनका फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाते हैं।

मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा को नागरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना होगा। साइबर अपराधी कई बार ठगी की रकम को अलग-अलग खातों और माध्यमों से दूसरे राज्यों या विदेश तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति को अपनी रकम वापस पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कई मामलों में पूरी राशि वापस नहीं मिल पाती।

इसके साथ नागरिकों की जागरूकता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बार-बार चेतावनी और जागरूकता अभियानों के बावजूद लोग फर्जी फोन, संदेश, लिंक और डिजिटल लेनदेन से जुड़ी ठगी का शिकार हो रहे हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं को यह समझना होगा कि केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है।

-शिवांश धाकड़

हाइकु

मुमुक्षु के. ठाकुर,
ओबड़ी, चंबा, (हि. प्र.)

आज करोड़ों लोग हैं भूखे,
फिर भी देश हुआ समृद्ध महान,
चेहरों पर मुस्कान सजी है,
मन में छिपा हुआ तूफान।
चंचल मन अब बदल गया है,
सपनों का भी बदला गगन,
जिस जीवन में प्रेम था पहले,
वहां बढ़ा अब केवल स्वार्थ-बंधन।
उम्र गुजारी जग को साधने में,
पर खुद को समझ न पाए हम,
मिट्टी जैसी यह देह हमारी,
एक दिन मिल जाएगी मिट्टी में सनम।
अनगिनत स्वार्थों की संगत में,
मनुष्य स्वयं से दूर हुआ,
रिश्तों की गर्माहट खोकर, हर चेहरा मजबूर हुआ।
ऋण अभी भी शेष बहुत हैं,
कर्तव्य बाकी अनेक,
फिर भी मोह-माया में उलझे,
भूल गए जीवन का विवेक।
नारी ने भी रूप बदला है,
समय के संग बदली पहचान,
स्वतंत्र बनी, सपनों को पाया,
फिर भी बाकी कई अरमान।
आधुनिकता की तेज हवा में, संस्कार कहीं न खो जाएं,
अधिकारों के साथ कर्तव्यों को,
हम सब मिलकर याद दिलाएं।

अमीरों को सुविधाओं का लाभ और गरीबों को संघर्ष वर्षों बाद भी कायम है सामाजिक-आर्थिक असमानता





रामलाल पाठक
वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार
निहारखन बासला, बिलासपुर (हि.प्र.)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार अस्तित्व में आई। अंग्रेज भले ही हमारा देश छोड़कर चले गए, लेकिन कई बुराइयां अपने पीछे छोड़ गए। हमारे देश के लोगों ने उनमें से कुछ को तो विरासत में अपना लिया। नतीजन समाज में अमीर और गरीब की खाई और अधिक गहरी होती गई। सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का अमीर आदमी ने ही ज्यादा लाभ लिया।

सरकारी नौकरियों की बात हो या अन्य रोजगार की। अमीर के बेटे ने उच्च शिक्षा के साथ ही नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरू में स्कूल दूर थे तथा प्रशिक्षण प्राप्त करना गरीब व्यक्ति के बस में नहीं था। इसलिए वह सरकारी नौकरी या अन्य अच्छा रोजगार प्राप्त करने से वंचित रहा।

यही क्रम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहा। नतीजन अमीर और अधिक अमीर होता गया, जबकि गरीब व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कमरतोड़ संघर्ष कर रहा है। यही निर्धन वर्ग हर पांच साल के बाद आने वाले चुनावों में सरकार बदल देता है। उसने बीते पांच सालों में सरकार की कारगुजारियां देखी। इस बीच उसके जीवन स्तर में विशेष सुधार नहीं हुआ। चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आकर लोक-लुभावने वादे करते हैं। निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का धुंआधार प्रचार किया जाता है। जिस राजनीतिक दल का प्रत्याशी सबसे ज्यादा वादे करता है, निर्धन वर्ग का मतदाता उसी ओर आकर्षित हो जाता है।

राजनीतिक दलों की बादाखिलाफी के चलते हर पांच सालों के बाद सत्ता बदलती रहती है यानी किसी राजनीतिक दल की नीतियां एवं कार्यक्रम ठीक लगने पर ही सरकार दोबारा अगले पांच वर्षों तक चुनी जाती है। गरीब अमीर होने के सपने देखते रहते हैं तथा सरकारें बदलती रहती है। अंत में गरीब व्यक्ति मायूस होकर यह कह देता है कि उसे रोटी कमाकर ही मिलेगी। इसलिए कई बार तो वह वोट डालने से भी परेहज ही करता है। अब सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अच्छा खासा वेतन मिलता है तथा और भी अन्य कई सुविधाएं मिलती हैं।

समय के साथ ही वेतन बढ़ोतरी होती है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन मिलती है। आम किसान-मजदूर की आमदनी न के बराबर होती है। सरकारी कर्मचारियों की तरह उसे कोई भी सुविधा नहीं मिलती। यही नहीं, उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं होता। जीवनभर उसे अपने परिवार का भरण-पोषण मुश्किल होता है। जीवन के 60 वर्ष पर करने के बाद उसे सरकार की ओर से जो पेंशन मिलती है। वह इतनी कम होती है कि उससे दवा-दारू का खर्च भी नहीं चल पाता। बुढ़ापे में शरीर में कई बीमारियां लग जाती हैं।

समाज में शुरू से ही असमानता का वातावरण रहा और अब भी यही स्थिति है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई थी। आज भी यह स्थिति यथावत है। अपनी उपेक्षाओं के चलते गरीब आदमी गरीब ही होता जा रहा है। सरकार द्वारा उसके उत्थान के लिए जो योजनाएं शुरू की जाती हैं उनके धरातल पर संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आते।

जब सरकार बदलती है तो उनकी योजनाएं भी बदल जाती हैं। जब वह योजनाएं शुरू होती हैं, उस समय तक पांच साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तब तक सरकार फिर बदल जाती है। इसलिए समाज के उस वर्ग को किसी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरी तरह लाभ नहीं मिल पाता। समाज में गरीबी और असमानता की समस्या समय के साथ लगातार गहराती चली गई है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

मॉडलिंग से अभिनय तक नवनीत

नवनीत कौर ढिल्लों भारतीय अभिनेत्री और निर्माता हैं, जिन्होंने मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिताओं से मनोरंजन जगत तक अपनी पहचान बनाई। उनका जन्म 23 सितंबर 1992 को हरियाणा के अंबाला में हुआ। शुरुआती दौर में मॉडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और कैमरे के सामने सहज उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाने में मदद की। मनोरंजन जगत में काम करते हुए उन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और अलग-अलग तरह की भूमिकाओं के जरिए अभिनय क्षमता दिखाने का प्रयास किया।



नवनीत कौर ढिल्लों
जन्म : 23 सितंबर 1992

नवनीत कौर ढिल्लों के करियर की प्रमुख फिल्मों में वर्ष 2016 में आई 'लवशुदा' शामिल है। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया और हिंदी सिनेमा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म की कहानी रोमांस और रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 में आई फिल्म 'एकता' में काम किया। इस फिल्म के जरिए भी उन्हें अलग तरह के किरदार के साथ दर्शकों के सामने आने का अवसर मिला। अभिनय के साथ-साथ फिल्म निर्माण से जुड़कर नवनीत ने मनोरंजन उद्योग के दूसरे पहलू को भी समझने और उसमें काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

वर्ष 2020 में नवनीत कौर ढिल्लों पंजाबी फिल्म 'जिंदे मेरिये' में नजर आईं। फिल्म में उन्होंने मुख्य कलाकारों के साथ अभिनय किया और पंजाबी सिनेमा में अपनी मौजूदगी को आगे बढ़ाया। पंजाबी फिल्मों में काम करने के कारण उन्हें क्षेत्रीय दर्शकों के बीच भी पहचान मिली। मनोरंजन जगत में उनका सफर केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मॉडलिंग और विभिन्न मंचों से जुड़ी गतिविधियों में भी वह सक्रिय रही हैं।

नवनीत कौर ढिल्लों के करियर में सौंदर्य प्रतियोगिताओं और मॉडलिंग का अनुभव महत्वपूर्ण रहा है। कैमरे के सामने काम करने का शुरुआती अनुभव बाद में उनके अभिनय करियर में भी उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने अलग-अलग परियोजनाओं में काम करते हुए मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान कायम रखने की कोशिश की है।

बच्चों को सफलता की दौड़ में आगे बढ़ाने के साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी जरूरी





नरेंद्र भारती
स्वतंत्र लेखक, मंडी

आज का समाज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विज्ञान, तकनीक और भौतिक विकास ने मानव जीवन को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सरल बनाया है। संचार के साधनों ने दूरियों को कम किया है और दुनिया को एक-दूसरे के करीब ला दिया है। इसके बावजूद इसी आधुनिकता के बीच नैतिक मूल्यों का क्षरण भी तेजी से दिखाई दे रहा है। ईमानदारी, सत्य, करुणा, प्रेम, त्याग, सहनशीलता और विश्वास जैसे गुण, जो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाते हैं, आज कई स्तरों पर कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे गहरा असर हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर पड़ रहा है।

नैतिक मूल्य केवल किताबों में पढ़ाए जाने वाले आदर्श नहीं हैं, बल्कि वे हमारे व्यवहार और संबंधों की नींव होते हैं। परिवार में प्रेम और विश्वास हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से पार की जा सकती हैं। इसके विपरीत जब स्वार्थ रिश्तों पर हावी होने लगता है तो मजबूत से मजबूत संबंधों में भी दरार पड़ने लगती है। आज माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी, भाई-बहनों के बीच बढ़ती दूरी और समाज में आपसी विश्वास का कमजोर होना इसी बदलाव की ओर संकेत करता है। रिश्ते जो कभी आत्मीयता और अपनत्व पर आधारित होते थे, उनमें अब कई बार औपचारिकता और स्वार्थ का प्रभाव दिखाई देता है।

आज व्यक्ति अपने हित को प्राथमिकता देने लगा है। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके दुख-दर्द में सहभागी बनने की प्रवृत्ति कमजोर हो रही है। आर्थिक सफलता और व्यक्तिगत उपलब्धियों को जीवन की सफलता का प्रमुख पैमाना मान लिया गया है। परिणामस्वरूप मनुष्य के पास सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए समय कम होता गया है। परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी अपनी-अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। संवाद की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है और आमने-सामने बैठकर बातचीत करने की आदत कम होती जा रही है।

सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पहले पड़ोसी एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते थे। मोहल्ले और गांव सामूहिक जीवन की भावना से जुड़े होते थे। आज महानगरीय जीवनशैली और व्यस्तता ने सामाजिक संबंधों को सीमित कर दिया है। लोग आसपास रहने वालों से अधिक आभासी दुनिया से जुड़े नजर आते हैं। सामाजिक माध्यमों पर हजारों संपर्क होना अलग बात है, लेकिन वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति के दुख में उसके साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। यह विरोधाभास आधुनिक जीवन की बड़ी चुनौती बन गया है।

मोबाइल और सामाजिक माध्यमों का विस्तार इस स्थिति को और जटिल बना रहा है। तकनीक अपने आप में न तो अच्छी है और न बुरी। उसका उपयोग किस उद्देश्य और किस सीमा तक किया जाता है, यही महत्वपूर्ण है। समस्या तब पैदा होती है जब तकनीक हमारे जीवन का साधन न रहकर हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगे। आज कई लोग परिवार के साथ बैठकर भी मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक स्क्रीन का बढ़ता समय वास्तविक संवाद और संवेदनशीलता को प्रभावित कर रहा है। दूसरे के दुख को समझने के लिए जिस धैर्य और भावनात्मक उपस्थिति की जरूरत होती है, वह लगातार कम होती जा रही है।

नैतिक मूल्यों का संकट केवल परिवार तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव शिक्षा, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन पर भी दिखाई देता है। यदि सफलता का अर्थ केवल अधिक धन, ऊंचा पद और अधिक सुविधाएं हासिल करना बन जाए तो ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी पीछे छूट सकती है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन ऐसी प्रतिस्पर्धा जो मनुष्य को दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना दे, समाज के लिए नुकसानदेह है। बच्चों को केवल अच्छे अंक और बेहतर करियर की दौड़ में आगे बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी सिखाना जरूरी है कि सफलता के साथ जिम्मेदारी, सहयोग, करुणा और ईमानदारी का होना उतना ही महत्वपूर्ण है।

नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। बच्चे वही अधिक सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि माता-पिता ईमानदारी, सम्मान और संवेदनशीलता का व्यवहार करेंगे तो बच्चों पर उसका स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा। केवल उपदेश देकर नैतिकता नहीं सिखाई जा सकती। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंद की सहायता, मिल-बांटकर रहने की आदत और दूसरों की भावनाओं का सम्मान जैसे छोटे-छोटे व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

विद्यालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार योग्य बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को केवल एक विषय के रूप में शामिल करने के बजाय विद्यालयी वातावरण में उसे व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सहयोग, अनुशासन, सहिष्णुता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा से जोड़ना चाहिए। शिक्षक स्वयं अपने आचरण से विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

माता-पिता की रजामंदी जरूरी नहीं बालिग महिला चुन सकती है अपना साथी

एजेंसी, प्रयागराज

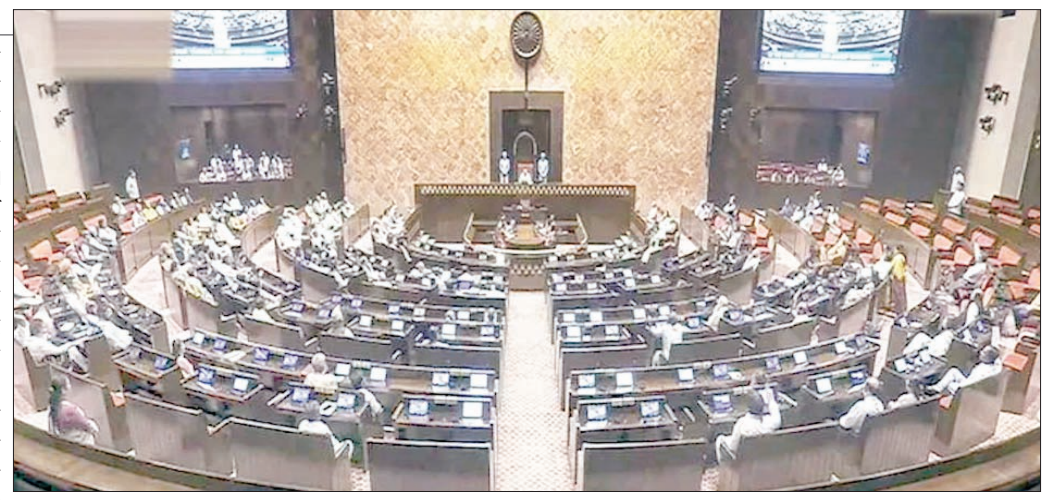
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि बालिग महिला को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है। इसके लिए माता-पिता या परिवार की रजामंदी जरूरी नहीं है। अदालत ने गाजियाबाद की 26 वर्षीय सोनिका चौहान को अपनी पसंद के पति के साथ रहने की अनुमति दी है। महिला के पिता को यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था। मामला गाजियाबाद का है, जहां महिला के संबंध और उसके साथ रहने को लेकर विवाद सामने आया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बालिग व्यक्ति के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के अधिकार को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग महिला अपनी इच्छा से जीवन के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2026 के आदेश के तहत राज्य सरकार को सोनिका चौहान को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की पुलिस ने महिला को अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान महिला की इच्छा और उसके साथ रहने के फैसले को ध्यान में रखा गया। अदालत ने महिला को अपनी पसंद के पति के साथ रहने की अनुमति दे दी। इस मामले में महिला के पिता की ओर से रिश्ते को स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद अदालत ने बालिग महिला के अधिकार को प्राथमिकता दी। कोर्ट के आदेश के बाद महिला अपने चुने हुए जीवनसाथी के साथ रह सकेगी। हाई कोर्ट का यह आदेश बालिग व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के अधिकार से जुड़ा है। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि बालिग महिला के निजी जीवन से जुड़े फैसले में केवल परिवार की असहमति उसके अधिकार को समाप्त नहीं करती।

राज्यसभा की इन सीटों पर 16 अक्टूबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव

एजेंसी, लखनऊ



उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए मतदान की तारीख 16 अक्टूबर तय की है। इसके साथ ही उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होगा। चुनाव आयोग के अनुसार, दोनों राज्यों की संबंधित सीटों पर मतदान और मतगणना 16 अक्टूबर को ही कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली होंगी। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, बृजलाल, बीएल वर्मा, राम गोपाल यादव, नीरजा शेखर, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, रामजी, सीमा और डॉ. दिनेश शर्मा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, राज्यसभा चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी। वहीं, उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा।

मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना पूरी होने के बाद देर शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की व्यवस्था है। राज्यसभा के चुनाव में संबंधित राज्य के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान निर्धारित प्रक्रिया और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है।

उत्तर प्रदेश से इस चुनाव में 10 राज्यसभा सीटें शामिल होने के कारण राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। हालांकि, उम्मीदवारों के नाम और चुनाव में वास्तविक मुकाबले की स्थिति नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। यदि किसी सीट पर आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराया जाएगा।

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट भी इसी चुनाव कार्यक्रम का हिस्सा है। आयोग ने दोनों राज्यों के लिए मतदान और मतगणना की तारीख एक ही रखी है। इससे चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी होगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन से लेकर मतगणना तक सभी चरण तय तारीखों पर होंगे। 29 सितंबर को अधिसूचना, 6 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख, 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 9 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी।

कानपुर में खौफनाक वारदात, सड़क किनारे मिला युवक का सिर कटा शव



एजेंसी, कानपुर। कानपुर के बिल्हौर में मंगलवार सुबह मकनपुर रोड पर सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खुर्द खोजनपुर मोड़ के पास सड़क किनारे करीब नौ बजे युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान राज किशोर पटवा के रूप में हुई है। शव के पास ही उसकी साइकिल मिली, जबकि कुछ दूरी पर शर्ट का फटा हुआ कालर और अंगौछा पड़ा था।

पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की तो सड़क किनारे पानी से भरे एक गड्ढे में युवक का सिर पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। स्वजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी और एसीपी अंकित कुमार भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

फिलहाल पुलिस हत्या के साथ दुर्घटना के बिंदु पर भी जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले सामान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की जांच के बाद ही युवक की मौत के कारण और घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने मृतक के स्वजन से भी जानकारी जुटाई है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और आसपास के हालात की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सही वजह सामने आएगी।

न्यूज ब्रीफ

पांच साल तक के बच्चों का घर बैठे बनेगा आधार कार्ड

एजेंसी, आगरा। पांच साल तक के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनवाने के लिए अभिभावकों को अब आधार केंद्र या डाकघर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) दिसंबर से नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत माता या पिता अपने मोबाइल फोन में आधार एप के माध्यम से घर बैठे बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकेंगे। नई सुविधा से छोटे बच्चों का आधार बनवाने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। यूआईडीएआई के अनुसार, पांच साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आधार बनवाते समय बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे की पहचान और अन्य जरूरी जानकारी अभिभावकों के माध्यम से दर्ज की जाएगी। अभिभावकों को मोबाइल एप पर उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार बच्चे की जानकारी भरनी होगी।

पितरों को तृप्त करने का 'पैकेज' प्रयागराज से काशी-गया तक सुविधा

एजेंसी, प्रयागराज। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने वालों की सुविधा के लिए प्रयागराज में 'पितृ पैकेज' शुरू किया गया है। जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति की ओर से शुरू की गई इस व्यवस्था में पिंडदान करने वालों को कई सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। पैकेज के तहत प्रयागराज के अलावा काशी और गया में तीर्थ पुरोहितों का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही आने-जाने, खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था भी शामिल रहेगी। समिति की ओर से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस पैकेज का प्रचार किया जा रहा है। जो लोग प्रयागराज नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है।

प्रयागराज में कल होगा रोजगार महोत्सव 3000 से अधिक पदों पर भर्ती

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में कल एक दिवसीय रोजगार महोत्सव-2026 आयोजित किया जाएगा। रोजगार महोत्सव सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें निजी क्षेत्र की करीब 20 कंपनियां अभ्यर्थियों का सीधे चयन करेंगी। विभिन्न पदों पर 3000 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती प्रस्तावित है। चयनित अभ्यर्थियों को 10 हजार से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलने की संभावना है। रोजगार मेले में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, पालीटेक्निक, बीटेक और एमबीए उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर रोजगार मेले में प्रतिभाग करना होगा।

मिट्टी लेने गए पांच बच्चों में दो दबे चचेरे भाई-बहन की दर्दनाक मौत

एजेंसी, अलीगढ़। अलीगढ़ के परौरा गांव में मंगलवार को मिट्टी की ढाय खिसकने से चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई। दोनों घर की चौका-पुताई के लिए भट्ठे के पास मिट्टी लेने गए पांच बच्चों में शामिल थे। मिट्टी की ढाय अचानक खिसकने से 8 वर्षीय कौशल और 13 वर्षीय काजल उसके नीचे दब गए। उनके साथ मौजूद तीन बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला। परिजन दोनों को छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया। एसडीएम अतरौली ने तहसीलदार और लेखपाल को मौके पर भेजकर घटना की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कौशल गांव के ही स्कूल में कक्षा दो का छात्र था।

अलीगढ़ में चलती ऑटो में महिला से दुष्कर्म, छह घंटे में आरोपी गिरफ्तार



एजेंसी, अलीगढ़। अलीगढ़ में चलती ऑटो में सवार महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह घंटे के भीतर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी चालक और ऑटो का सुराग लगाकर उसे दबोचा। जानकारी के अनुसार, महिला ऑटो में सवारी के तौर पर बैठी थी। इसी दौरान चालक पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद थाना महुआ खेड़ा पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी चालक की तलाश की। छह घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।

हरदुआगंज प्लांट में बड़ा खतरा, कन्वेयर बेल्ट फटने से कोयला आपूर्ति प्रभावित

एजेंसी, अलीगढ़



हरदुआगंज तापीय परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर 10 में सोमवार को कन्वेयर बेल्ट फटने से कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो गई। चालू हालत में अचानक बेल्ट नंबर 'सीबी' के फट जाने के कारण यूनिट को होने वाली कोयले की आपूर्ति आधी रह गई है। इससे परियोजना में संकट की स्थिति बन गई है।

फिलहाल पूरे सिस्टम को केवल एक कन्वेयर बेल्ट के सहारे चलाया जा रहा है। इससे दूसरी बेल्ट पर अचानक दोगुना भार पड़ गया है। इस कारण उसके भी क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। परियोजना में कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयला यूनिट के बंकरों तक पहुंचाया जाता है। एक बेल्ट के खराब होने से आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। यदि दूसरी कन्वेयर बेल्ट भी क्षतिग्रस्त होकर टूट जाती है तो यूनिट के बंकरों तक कोयले की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है। इससे बिजली उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ने की आशंका है।

बेल्ट फटने की घटना के बाद परियोजना प्रबंधन के सामने कोयला आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट में कोयले की आपूर्ति आधी होने से उत्पादन व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। एक ही बेल्ट पर निर्भर रहने के कारण आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। फिलहाल यूनिट को उपलब्ध कन्वेयर बेल्ट के सहारे संचालित किया जा रहा है और दूसरी बेल्ट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है।

कानपुर को मिला नया डीएम, महेंद्र सिंह तंवर की हुई तैनाती

एजेंसी, कानपुर



उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए कानपुर के जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह का तबादला कर दिया गया। शासन ने उन्हें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक पद पर नई जिम्मेदारी दी है। वहीं कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को कानपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत दोनों अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।

जितेन्द्र प्रताप सिंह अब राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। कानपुर के जिलाधिकारी के तौर पर उनकी जगह महेंद्र सिंह तंवर को भेजा गया है। महेंद्र सिंह तंवर इससे पहले कुशीनगर के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। शासन के आदेश के बाद अब उन्हें कानपुर जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

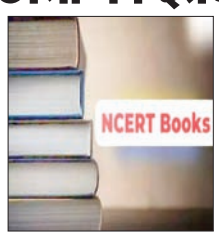
कानपुर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और बड़े महानगरों में शामिल है। जिले में प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिलाधिकारी के स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी, कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में समन्वय, राजस्व प्रशासन और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं।

नए जिलाधिकारी की तैनाती के बाद इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह तंवर संभालेंगे। महेंद्र सिंह तंवर कुशीनगर में जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अब शासन ने उनका स्थानांतरण कानपुर कर दिया है। वहीं कानपुर के मौजूदा जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निदेशक बनाया गया है। दोनों अधिकारियों के तबादले को प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा बताया गया है।

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नई तैनाती तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुसार कार्यभार संभालने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कानपुर में नए जिलाधिकारी की तैनाती के साथ जिला प्रशासन के स्तर पर नेतृत्व में बदलाव होगा। नई जिम्मेदारी के साथ प्रशासनिक कार्यों में बदलाव आएगा।

◆ **नई** तैनाती के बाद महेंद्र सिंह तंवर के सामने कानपुर में कानून-व्यवस्था, राजस्व मामलों और विकास योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। वहीं जितेन्द्र प्रताप सिंह राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दोनों अधिकारियों की नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू होगी और कार्यभार सौंपा जाएगा।

कक्षा 9 की गणित मंजरी भाग 2 उपलब्ध, छात्रों का इंतजार खत्म



एजेंसी, मेरठ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं की संशोधित गणित पाठ्यपुस्तक 'गणित मंजरी' भाग-2 उपलब्ध करा दी है। सोमवार से पुस्तक की बिक्री शुरू होने के साथ ही कक्षा नौवीं गणित की संशोधित पाठ्यपुस्तक का पूरा संसाधन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध हो गया है। पुस्तक का भाग-1 पहले ही जारी किया जा चुका है।

नई पुस्तक में गणित की अवधारणाओं को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच गणित को लेकर समझ को बेहतर बनाना और विषय को केवल सूत्रों तथा सवालों तक सीमित रखने के बजाय व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ना है। पुस्तक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूली शिक्षा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है।

गणित मंजरी भाग-2 में विद्यार्थियों को विषय की अवधारणाओं को गतिविधियों, उदाहरणों और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े संदर्भों के माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को गणितीय सोच विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुस्तक की सामग्री तैयार करते समय सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और रुचिकर बनाने पर ध्यान दिया गया है।

मेरठ में पुलिस की जेल भेजने की धमकी से डरी बुजुर्ग महिला ने दी जान

एजेंसी, मेरठ। मेरठ में पुलिस की जेल भेजने की धमकी से सहमी सेवानिवृत्त शिक्षक की 62 वर्षीय पत्नी ने शनिवार देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। महिला का पिछले कई दिनों से पेंशन को लेकर अपने बेटे के साथ विवाद चल रहा था। बताया गया कि शनिवार रात विवाद बढ़ने पर गुस्साई वृद्धा ने बेटे और पोते पर टायलेट क्लीनर फेंक दिया। इसके बाद परिवार में तनाव की स्थिति बन गई। परिजनों के अनुसार, घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जेल भेजने की धमकी दी। इसी बात से महिला काफी डर गई थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई की बात से वह सहम गई और मानसिक रूप से परेशान हो गई। देर रात उसने घर में फांसी लगा ली। परिवार के लोगों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो आनन-फानन में नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिवार के सदस्यों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। साथ ही महिला और उसके बेटे के बीच चल रहे विवाद की भी जांच की जा रही है। बताया गया कि विवाद सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन को लेकर था। परिवार में इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से कहासुनी चल रही थी। शनिवार रात विवाद बढ़ने के बाद महिला ने बेटे और पोते पर टायलेट क्लीनर फेंक दिया था।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत, 25 प्रतिशत जमा पर मिलेगा पीडीए फ्लैट

◆ सरकारी कर्मचारियों के लिए आसान हुआ घर का सपना

एजेंसी, प्रयागराज



प्रयागराज में सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना घर खरीदना आसान होने जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में बने फ्लैटों की बिक्री करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इच्छुक कर्मचारियों को फ्लैट की पूरी कीमत एकमुश्त जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर ही फ्लैट का कब्जा देने की व्यवस्था की जा रही है।

पीडीए की इस योजना के तहत शेष 75 प्रतिशत धनराशि सात वर्ष में आसान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। इससे उन सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, जो एक साथ पूरी रकम जमा करने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत अलग-अलग आवासीय योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों की बिक्री की जाएगी। पीडीए अपने छह आवासीय योजनाओं में कुल 465 फ्लैटों की बिक्री करेगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को फ्लैट लेने का अवसर दिया जाएगा।

योजना में भुगतान की शर्तों को इस तरह रखा गया है कि शुरुआती तौर पर कम राशि जमा कर कर्मचारी फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर सकें और बाद में निर्धारित अवधि में शेष रकम चुका सकें। योजना में एक और विशेष सुविधा दी गई है। यदि खरीदार शेष 75 प्रतिशत धनराशि 45 से 90 दिन के भीतर जमा कर देता है तो उसे चार से छह प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यानी पूरी रकम जल्दी जमा करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा।

नामांतरण मेरठ के कॉलेज की बदली पहचान, अब कहलाएगा चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज

मेरठ के जनता पीजी कॉलेज को मिला चौधरी चरण सिंह का नाम

एजेंसी, लखनऊ



मेरठ के मवाना तहसील के फलावदा कस्बा स्थित जनता पीजी कॉलेज का नाम अब चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज कर दिया गया है। शासन ने कॉलेज का नाम बदलने की प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए इसे नया नाम दिया है। इसके बाद कॉलेज की पहचान अब चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के रूप में होगी।

कॉलेज के नाम परिवर्तन की कार्यवाही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की कार्यपरिषद की संस्तुति के आधार पर पूरी की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से नाम बदलने की संस्तुति शासन को भेजी गई थी। इसके बाद शासन स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए कॉलेज के नए नाम को मंजूरी प्रदान की गई। नाम परिवर्तन के बाद अब फलावदा स्थित इस महाविद्यालय का आधिकारिक नाम चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज होगा। जनता पीजी कॉलेज के नाम से पहचाने जाने वाले संस्थान को अब पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कॉलेज के नाम परिवर्तन को महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के योगदान और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। कॉलेज का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर किए जाने से विद्यार्थियों को उनके योगदान और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। शासन की मंजूरी के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब कॉलेज से जुड़े दस्तावेजों और संस्थान की पहचान में नए नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।

फलावदा कस्बे में स्थित इस कॉलेज का नाम बदलने का निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की संस्तुति के बाद लिया गया है। कॉलेज के नामकरण को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसे महापुरुषों के योगदान को याद रखने और नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाने से जोड़कर देखा गया है। शासन की मंजूरी के साथ ही जनता पीजी कॉलेज की पुरानी पहचान बदलकर चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के रूप में स्थापित हो गई है।

कॉलेज की बदली पहचान

नाम परिवर्तन के बाद अब महाविद्यालय से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेजों, अभिलेखों और संस्थागत पहचान में चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉलेज के नए नाम को लेकर शासन स्तर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की संस्तुति के बाद शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे फलावदा स्थित महाविद्यालय की पुरानी पहचान अब बदल गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नामकरण के पीछे महापुरुषों के योगदान को स्मरण करने और विद्यार्थियों को उनके विचारों से परिचित कराने का उद्देश्य है। कॉलेज के नाम परिवर्तन के बाद स्थानीय स्तर पर भी इसकी नई पहचान स्थापित होगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़े रिकॉर्ड में भी नए नाम का प्रयोग किया जाएगा।

आगरा के नगला परमाल में चोरी एक करोड़ का माल लेकर फरार चोर

एजेंसी, आगरा



आगरा के थाना कागारौल क्षेत्र के गांव नगला परमाल में रात अज्ञात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दोनों घरों से नकदी समेत करीब एक करोड़ रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण समेटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह होने पर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में भी चोरी की घटना को लेकर दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, चोर रात के समय दोनों घरों में घुसे और कमरों में रखे सामान को खंगालना शुरू कर दिया। चोरों ने घरों में रखी नकदी और सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह परिवार के लोगों की नींद खुलने पर घर का सामान बिखरा मिला। जांच करने पर चोरी का पता चला। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कागारौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ित परिवारों से चोरी हुए सामान और नकदी की जानकारी जुटाई।

प्रारंभिक जानकारी में चोरी हुए आभूषणों और अन्य सामान की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

फरीदाबाद में टैंकर की टक्कर से महिला कर्मी की मौत, चालक फरार

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद



फरीदाबाद में एनएचपीसी के पास रात हुए सड़क हादसे में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला कर्मी की मौत हो गई। पानी के टैंकर ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में 36 वर्षीय आशा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। स्कूटी पर सवार दूसरी महिला कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। सराय थाना पुलिस के अनुसार, आशा एसजीएम नगर की 22 फुट रोड की रहने वाली थी। वह ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर कार्यरत थी। इन दिनों उसकी ड्यूटी एनएचपीसी के पास स्थित ईएसआईसी गर्ल्स हॉस्टल में लगी हुई थी। सोमवार रात ड्यूटी खत्म करने के बाद आशा अपनी महिला सहकर्मी के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी।

इसी दौरान एनएचपीसी के पास पानी के टैंकर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों महिलाएं सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। आशा की हालत गंभीर होने के कारण उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दूसरी घायल महिला का उपचार जारी है। पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

जीटी रोड जाम करने पहुंचे किसान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार को धान की सरकारी खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की ओर से जीटी रोड जाम करने का ऐलान किया गया था। किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान सड़क जाम करने के लिए आगे बढ़े। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जानकारी के अनुसार, धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान नाराज हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं। मंगलवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल की उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के साथ बैठक हुई। हालांकि, बैठक में मांगों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद किसानों ने जीटी रोड जाम करने का फैसला किया।

किसानों के सड़क की ओर बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान फ्लाईओवर पर चढ़ गए। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जीटी रोड पर यातायात प्रभावित होने की आशंका के बीच पुलिस ने व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया है। किसानों का कहना है कि धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू होनी चाहिए, ताकि मंडियों में पहुंचने वाली फसल की खरीद में किसानों को परेशानी न हो। वहीं, प्रशासन की ओर से किसानों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कुरुक्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र में किसान आंदोलन को लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस की कार्रवाई और किसानों के प्रदर्शन के चलते स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

बहादुरगढ़ में 1.50 लाख की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार, विजिलेंस ने पकड़ा रंगे हाथ

शिकायत पर रोहतक विजिलेंस ने बिछाया जाल, रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बहादुरगढ़



बहादुरगढ़ में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने बहादुरगढ़ शहर थाने में तैनात अनुसंधान अधिकारी एएसआई नवीन को 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपित की पहचान 52 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है। वह मूल रूप से रोहतक जिले के मकड़ौली गांव का रहने वाला बताया गया है।

मामले में शिकायतकर्ता अनमोल निवासी आमिकोन-1, लोहिया एन्क्लेव, ग्रेटर नोएडा ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह प्रापर्टी डीलर का काम करता है। उसकी सास सुनीता के खिलाफ बहादुरगढ़ शहर थाने में मामला दर्ज था। जांच आगे बढ़ने के दौरान शिकायतकर्ता की पत्नी अनु चहल, साली जन्नत और ससुर धनेंद्र को भी मामले में आरोपित बनाया गया था। शिकायत के अनुसार, मामले की जांच कर रहे एएसआई नवीन ने शिकायतकर्ता की पत्नी, साली और ससुर का नाम केस से हटाने की एवज में तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में रिश्वत की रकम को लेकर सौदा 1.50 लाख रुपये में तय हुआ।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जानकारी रोहतक विजिलेंस टीम को दी। शिकायत मिलने के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की। टीम ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद कार्रवाई की योजना बनाई। इसके तहत शिकायतकर्ता को तय रकम लेकर एएसआई के पास जाने के लिए कहा गया। विजिलेंस टीम ने भी पूरी कार्रवाई के दौरान निगरानी रखी।

सोमवार को बहादुरगढ़ शहर थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता ने एएसआई नवीन को तय 1.50 लाख रुपये की रिश्वत दी। जैसे ही एएसआई ने रकम स्वीकार की, विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने आरोपित एएसआई को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिश्वत की मांग और मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

हरियाणा की 106 नहरों को मिलेगा 'जल कवच', 2484 करोड़ होंगे खर्च

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर



हरियाणा की 106 नहरों को टूटने, क्षतिग्रस्त होने और पानी की बर्बादी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश की इन नहरों को मजबूत बनाने और उनकी जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए 2484.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कार्य 'जल संरक्षित हरियाणा' परियोजना के तहत किया जाएगा।

विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश की नहरों को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना है। परियोजना के तहत नहरों के कमजोर हिस्सों की पहचान कर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही नहरों की पानी ले जाने की क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी। इससे नहरों में पानी के प्रवाह को बेहतर बनाने और क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में नहरों की क्षमता बढ़ने और कमजोर हिस्सों के मजबूत होने से सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत 106 नहरों पर होने वाला यह काम जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, नहरों के सुदृढ़ीकरण से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और पानी को अधिक प्रभावी तरीके से खेतों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

झज्जर में नशे की खेप के साथ युवक गिरफ्तार पुलिस ने बरामद किया 4.40 किलो गांजा

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर



झज्जर जिला सीआईए टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 4 किलो 40 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को थाना सदर झज्जर क्षेत्र से पकड़ा गया। उसकी पहचान रवि निवासी मदनपुर डबास, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, सीआईए टीम क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक युवक गांजे की खेप लेकर इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध युवक को चिन्हित किया। टीम ने उसे रोककर पूछताछ की और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान युवक के पास मौजूद प्लास्टिक के कट्टे से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ का वजन कराया, जो 4 किलो 40 ग्राम निकला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रवि को हिरासत में ले लिया। बरामद गांजे को कब्जे में लेकर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह गांजा कहां से लेकर आया था और इसकी सप्लाई किसे करने वाला था।

इसके अलावा पुलिस आरोपी के संपर्क में रहने वाले लोगों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ के लिए उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से एक दिन का पुलिस रिमांड मिला। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गांजे की खरीद-फरोख्त और उसके संभावित साथियों के बारे में जानकारी हासिल करेगी।

यमुनानगर में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत ट्रैक्टर-ट्राली में मिला शव

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर जिले के छछरौली थाना क्षेत्र के गांव जयधर में खाली ट्रैक्टर-ट्राली से 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अरुण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अरुण करीब तीन दिन पहले गांव के कुछ मजदूरों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली में भूसा लेकर हिमाचल प्रदेश गया था। सोमवार को उसके साथ गए अन्य लोग वापस गांव लौट आए, जबकि अरुण का शव गांव में खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिजनों ने अरुण की मौत को संदिग्ध बताते हुए उसके साथ हिमाचल गए चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

लिव-इन प्रेमिका का गर्भपात कराने का मामला, फर्जी महिला डॉक्टर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार



हरियाणा के हिसार में अवैध रूप से गर्भपात कराने और नवजात को ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने एक फर्जी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान गीता के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह गोहाना में 'कृष्णा क्लिनिक' नाम से अवैध क्लिनिक चला रही थी और इसी क्लिनिक में युवती को गर्भपात की दवाई दी गई थी।

मामले की शुरुआत 8 जुलाई को हुई थी। पुलिस ने हिसार के ऋषि नगर और सेक्टर-14 क्षेत्र में एक नवजात को फेंकने की कोशिश करते हुए आरोपी अनिल कुमार को पकड़ा था। अनिल की उम्र 29 वर्ष है और वह गांव नियाणा का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि अनिल और युवती पिछले करीब सात साल से प्रेम संबंध में थे और हिसार में लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे।

पुलिस के अनुसार युवती के गर्भवती होने के बाद दोनों ने गर्भपात कराने का फैसला लिया। इसके बाद युवती को गर्भपात की दवाई दी गई। मामले में पुलिस ने पहले अनिल और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया था। जांच आगे बढ़ने पर उस महिला का नाम सामने आया, जिसने कथित तौर पर युवती को गर्भपात की दवा उपलब्ध कराई थी। पुलिस ने आरोपी महिला गीता को गिरफ्तार कर लिया।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने खरगे को सौंपा एक साल का रिपोर्ट कार्ड, बताया आगे का रोडमैप

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर अपने एक साल के संगठनात्मक कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। राव नरेंद्र को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 29 सितंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान संगठन को जिला और ब्लॉक स्तर तक सक्रिय करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को दी।

राव नरेंद्र के कार्यकाल में जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। संगठन के इस चरण को पूरा करने के बाद अब प्रदेश कमेटी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाना अगला लक्ष्य बताया गया है। बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित सम्मेलनों तथा पार्टी नेताओं को एक मंच पर लाने से जुड़ी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। राव नरेंद्र ने खरगे को संगठन में किए गए बदलावों के पहले चरण से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग स्तरों पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी काम किया गया है।

मुलाकात के दौरान हरियाणा के राजनीतिक हालात के साथ संगठन की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। राव नरेंद्र ने अगले तीन महीनों के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी पार्टी अध्यक्ष को दी। इसमें संगठन के अगले चरण से जुड़े काम और प्रदेश स्तर पर कमेटी गठन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से शामिल है। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी चर्चा हुई। जिला और ब्लॉक स्तर पर ढांचा तैयार होने के बाद अब प्रदेश कमेटी के गठन के साथ संगठन को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है।

राव नरेंद्र ने अपने एक साल के कार्यकाल में हुए संगठनात्मक कामकाज का विस्तृत ब्योरा खरगे के सामने रखा। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों के साथ आने वाले समय की प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। अब प्रदेश कमेटी के गठन और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने को आगे की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। प्रदेश कमेटी गठन और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की तैयारी, संगठन को मिलेगा नया विस्तार।

सावन हत्याकांड में नया विवाद, परिजनों ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक



पाडा मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय सावन की हत्या के मामले में अब उसके परिवार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के सदस्य मंगलवार को रोहतक एसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि सावन हत्याकांड में नामजद आरोपी लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं।

परिवार का कहना है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। इसी कारण परिवार के सदस्यों में भय का माहौल है और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। जानकारी के अनुसार, पाडा मोहल्ले में 24 जनवरी 2026 को सावन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एफआईआर में आशु, शिवम, रविंद्र, सुरेंद्र, बिजेंद्र, चांद, निहाल, शंकर, रितिक, नवीन, फाटा, दीपक, चिराग और अभिषेक समेत अन्य लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं। परिजनों ने एसपी को दी शिकायत में आरोप लगाया कि हत्या के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है।

परिवार ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि सावन की हत्या के बाद से ही वे मानसिक दबाव में हैं और अब उन्हें लगातार अपनी सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। परिजनों ने कहा कि सुरक्षा मिलने से वे बिना भय के मामले की पैरवी कर सकेंगे और न्याय की उम्मीद रखेंगे।

करनाल में मजार तोड़ने पर हंगामा विरोध करने पहुंचे लोगों से हाथापाई

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। हरियाणा के करनाल में मंगलवार दोपहर मजार तोड़े जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोगों ने हथौड़े चलाकर मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजार की देखरेख करने वाले लोगों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि मजार के आसपास रात के समय चिल्लाने और किलकारियों जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। इसी को लेकर उन्होंने वहां कार्रवाई की। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मजार की देखरेख करने वाले पक्ष ने घटना का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मौके पर विवाद बढ़ने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। वायरल वीडियो और मौके पर हुई घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच के बाद ही विवाद से जुड़े तथ्यों और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी। वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद ही मजार तोड़े जाने की जिम्मेदारी और अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

न्यूज ब्रीफ

भिवानी के बहल में नाले में लगी आग, चारों तरफ छाया काला धुआं

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे बहल गांव के नाले में अचानक आग भड़कने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। नाले के आसपास खड़े पेड़ और बिजली के तार भी आग की चपेट में आकर जल गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले इसी जगह के पास केमिकल से भरा टैंकर पलट गया था। टैंकर से निकला केमिकल नाले में जमा था। आशंका है कि उसी केमिकल के कारण आग भड़की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिरसा में पेड़ कटाई का मामला गरमाया, सरपंच और प्रतिनिधि पर मामला दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। सिरसा के मांगेआना गांव में 75 हरे पेड़ काटने के आरोप में पुलिस ने महिला सरपंच सुदेश रानी और सरपंच प्रतिनिधि दयानंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डबवाली सदर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई डीएसपी कालांवाली की जांच रिपोर्ट के आधार पर की। आरोप है कि पेड़ों की कटाई से करीब 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ। मामले की शिकायत मिलने के बाद डीएसपी स्तर पर जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ और मामले की जांच आगे जारी है।

करनाल में चोरों ने घर को बनाया निशाना, मेन गेट और अलमारी के ताले तोड़े

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। करनाल शहर की मंगल कॉलोनी पार्ट-2 में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। परिवार के सदस्य दोपहर के समय काम से बाहर गए हुए थे। करीब 1:35 बजे जब वे वापस घर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर कमरे में रखी लोहे की अलमारी के ताले भी टूटे थे और सामान व कपड़े बिखरे पड़े थे। परिवार ने जांच की तो अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब मिली। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

मंदिर में रात को घुसा चोर, गुल्लक तोड़ी और 3 लाख रुपए लेकर हुआ फरार

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर की सरोजनी कॉलोनी स्थित भगवान हनुमान मंदिर में रात के समय चोरी की वारदात हुई। चेहरा ढककर आया अज्ञात चोर मंदिर के अंदर घुसा और गुल्लक तोड़कर करीब 3 लाख रुपये चोरी कर ले गया। यह रकम गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए जमा की गई थी। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मनीषा हत्याकांड में नया मोड़, यूट्यूबर ने आत्मा से बात करने का किया दावा

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी



शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला किसी नई जांच रिपोर्ट के कारण नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। वीडियो में बंगाल के एक यूट्यूबर ने मनीषा की आत्मा से बात करने का दावा किया है। यूट्यूबर ने वीडियो में इस मामले को हत्या बताते हुए चार लोगों पर आरोप लगाए हैं। हालांकि, ये सभी दावे यूट्यूबर के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

मामले को लेकर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने वायरल वीडियो में किए गए दावों का हवाला देते हुए यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस से पूरे मामले की जांच करने और वीडियो में किए गए दावों की सत्यता की पड़ताल करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि 11 अगस्त 2025 को ढाणी लक्ष्मण गांव की प्ले-वे स्कूल शिक्षिका मनीषा लापता हो गई थीं। इसके दो दिन बाद 13 अगस्त को उनका शव सिंघानी में नहर के किनारे मिला था। मनीषा की मौत के बाद स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की थी।

परिवार की मांग और मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का तीन बार पोस्टमार्टम कराया गया। सबसे पहले नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद पीजीआइ रोहतक और अंत में दिल्ली एम्स में भी पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में स्वजन की मांग पर मुख्यमंत्री ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने एक साल से अधिक समय तक मामले की जांच की। जांच पूरी करने के बाद एजेंसी की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मनीषा की मौत को आत्महत्या बताया गया।

अब करीब दो दिन से बंगाल के एक यूट्यूबर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में वह मनीषा की आत्मा से बातचीत करने का दावा करते हुए मौत को हत्या बता रहा है। वीडियो में किए गए आरोपों को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायत भी दी गई है। ऐसे में यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पुलिस शिकायत के आधार पर वीडियो और उसमें किए गए दावों की जांच कर सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से यूट्यूबर के दावों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय कबड्डी टीम की शानदार जीत एशियन गेम्स में हिसार की बेटियों का जलवा

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार



- हॉकी और कबड्डी में हिसार की बेटियों का शानदार प्रदर्शन

एशियन गेम्स में हिसार के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम में हिसार की दीपिका सहरावत ने अपने दमदार खेल से खास पहचान बनाई है। वहीं भारतीय कबड्डी टीम में हिसार की मनीषा ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से उनके गांव और शहर में खुशी का माहौल है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी दीपिका सहरावत ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले आठ गोल दागे।

भारतीय टीम ने यह मुकाबला 19-0 के बड़े अंतर से अपने नाम किया। दीपिका के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद इंडोनेशिया के खिलाफ मुकाबले में भी दीपिका ने लगातार तीन गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। दीपिका अब टूर्नामेंट में कुल 11 गोल कर चुकी हैं और गोल करने वाले खिलाड़ियों में सबसे आगे चल रही हैं। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन से हिसार का नाम भी एशियन गेम्स में चर्चा में है। दीपिका के खेल को लेकर उनके क्षेत्र के लोगों में उत्साह है और उनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

दूसरी ओर भारतीय कबड्डी टीम ने भी सोमवार को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 42-21 से हराया। इस मैच में हिसार के गांव भिवानी रोहिल्ला की मनीषा ने भारतीय टीम के लिए लेफ्ट कवर की भूमिका निभाई। उन्होंने डिफेंस में जिम्मेदारी संभालते हुए टीम के प्रदर्शन में योगदान दिया। हिसार की ही हसनगढ़ निवासी निकिता नैन भी भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा हैं। इस तरह एशियन गेम्स में हिसार से जुड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी और प्रदर्शन क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बना हुआ है। हॉकी और कबड्डी में हिसार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद स्थानीय स्तर पर उनके परिवारों और ग्रामीणों में खुशी है। दीपिका के 11 गोल और मनीषा की डिफेंस में भूमिका ने एशियन गेम्स में हिसार की खेल प्रतिभा को एक बार फिर सामने रखा है। हिसार के खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिला है।

दीपिका सहरावत के लगातार गोल और मनीषा के मजबूत डिफेंस ने भारतीय टीमों की जीत में अहम योगदान दिया। खिलाड़ियों के परिवार और ग्रामीण उनके प्रदर्शन से बेहद उत्साहित हैं। दीपिका के 11 गोल और मनीषा की लेफ्ट कवर में जिम्मेदारी ने एशियन गेम्स में हिसार की पहचान को और मजबूत किया है। वहीं निकिता नैन के भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा होने से भी क्षेत्र के लोगों में खुशी है। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों में हिसार के खिलाड़ी इसी तरह शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, कनेक्टिंग यात्रियों को मिलेगा 24 घंटे एस्कॉर्ट

दस्तावेजों के मैनुअल मिलान में सामने आई चूक, मंत्रालय ने जारी किए नए सुरक्षा निर्देश

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में सामने आई गंभीर चूक के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उड़ानों से दिल्ली पहुंचकर आगे अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार दिल्ली को हब बनाकर घरेलू उड़ान से आने वाले और आगे अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को 24 घंटे तैनात नोडल टीमें फिजिकल एस्कॉर्ट करेंगी।

ये टीमें यात्रियों को निर्धारित रास्ते से इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचाएंगी। इसके साथ ही इमिग्रेशन और ट्रांसफर कॉरिडोर में भी जांच और निगरानी को मजबूत किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को गलती से ऐसे कॉरिडोर में जाने से रोकना है, जहां से वे जरूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना आगे की उड़ान तक पहुंच सकते



हैं। एयरपोर्ट पर संबंधित कर्मचारियों को भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना होगा।

नई गाइडलाइंस तीन सितंबर की मध्यरात्रि में सामने आई एक घटना के बाद जारी की गई हैं। अमृतसर से एअर इंडिया की उड़ान से दिल्ली पहुंचे इटली के तीन नागरिकों को ग्राउंड स्टाफ की गलती के कारण निर्धारित निकासी द्वार से बाहर निकालकर इमिग्रेशन क्लीयरेंस कराने के बजाय सीधे इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर कॉरिडोर में भेज दिया गया।

इसके बाद तीनों यात्री बिना पासपोर्ट और इमिग्रेशन क्लीयरेंस कराए ही म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा की उड़ान में सवार होकर विदेश रवाना हो गए। मामले का पता बाद में दस्तावेजों के मैनुअल मिलान के दौरान चला।

कनेक्टिंग यात्रियों की आवाजाही पर रहेगी निगरानी

मामले की जानकारी सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं गृह मंत्रालय ने शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के साथ आपात बैठक कर घटना की समीक्षा की। जांच में सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में हुई लापरवाही को गंभीरता से लिया गया। नई व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट पर घरेलू से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाही पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। नोडल टीमें यात्रियों को निर्धारित मार्ग से इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों को तय प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इमिग्रेशन और ट्रांसफर कॉरिडोर में जांच बढ़ाने के साथ यात्रियों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

लक्ष्मी नगर में 50 करोड़ की महाठगी

200 महिलाओं का सोना लेकर ज्वेलर दुकान-संपत्ति बेचकर फरार

एजेंसी, नई दिल्ली



लक्ष्मी नगर के जे एक्सटेंशन इलाके में पुराने सोने के बदले नया जेवर देने और उस पर मेकिंग चार्ज नहीं लेने का झांसा देकर गफ्फार ज्वेलर पर करीब 200 महिलाओं समेत अन्य लोगों से 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि ज्वेलर ने ग्राहकों को आकर्षक योजना बताकर उनसे पुराने सोने के आभूषण और रकम जमा कराई। ग्राहकों को भरोसा दिया गया कि तय समय के बाद उनके पुराने सोने के बदले नए आभूषण दिए जाएंगे।

काफी समय बीतने के बाद जब ग्राहक अपने जेवर लेने दुकान पहुंचे तो वहां ज्वेलर नहीं मिला। दुकान बंद होने की जानकारी मिलने के बाद पीड़ितों में रोष फैल गया। बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर जमा हुए और अपने सोने की वापसी की मांग की। बताया जा रहा है कि करीब 200 महिलाओं समेत अन्य लोगों ने इस योजना के तहत अपना सोना ज्वेलर के पास जमा कराया था। आरोप है कि ज्वेलर दुकान और संपत्ति बेचकर फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू की गई है।

ठगी की रकम और सोने की सही मात्रा का पता लगाने के लिए दस्तावेज और लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपे जाने की तैयारी है। पुलिस ज्वेलर की तलाश के साथ पीड़ितों से मिली शिकायतों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगालकर ठगी की कुल रकम और जमा कराए गए सोने की वास्तविक मात्रा का आकलन किया जाएगा।

सोना और नकदी लेकर फरार ज्वेलर, खातों की जांच शुरू

जांच में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित ज्वेलर ने ग्राहकों से कितना सोना और नकदी जमा कराई थी। इसके अलावा दुकान के कर्मचारियों, लेनदेन से जुड़े लोगों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा सकती है। पुलिस को आशंका है कि ठगी की रकम और सोने की मात्रा शिकायतों की संख्या बढ़ने के साथ और अधिक सामने आ सकती है। अधिकारियों ने पीड़ितों से अपील की है कि जिन लोगों ने योजना के तहत अपना पुराना सोना या रकम जमा कराई थी, वे संबंधित दस्तावेज और भुगतान की जानकारी जांच टीम को उपलब्ध कराएं। इससे मामले की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पुलिस दुकान से जुड़े बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ठगी की वास्तविक रकम और पीड़ितों की संख्या स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस टीम दुकान और आरोपित ज्वेलर से जुड़े अन्य ठिकानों की भी जानकारी जुटा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान करने के बाद पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। पुलिस यह भी देख रही है कि ग्राहकों से लिया गया सोना किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान को तो नहीं सौंपा गया। इसके लिए लेनदेन की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। वहीं, पीड़ितों की ओर से लगातार शिकायतें सामने आने पर पुलिस उनकी जानकारी दर्ज कर रही है। आरोपित की तलाश के साथ उसकी संपत्ति और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

आरोग्य मंदिर की जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने पहुंचे पूर्व विधायक चंदेला

एजेंसी, नई दिल्ली

- बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पूर्व विधायक दयानंद चंदेला ने उतारे कपड़े



ख्याला के एनडब्ल्यू चौक स्थित चौपाल की जमीन पर प्रस्तावित आरोग्य मंदिर के निर्माण के लिए सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और पुलिस की संयुक्त टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के पूर्व विधायक दयानंद चंदेला भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया।

विरोध के दौरान उन्होंने अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया, जिससे मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। डूसिब की टीम पुलिस बल के साथ चौपाल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी। अधिकारियों के अनुसार, इस जमीन पर स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत आरोग्य मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जमीन को खाली कराया जाना है। टीम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की, स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया। पूर्व विधायक के मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। दयानंद चंदेला ने कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को हटाने से पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने विरोध के तौर पर अपने कपड़े उतार दिए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। काफी देर तक चले विरोध के कारण कार्रवाई प्रभावित हुई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि आरोग्य मंदिर के निर्माण के लिए निर्धारित जमीन को खाली कराना जरूरी है। आरोग्य मंदिर के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

कालकाजी गैंगरेप केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के बाद आरोपित गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी आसिफ को मंगलवार रात पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आसिफ घायल हुआ और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि मामले में शामिल आसिफ अमर कॉलोनी स्थित डीएम ऑफिस रोड के आसपास मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस टीम पर तीन गोलियां चलाईं। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से ही आरोपितों की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपितों के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। इसी कार्रवाई में मामले से जुड़े दो अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब तीनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। जांच में घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपितों की भूमिका को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।

- आस्था कुंज पार्क मामले में पुलिस कार्रवाई, तीनों आरोपित गिरफ्तार किए गए

दिल्ली से पटना जाने वालों की बढ़ी परेशानी एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें सात दिन रद्द

एजेंसी, नई दिल्ली

- त्योहारों से पहले दिल्ली-पटना हवाई सेवा प्रभावित, सात दिनों तक उड़ानें रद्द
- उड़ानें रद्द होने से दिल्ली-पटना रूट पर बढ़ सकता है हवाई किराया



दिल्ली और पटना के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली-पटना-दिल्ली रूट पर संचालित अपनी दो उड़ानों को सात दिनों के लिए रद्द करने का फैसला किया है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक संचालित नहीं होंगी। एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द करने के पीछे परिचालन कारणों का हवाला दिया है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की दोनों उड़ानें एक सप्ताह तक रद्द रहने के कारण इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि एयरलाइंस की ओर से पटना एयरपोर्ट अथारिटी को उड़ानों के रद्द होने की जानकारी दे दी गई है। हालांकि, कंपनी ने परिचालन संबंधी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। उड़ानों के रद्द होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो सकती है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान, यात्रा की तारीख में बदलाव या रिफंड को लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यात्रियों को एयरलाइंस से संपर्क कर अपनी बुकिंग की स्थिति और आगे की यात्रा के विकल्पों की जानकारी लेनी पड़ सकती है।

दिल्ली-पटना रूट पर सात दिनों तक दो उड़ानों के उपलब्ध नहीं रहने का असर अन्य उड़ानों पर भी पड़ सकता है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से उपलब्ध सीटों की मांग बढ़ सकती है। इससे हवाई किराए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। खासकर त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले यात्रियों के लिए सीट मिलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से उड़ानों को रद्द करने के लिए फिलहाल सिर्फ परिचालन कारणों का उल्लेख किया गया है। किसी विशेष तकनीकी समस्या या अन्य कारण की जानकारी नहीं दी गई है।

नकली नोटों के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़

दिल्ली से बिहार, झारखंड और बंगाल तक फैला था नकली नोटों का नेटवर्क

एजेंसी, नई दिल्ली



गांधी नगर पुलिस ने नकली नोटों के अंतरराज्यीय नेटवर्क का किया पर्दाफाश।

गांधी नगर थाना पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों को दिल्ली और बिहार के बोधगया से पकड़ा। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 35 वर्षीय मोहम्मद दानिश निवासी गया, बिहार और 36 वर्षीय मोहम्मद मेराज उर्फ गुड्डू निवासी चतरा, झारखंड के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे और जांच के दौरान 500 रुपये के 187 नकली नोट बरामद किए हैं। बरामद नकली नोटों की कुल कीमत 93,500 रुपये बताई गई है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि नकली नोटों का नेटवर्क दिल्ली से बिहार, झारखंड और मालदा, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। मामले की जांच उस समय शुरू हुई, जब 22 अगस्त को गांधी नगर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की महिला कॉलोनी शाखा में एक ग्राहक नफीस अहमद ने 90 हजार रुपये जमा कराए। बैंक में रकम की जांच के दौरान 500 रुपये के 18 नकली नोट मिले। इसके बाद पुलिस ने नोटों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ में नफीस अहमद ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को दानिश नामक व्यक्ति ने उसकी दुकान से करीब 17,200 रुपये के कपड़े खरीदे थे। भुगतान के दौरान उसने नकद रुपये दिए थे। बाद में इन्हीं रुपयों में नकली नोट मिलने पर पुलिस ने दानिश के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को नकली नोटों के एक बड़े नेटवर्क के बारे में सुराग मिले।

नकली नोटों के लेनदेन की जांच जारी

जांच के दौरान पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई और आरोपितों की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दानिश और मेराज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में नकली नोटों की सप्लाई और उन्हें बाजार में चलाने से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही नकली नोटों के स्रोत और अब तक किए गए लेनदेन की भी जांच की जा रही है। पुलिस नकली नोटों के स्रोत और नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपितों का पता लगा रही है।

आईआरसीटीसी पर नया नियम, चार सेकेंड में फॉर्म भरा तो आईडी ब्लॉक

एजेंसी, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेलवे टिकटों की मांग बढ़ गई है। इसी के साथ टिकट दलालों की सक्रियता पर अंकुश लगाने के लिए आईआरसीटीसी ने अपनी निगरानी व्यवस्था को सख्त किया है। रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके तहत चार सेकेंड से कम समय में बुकिंग फॉर्म सबमिट करने वाली यूजर आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य तेजी से टिकट बुक करने वाले संदिग्ध खातों की पहचान करना है। आईआरसीटीसी के अनुसार, पिछले एक वर्ष में 9.34 करोड़ यूजर आईडी को निलंबित या निरस्त किया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि एआई प्रणाली की मदद से टिकट बुकिंग में होने वाली अनियमित गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों का दुस्साहस, महिला से दिनदहाड़े छीना आईफोन

एजेंसी, नई दिल्ली



ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला से आईफोन लूटने का मामला सामने आया है। चेरी काउंटी सोसायटी के पास ई-रिक्शा का भुगतान करने के दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश महिला के हाथ से आईफोन छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, महिला चेरी काउंटी सोसायटी के पास ई-रिक्शा से पहुंची थी।

वह ई-रिक्शा का भुगतान कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक उसके पास पहुंचे। बदमाशों ने महिला से आईफोन के बारे में सवाल किया। बताया गया है कि उन्होंने पूछा कि क्या यह आईफोन 18 प्रो है। महिला के हां में जवाब देते ही बदमाशों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और बाइक से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से महिला घबरा गई। दिनदहाड़े हुई मोबाइल लूट की वारदात से आसपास के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई। महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। बिसरख कोतवाली पुलिस बदमाशों तक पहुंचने के लिए आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश कौन थे और किस दिशा में फरार हुए। घटना के संबंध में पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा सकती है।

चेरी काउंटी सोसायटी के पास हुई इस वारदात ने मोबाइल लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाइक सवार दोनों अज्ञात बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है, ताकि बदमाशों की पहचान और उनके फरार होने की दिशा का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

72 से ज्यादा एफआईआर वाले गैंगस्टर पर शिकंजा, मकान ध्वस्त करने की तैयारी

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम में कुख्यात अपराधी कौशल चौधरी के खिलाफ प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नाहरपुर रूपा स्थित उसके मकान को मंगलवार दोपहर कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

कौशल चौधरी पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और अवैध हथियारों से जुड़े 72 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ छह दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज हैं। इन्हीं मामलों के बीच प्रशासन ने अब उसके नाहरपुर रूपा स्थित मकान के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। बताया गया है कि मकान को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराया जाएगा।

कार्रवाई से पहले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह



की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासन की टीम कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है। कुछ ही देर में मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। नाहरपुर रूपा में पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की नजर इस कार्रवाई पर बनी हुई है।

मकान ध्वस्तीकरण से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा

कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहेगी। अधिकारियों के अनुसार मकान गिराने की प्रक्रिया तय नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैयार रखा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कार्रवाई के दौरान मौके से दूरी बनाए रखने की अपील की है।

विकास सड़क ढांचे के साथ नालियों और ड्रेनेज लाइनों को मुख्य नेटवर्क से जोड़ा जाएगा

बुराड़ी में 125 करोड़ का प्रोजेक्ट, सड़क-ड्रेनेज नेटवर्क होगा अपग्रेड

एजेंसी, नई दिल्ली



पीडब्ल्यूडी विभाग बुराड़ी की सड़कों और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू करेगा। इस परियोजना पर करीब 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या को दूर करना है।

परियोजना के तहत बुराड़ी क्षेत्र में करीब 7.1 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 9.3 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। बारिश के दौरान बुराड़ी के कई हिस्सों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित होने के साथ वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। नए ड्रेनेज नेटवर्क के तैयार होने के बाद बारिश के पानी की निकासी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत सड़क ढांचे को मजबूत करने के साथ जरूरी स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी का उद्देश्य ऐसा नेटवर्क तैयार करना है, जिससे सड़क पर यातायात सुचारु रहे और बारिश के दौरान पानी की निकासी तेजी से हो सके। सड़क और ड्रेनेज दोनों कार्यों को एक साथ विकसित किए जाने से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा। बुराड़ी की आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए बेहतर सड़क संपर्क की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। प्रमुख मार्गों के सुधरने से आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

बुराड़ी में सड़क-ड्रेनेज नेटवर्क से जलभराव होगा दूर

परियोजना के तहत सड़क निर्माण और ड्रेनेज व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख मार्गों के साथ उन स्थानों को भी चिन्हित किया जाएगा, जहां बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या अधिक रहती है। जल निकासी की क्षमता बढ़ाने के साथ नालियों और ड्रेनेज लाइनों को मुख्य नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इससे बारिश के पानी को तेजी से निकालने में मदद मिलेगी। सड़क नेटवर्क के सुधार से बुराड़ी और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। परियोजना में सड़क की गुणवत्ता और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी हिस्सों का विकास किया जाएगा। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों के साथ स्थानीय कारोबारियों और वाहन चालकों को भी सुविधा मिल सकती है। पीडब्ल्यूडी की योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बारिश के दौरान यातायात बाधित होने की स्थिति को कम करना है। सड़क और ड्रेनेज कार्य पूरा होने के बाद बुराड़ी में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

न्यूज ब्रीफ

कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू, आखिरी समय में फड़फड़ा रहे कांग्रेसी: भाजपा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बयानों पर सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष जसवंत ठाकुर और बमसन टौणीदेवी मंडल अध्यक्ष प्रो. विक्रम राणा ने तीखा पलटवार किया है। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का हाल उस मरीज जैसा हो गया है जिसका आखिरी समय आ गया हो और डॉक्टर परिजनों से कह रहे हों कि अब सेवा ही कर लो। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विदाई तय है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिन घटते जा रहे हैं और ऐशो-आराम की कुर्सी छूटती दिख रही है तो दर्द होना स्वाभाविक है। इसी बौखलाहट में कांग्रेसी मित्र मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष को बेचैनी क्यों हो रही है? क्या पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करना गैर-कानूनी हो गया है? कांग्रेस ने तो पंचायती राज को कमजोर और चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम किया है, जबकि भाजपा पंचायतों को सशक्त करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने हमीरपुर के स्वाभिमान के लिए सत्ता को ठोकर मारी थी, सत्ता के लिए स्वाभिमान नहीं बेचा। जिन्हें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने की राजनीति के लिए जाना जाता है, वे आज विभीषण का उदाहरण देकर खुद ही विरोधाभास के शिकार हो रहे हैं। अगर अन्याय और अधर्म का साथ छोड़ना विभीषण होना है तो विभीषण ही सही, लेकिन स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा देने वाली राजनीति स्वीकार नहीं। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियां देकर सत्ता हासिल की और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाकर कांग्रेस के ही नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को हाशिए पर धकेला। बौखलाहट का कारण यही है कि अब जनता रोजगार, सड़क, परिवहन और स्थानीय विकास पर सवाल पूछ रही है। भाजपा मंडल अध्यक्षों ने कांग्रेस नेताओं को 26 सितंबर को टौणीदेवी के अस्पताल चौक पर सुबह 10 बजे होने वाले धरना-प्रदर्शन में आने का खुला न्योता दिया है। कहा कि अगर दावा है कि सुजानपुर का विकास नहीं रोका तो जनता के बीच आकर बताएं कि उटपुर आईटीआई का काम क्यों लटका है, सड़कें क्यों बदहाल हैं और 40 बस रूट क्यों बंद हैं।

पीएमजेजेबीवाई के तहत महिला को दिया बीमा लाभ



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत एक महिला खाताधारक को दो लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि यह केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कम प्रीमियम पर आम नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत पात्र खाताधारक की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र बचत खाता धारक इस योजना में नामांकन कर सकते हैं तथा इसका नवीनीकरण 55 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। यूनियन बैंक की ओर से ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और बीमा सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बैंक अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे पीएमजेजेबीवाई सहित अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पात्रता के अनुसार इनका लाभ उठाएं।

बाल विज्ञान कांग्रेस में हिम अकादमी का दबदबा



भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में आयोजित उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 का समापन हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने विज्ञान और गणित से जुड़ी प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हिम अकादमी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कई वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतियोगिता में साइंस क्विज, साइंस एक्टिविटी कॉर्नर, साइंस मॉडल और मैथ ओलंपियाड आयोजित किए गए। मैथ ओलंपियाड के सीनियर सेकेंडरी वर्ग में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर के अनिकेत कौंडल ने प्रथम स्थान हासिल किया। साइंस क्विज के सीनियर सेकेंडरी वर्ग में इसी स्कूल के चिन्मय शर्मा और विशेष डटवाल प्रथम रहे। साइंस एक्टिविटी कॉर्नर के जूनियर वर्ग में हिम अकादमी विकासनगर के अभिजय डोगरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती और प्रधानाचार्य दीप्ति राणा ने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता की सराहना की। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित करते हैं।

बिलासपुर में मारपीट व तोड़फोड़ के तीन मामले

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और अवैध शराब तस्करी के चार मामलों में कार्रवाई की है। सदर थाना में एक महिला ने दिलावर खान और आशिन खान पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य मामले में अमीन ने जमीन विवाद को लेकर सरोज और उसके बेटे सलमान पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं सुरेश कुमार की शिकायत पर देव राज और प्यार चंद के खिलाफ जेसीबी से महेश टी स्टॉल तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है। इधर, थाना स्वारघाट और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गरा बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान पिकअप से 150 पेटी यानी 1800 बोतल टुबोर्ग बीयर बरामद की। चालक सिमरनजीत सिंह वैध परमिट या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

सुक्खू सरकार ने कांगड़ा में रोके विकास के सारे काम : जयराम

बोले- कांगड़ा में पूर्व सरकार की योजनाएं बंद, संस्थानों पर लटके ताले

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को बैजनाथ में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला सुक्खू सरकार में पूरी तरह बदहाल है। नए काम तो छोड़िए, पूर्व सरकार के समय के जो काम थे, उन्हें भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनका बजट रोक दिया गया या डायवर्ट कर दिया गया। जो सड़कें टूटी हुई थीं, वे आज भी टूटी हुई हैं। जो काम जहां था, वहीं ठहरा हुआ है। कांगड़ा के लिए पूर्व सरकार में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थीं, वे बंद हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में बैजनाथ में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, जिसकी भी मांग की गई, सब कुछ मिला। लेकिन तालाबंदी में माहिर मुख्यमंत्री ने सत्ता में आते ही ज्यादातर संस्थानों को डीनोटिफाई कर दिया। आईटीआई सकड़ी का भवन बनकर तैयार है, लेकिन ताला अभी तक लगा है। छोटा भंगाल में मिनी सचिवालय बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर भी ताला लटका हुआ है। बस अड्डे का काम रोका गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला बंद होने के कगार पर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में जहां देखो, वहां व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार की तालाबंदी नजर आती है। इसका कारण है कि यह सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना और तालाबंदी की नीयत के साथ ही आगे बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पंचायतीराज चुनावों में भाजपा को मिली यह जीत प्रदेशवासियों के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति विश्वास की जीत है।



विश्वविद्यालय के लिए राशि नहीं दे रही सरकार

जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पूर्व सरकार द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, बस प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए जमा करने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वह पैसे नहीं जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने लिए 50 करोड़ से हाई-फाई कार्यालय बनवा रहे हैं। जय राम ने कहा कि काम करने के लिए कार्यालय नहीं, सही नीयत और सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए। दुर्भाग्य से वह मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है। इस दौरान कांगड़ा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तथा सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री एवं विधायक सुधीर शर्मा, विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पार्टी प्रत्याशी रहे मुल्क राज प्रेमी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अनुराग ठाकुर ने पीएसी सदस्यों के साथ मध्य रेलवे मुख्यालय का किया निरीक्षण

◆ पीएसी सदस्यों ने लालबागचा राजा के किए दर्शन, की पूजा-अर्चना

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। सांसद व पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद की सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) के सदस्यों के साथ मुंबई में आधिकारिक अध्ययन दौरे के दौरान मध्य रेलवे मुख्यालय और ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) का निरीक्षण किया। अध्ययन दौरे का उद्देश्य रेलवे के आधुनिकीकरण, परिचालन दक्षता, बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करना रहा।



समिति के सदस्यों ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर मध्य रेलवे क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान रेलवे के परिचालन को अधिक प्रभावी बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। सीएसएमटी के निरीक्षण के दौरान समिति ने यात्री सुविधाओं, अधिक यात्री दबाव के प्रबंधन और स्टेशन परिसर में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सीएसएमटी की ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विरासत के संरक्षण से संबंधित पहलुओं की भी समीक्षा की गई।

आधिकारिक निरीक्षण और प्रशासनिक समीक्षा के बाद अनुराग ठाकुर सहित समिति के सदस्यों ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में पहुंचकर दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। समिति के सदस्यों ने यहां आशीर्वाद प्राप्त किया। यह अध्ययन दौरा संसदीय दायित्वों के निर्वहन के साथ रेलवे की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर रहा। दौरे के दौरान रेलवे की आधारभूत संरचना, यात्री सुविधाओं और आधुनिकीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का अवलोकन किया गया।

मोबाइल का उपयोग मनोरंजन नहीं ज्ञान बढ़ाने के लिए करें : धर्माणी



भारतेन्दु संवाददाता, भराड़ी। तकनीकी शिक्षा, नगर व ग्राम नियोजन, आवास, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए केवल डिग्री और किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आत्म-विकास, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान देना चाहिए। वह पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में आयोजित विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे।

संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने मंत्री से उनके संघर्ष, रुचियों, जीवन अनुभवों और घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े सवाल पूछे। धर्माणी ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बदाघाट में 132 केवी तथा बम्म और घुमारवीं में 33-33 केवी के सब-स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिकंडक्टरिंग और ट्रांसफार्मरों के उन्नयन का काम भी जारी है। धर्माणी ने विद्यार्थियों से मोबाइल फोन का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न कर ज्ञान और सीखने के साधन के रूप में करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग तथा खेलकूद को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने और चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए प्रेरित किया।

स्वारघाट कोर्ट की पहली मंजिल से कूदा आरोपी, बस स्टैंड से दबोचा

भारतेन्दु संवाददाता, स्वारघाट। स्थानीय न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर पहली मंजिल से छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही दूरी पर स्थित बस स्टैंड परिसर से आरोपी को दोबारा पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार थाना स्वारघाट में दर्ज प्राथमिकी संख्या 73/26 के तहत नामजद आरोपी को पुलिस पेशी के लिए अदालत लेकर पहुंची थी। पेशी से पहले आरोपी ने उल्टी आने का बहाना बनाया और मुंह में हाथ डाल लिया। पुलिसकर्मी उसे वॉशरूम की ओर ले जा रहे थे, तभी उसने अदालत भवन की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा कर आरोपी को बस स्टैंड से हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर ड्यूटी में तैनात कर्मियों की लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एनआईटी हमीरपुर में जीएसटी सुधारों, कर साक्षरता, वित्तीय जागरूकता, नवाचार और उद्यमिता के विषय पर दी जानकारी



अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के प्रबंधन अध्ययन विभाग ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के सहयोग से दो सप्ताह के राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रोथ-2026 जीएसटी 2.0 नीति, समुदायों और क्षेत्रों को जोड़ना का सफलतापूर्वक समापन किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन विशेषज्ञ व्याख्यानों का आयोजन किया गया, जिसमें एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी तथा विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने सहभागिता की। इसके पश्चात दूसरे सप्ताह में ऑफलाइन क्षेत्रीय सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षाविद्, सरकारी अधिकारी तथा स्थानीय समुदाय शामिल हुए ऑफलाइन क्षेत्रीय सहभागिता श्रृंखला के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय एनआईटी हमीरपुर के उद्यमिता प्रकोष्ठ, एनआईटी हमीरपुर में अकादमिक सरकार पैनल, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर, ग्राम पनियाला तथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में विशेषज्ञ व्याख्यान, पैनल चर्चा, बिजनेस मॉडल कैनवास, पोस्टर निर्माण, अपशिष्ट से रचनात्मकता गतिविधियां, उद्यमिता संबंधी गतिविधियां तथा सामुदायिक सहभागिता शामिल रही। इन गतिविधियों के माध्यम से जीएसटी सुधारों, कर साक्षरता, वित्तीय जागरूकता, नवाचार, उद्यमिता तथा जिम्मेदार नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी एवं व्यावहारिक समझ प्रदान की गई। विशेषज्ञ ज्ञान, अनुभवात्मक अधिगम तथा सामुदायिक सहभागिता के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को जीएसटी के बदलते परिदृश्य की व्यावहारिक समझ प्रदान की तथा जागरूक सहभागिता, उद्यमशील सोच, नवाचार और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। इस पहल ने नीति, अकादमिक जगत, सरकारी संस्थानों, विद्यार्थियों तथा स्थानीय समुदायों के बीच प्रभावी समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एच. एम. सूर्यवंशी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. विवेक तिवारी तथा समन्वयक डॉ. शैम्पी कंबोज और डॉ. सुंदर कला नेगी रहे।

विधायक मलेंद्र राजन ने किया अंडर-19 मेजर गेम्स का शुभारंभ

खिलाड़ियों को दिलाई नशामुक्ति की शपथ



भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंदौरा में अंडर-19 छात्र वर्ग की जिला स्तरीय मेजर गेम्स प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में जिले के 45 विद्यालयों के 690 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

विधायक मलेंद्र राजन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा टीम भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। उन्होंने अपनी विधायक निधि से 31 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। मलेंद्र राजन ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंदौरा को सीबीएसई का दर्जा मिलना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हिमाचली संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संदेशों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। आयोजन में प्रधानाचार्य राम कृष्ण शर्मा, एसडीएम सुरिंदर ठाकुर, डीएसपी संजीव यादव सहित शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और शिक्षकों में उत्साह देखने को मिला।

खोली पंचायत में लावारिस हालत में मिला नवजात, उपचार के दौरान मौत



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। ग्राम पंचायत खोली के वार्ड नंबर सात में नवजात शिशु के लावारिस हालत में मिलने का मामला सामने आया है। जन्म के बाद नवजात को कथित तौर पर सुनसान स्थान पर छोड़ दिया गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पंचायत प्रधान कुलवंत चौधरी ने पुलिस को जानकारी दी।

प्रधान ने बताया कि उन्हें शाम करीब साढ़े चार बजे एक ग्रामीण का फोन आया था। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस थाना कांगड़ा को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नवजात को अपने कब्जे में लिया और तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई। इसके बाद बच्चे को उपचार और स्वास्थ्य जांच के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा भेजा गया। हालांकि, उपचार के दौरान नवजात की मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवजात को किसने जन्म दिया और उसे किन परिस्थितियों में वहां छोड़ा गया, इसका पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटा रही है। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के साथ घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े वास्तविक तथ्यों का पता चल सकेगा।

हिमाचल में दो आईएएस बदले, अनुराग चंद्र शर्मा होंगे एचपीटीडीसी के एमडी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा को धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वहीं, निगम के मौजूदा प्रबंध निदेशक डॉ. राजीव कुमार को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अधिसूचना के मुताबिक अनुराग चंद्र शर्मा वर्तमान में नई तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्हें धर्मशाला स्थित एचपीटीडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुराग चंद्र शर्मा इससे पहले कुल्लू के उपायुक्त के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. राजीव कुमार अब कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे।

एमसीए द्वितीय सेमेस्टर में एमसीएम डीएवी कांगड़ा का 100 प्रतिशत परिणाम



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से घोषित एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। महाविद्यालय की मेरिट सूची में भी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया।

मेरिट सूची में निशांत ने 85.57 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। गुरजीत 84.57 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं ताशी परवान और बिक्कु ठाकुर ने 81.71 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने सभी सफल और मेधावी विद्यार्थियों को बधाई दी।

उन्होंने विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्राध्यापकों को भी इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रबंधन ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

पैदावार नेरी के हर्बल गार्डन में तैयार हो रही काली हल्दी, मध्य प्रदेश से लाया ट्रायल बीज पर हुई सफल पैदावार

हिमाचल काली हल्दी की पैदावार में बनेगा देश का पांचवां राज्य

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश काली हल्दी की पैदावार करने वाला देश का पांचवां राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हमीरपुर के नेरी स्थित हर्बल गार्डन में मध्य प्रदेश से लाए गए काली हल्दी के बीज का सफल परीक्षण किया गया है। पैदावार सफल होने के बाद अब इसके बीज को प्रमाणिकता के लिए देहरादून स्थित औषधीय पौधा बोर्ड को भेजा गया है। प्रमाणिकता मिलने के बाद प्रदेश में उत्पादित काली हल्दी को हिमाचली पहचान मिलने का रास्ता साफ होगा। जानकारी के अनुसार देश में वर्तमान में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में काली हल्दी की पैदावार की जाती है। हिमाचल में इसकी खेती को बढ़ावा मिलने से प्रदेश पांचवां उत्पादक राज्य बन सकता है। नेरी हर्बल गार्डन में एक सेमिनार के दौरान मध्य प्रदेश से काली हल्दी का बीज लाकर इसे उगाने का प्रयास किया गया था। अनुकूल परिस्थितियों में इसका उत्पादन सफल रहा है। काली हल्दी की बाजार कीमत सामान्य हल्दी की तुलना में काफी अधिक बताई जाती है। ऐसे में प्रदेश के किसानों के लिए इसकी खेती आय का अतिरिक्त साधन बन सकती है। हिमाचल में जंगली जानवरों और लावारिस पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान के कारण कई किसान खेती से दूरी बना रहे हैं। काली हल्दी जैसी वैकल्पिक फसल किसानों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि, इसकी खेती और विपणन को लेकर किसानों को प्रशिक्षण और उचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाना भी जरूरी होगा।



औषधीय उपयोग के कारण बढ़ रही मांग

काली हल्दी का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में जड़ी-बूटी के रूप में किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले करक्यूमिन सहित विभिन्न तत्वों के कारण इसके औषधीय गुणों पर अध्ययन किए गए हैं। इसका इस्तेमाल पाचन संबंधी समस्याओं, सूजन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी उपयोगों के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। हालांकि, गंभीर बीमारियों के उपचार के दावों को चिकित्सकीय प्रमाण के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। काली हल्दी का इस्तेमाल पारंपरिक मान्यताओं और तंत्र संबंधी गतिविधियों में भी किए जाने की जानकारी सामने आती है। नेरी हर्बल गार्डन में इसकी सीमित उपलब्धता के कारण कुछ लोग इसकी मांग कर रहे हैं। फिलहाल गार्डन प्रबंधन का ध्यान उपलब्ध पौध सामग्री को बढ़ाने और इसकी पैदावार को विस्तार देने पर है।

किसानों को जागरूक करने की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में काली हल्दी की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने से पहले किसानों को इसकी उन्नत खेती, बीज संरक्षण, उत्पादन लागत और बाजार व्यवस्था की जानकारी देना जरूरी है। प्रमाणिकता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कृषि और बागवानी विभाग के स्तर पर इसके संभावित व्यावसायिक उत्पादन को लेकर आगे की योजना बनाई जा सकती है। नेरी हर्बल गार्डन के प्रभारी कमल भारद्वाज ने बताया कि काली हल्दी को अभी गार्डन में अपने स्तर पर उगाया गया है और इसकी पैदावार सफल रही है। सफल उत्पादन के बाद बीज को देहरादून स्थित औषधीय पौधा बोर्ड को प्रमाणिकता के लिए भेजा गया है। उनका कहना है कि प्रमाणिकता मिलने के बाद काली हल्दी के उत्पादन को और बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें : एसडीएम



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग ने उपमंडल के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में जमाबंदियों के अद्यतन, इंतकालों के सत्यापन, तहसील स्तर पर लंबित न्यायालय मामलों और फील्ड स्तर के लंबित कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और पांच अक्तूबर तक जमाबंदियों को अपडेट करने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि उचित कारण के बिना कोई राजस्व मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से मामलों का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। डॉ. अंजलि गर्ग ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन से जुड़ा है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगात्मक एवं शालीन होना चाहिए। लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में पटवारियों ने पटवारखानों में फर्नीचर, लैपटॉप सहित अन्य समस्याएं भी रखीं। एसडीएम ने समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अ

न्यूज ब्रीफ

सिद्ध गणपति मंदिर में प्रो. अनुपमा ने की पूजा-अर्चना

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। समाजसेवी प्रो. अनुपमा सिंह ने सिद्ध गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान गणपति से मंडी सहित पूरे हिमाचल प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सिद्ध गणपति बप्पा की कृपा मंडी की पावन धरती और यहां के प्रत्येक परिवार पर बनी रहे। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश की युवा शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि युवाओं में ज्ञान, साहस, अनुशासन, संस्कार और राष्ट्रसेवा की भावना और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि विकास के साथ अपनी सनातन संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से जुड़े रहना भी आवश्यक है। इस अवसर पर अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, प्रीति मल्होत्रा, डीएन सैनी, तारा शर्मा, पुष्पराज शर्मा, नंदन, एमएल शर्मा सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पंजाब भेजी जाने वाली बीयर की 150 पेटियां जब्त



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। अवैध शराब के प्रवेश और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य कर व आबकारी विभाग की बिलासपुर टीम ने गरामोड़ा में कार्रवाई करते हुए पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित टुबर्ग बीयर की 150 पेटियां जब्त की हैं। विभाग ने बीयर ले जा रहे वाहन को भी कब्जे में लिया है। डीसी राज्य कर व आबकारी हरिश छेत्री ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सात बजे गरामोड़ा के पास नाकाबंदी के दौरान वाहन संख्या एचपी 72 डी 6478 को जांच के लिए रोका गया। तलाशी में 150 पेटी बीयर बरामद हुई। पेटियों पर 'केवल पंजाब में बिक्री के लिए' अंकित था। वाहन में मौजूद व्यक्ति बीयर को हिमाचल लाने और परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। विभाग ने खेप और वाहन कब्जे में लेकर आबकारी कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम खेप के स्रोत और संभावित गंतव्य की भी जांच कर रही है। कार्रवाई में सहायक आयुक्त शम्मी कुमार, अधिकारी अतुल कौशल सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

पठानकोट में कर्मचारियों ने शोरूम-गोदाम से चुराया 11 लाख रुपए का सामान



भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी के कर्मचारियों द्वारा चोरी का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों ने कारोबारी के दूसरे शोरूम और गोदाम से करीब 11 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चोरी किया। इसके अलावा घर से कारोबारी की पैंट की जेब से 22 हजार रुपए नकद भी चुराए गए। कारोबारी राजेश कुमार की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर दो में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार नए मामले में अमित उर्फ मीता, अभिषेक उर्फ गबरू, सुनील कुमार और बलबीर चंद को नामजद किया गया है। अमित और अभिषेक पहले मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सुनील और बलबीर की तलाश जारी है। शिकायत के मुताबिक पांच जून को अमित और अभिषेक सामान लेने कारोबारी के घर पहुंचे थे और मौका पाकर जेब से नकदी निकाल ली। छह से 21 जून के बीच चार कर्मचारियों ने ढांगू रोड स्थित शोरूम और गुरु रविदास चौक के गोदाम से सामान चोरी किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवती से सामूहिक दुष्कर्म, चार युवकों पर केस

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में 18 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चार युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि युवती 20 सितंबर को निजी काम से मोहाली से पठानकोट लौट रही थी। घर जाते समय चार युवकों ने बाइक से उसे टक्कर मारकर गिराया और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपियों की पहचान विशाल, गगन, रणजीत और दक्ष के रूप में की है। बताया गया कि युवती ने इससे पहले गांव में परिवार के साथ हुई मारपीट की वीडियो बनाई थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पहले भी प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़िता का आरोप है कि वीडियो सामने आने के बाद आरोपी उससे नाराज थे। डीएसपी ग्रामीण सुखजिंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

आयुर्वेद अपनाने व नियमित सैर के लिए किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह की ओर से मंगलवार को 11वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में वॉकथॉन आयोजित किया गया। आयुर्वेद के प्रति जागरूकता और स्थानीय लोगों के साथ सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस पदयात्रा में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। करीब तीन किलोमीटर लंबी वॉकथॉन क्षेत्रीय परिसर से बीबीएमबी आवासीय कॉलोनी तक आयोजित की गई। इसमें संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नोबल स्कूल के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को आयुर्वेद अपनाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित पैदल चलने के फायदों के प्रति जागरूक किया। संस्थान प्रभारी डॉ. विनीता कुमारी नेगी ने कहा कि आयुर्वेद स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है। दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक सहभागिता और आपसी बंधुत्व की भावना भी मजबूत होती है।

राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अधिवेशन में जोशी सम्मानित



भारतेन्द्र संवाददाता, कुनिहार। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश के राज्य संयोजक आरपी जोशी को संगठन के प्रति सक्रिय योगदान और सहभागिता के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। सिकंदराबाद स्थित एमसीईएमई सभागार में आयोजित अधिवेशन के दौरान तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आरपी जोशी को सम्मान पदक और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। अधिवेशन का मुख्य विषय 'विकसित भारत 2047–पूर्व सैनिकों एवं राष्ट्रभक्त नागरिकों की भूमिका' रहा। इसमें देशभर से पूर्व सैनिकों और राष्ट्रभक्त नागरिकों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के राज्य संयोजक को मिला सम्मान संगठन के प्रति उनके योगदान और राष्ट्रसेवा से जुड़े कार्यों में सक्रिय सहभागिता को रेखांकित करता है। सम्मान प्राप्त करने के बाद आरपी जोशी ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत गौरव के साथ हिमाचल प्रदेश के सभी पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और राष्ट्रभक्त नागरिकों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी राष्ट्रहित और समाजसेवा से जुड़े कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देते रहेंगे।

स्लोगन राइटिंग में तमन्ना पटियाल रही प्रथम

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय घुमारवीं में विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जेंडर संबंधी विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर संदेश दिए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रीतम लाल ने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, स्वच्छता और लैंगिक समानता के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। उन्होंने युवाओं से स्वयं स्वस्थ आदतें अपनाने के साथ समाज में भी जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। पोस्टर मेकिंग में काजल ने प्रथम, जबकि नंदिनी और अंजलि ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान हासिल किया। स्लोगन राइटिंग में तमन्ना पटियाल प्रथम और काव्यांशी चंदेल द्वितीय रहीं। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह बरवाल भी मौजूद रहे।

सेना के लिए तैयार किया रडार व जैमर फ्री ड्रोन

बहुतकनीकी कॉलेज के छात्र सर्वेश शर्मा ने सेना की बहुत बड़ी समस्या का किया समाधान



अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती और प्रतिभाशाली बच्चे को कोई भी मुश्किल आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

हुनर सर चढ़कर बोलता है और यह सब कर दिखाया है बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस के छात्र सर्वेश ने। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्र की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसे हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर के सर्वेश शर्मा ने भारतीय थल सेना की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकालते हुए एक ऐसा ड्रोन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जोकि न तो दुश्मन के राडार की पकड़ में आएगा और न ही कोई भी जैमर इसे जाम कर पाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सर्वेश शर्मा के इस प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (डीआईओ) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस इक्सीलेंस (आईडैक्स) की ओर से 3.50 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सीईओ दिनेश माहौर ने सोमवार को ही इस बजट को स्वीकृति प्रदान की। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले सर्वेश शर्मा की इस उपलब्धि ने न केवल अपने परिवार एवं संस्थान को, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। दरअसल, सर्वेश ने आईआईटी जोधपुर और कोनार्क कोर के राष्ट्रीय स्तरीय ओपन कार्ड बोर्ड ड्रोन कंपीटिशन में भाग लिया था। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों की 50 टीमों ने भाग लिया था और अपने-अपने इनोवेटिव आइडिया रखे थे। इसी दौरान भारतीय सेना की बॉर्डर सर्विलांस से संबंधित समस्या पर भी चर्चा की गई थी। इस प्रतियोगिता में सर्वेश की टीम ने दस लाख रुपए का चौथा पुरस्कार हासिल किया था। यहीं से प्रेरित होकर सर्वेश ने भारतीय सेना की समस्या के समाधान के लिए ड्रोन तैयार करने पर काम आरंभ किया और इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली। इस प्रोजेक्ट पर 87 हजार रुपए खर्च हुए। इसके बाद सर्वेश ने डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (डीआईओ) और इनोवेशन फॉर डिफेंस इक्सीलेंस (आईडैक्स) के प्रोजेक्ट के तहत स्टार्टअप के लिए आवेदन किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। सर्वेश अब भारतीय सेना के लिए रुद्रा ऐज

◆अब सेना के लिए बनाएगा अत्याधुनिक ड्रोन, रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किए 3.50 करोड़

टी-1 (स्पेक्ट्रा) ड्रोन तैयार करेगा, जोकि सीमा पर निगरानी में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। क्योंकि, यह दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आएगा और जैमर भी इसे जाम नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए 20 दिन का समय दिया है और इसका इनक्यूबेशन सेंटर आईआईटी रुड़की में बनाया गया है। यानि सर्वेश अब आईआईटी रुड़की की लैब में इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा, जिसे 20 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस उपलब्धि पर बहुतकनीकी कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर, संस्थान के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष समीर भारती और अन्य शिक्षकों ने सर्वेश को बधाई देते हुए उसके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

आनी में भीषण सड़क हादसा चार लोगों की मौत, एक घायल



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा निगान-धारीपुर सड़क मार्ग पर सुबह करीब 3:30 बजे हुआ।

जानकारी के अनुसार पांच लोग एक गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रामपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार हादसे में राहुल राणा (25) पुत्र जगदीश चंद, बाल कृष्ण पुत्र ढीक राम, विकास उर्फ विक्की पुत्र हीरा सिंह तथा गुंजन पुत्र राम प्रकाश की मौत हुई है। चारों मृतक जाबो, डाकघर कराणा, तहसील आनी जिला कुल्लू के निवासी थे। वहीं, सुरेश कुमार (29) पुत्र मोहन लाल, निवासी जाबो, डाकघर कराणा तहसील आनी गंभीर रूप से घायल हुआ है। चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए रामपुर रेफर किया है। एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे पर विधायक लोकेंद्र कुमार ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है।

अंडर-19 बॉक्सिंग में अर्की स्कूल का दबदबा, जीती ट्रॉफी



भारतेन्दु संवाददात, अर्की। कुनिहार में आयोजित अंडर-19 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पीएम श्री एससीवीटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम की।

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता में विद्यालय के मानस, जतिन, चिराग और मोहित ने अपने-अपने मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं, रोहित व स्वारित ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक जीते। ध्रुव और दीक्षित ने भी बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किए। विद्यालय के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान आत्मविश्वास, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। उनके प्रदर्शन की बदौलत विद्यालय ने सर्वाधिक पदक हासिल कर प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर कब्जा किया। खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत को अपनी सफलता का आधार बताया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य हेम राज गौर ने सभी पदक विजेता विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण सराहनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि खेलों में भागीदारी से अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। विद्यालय की सफलता पर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों ने खुशी जताई।

17.77 ग्राम चिट्टे के साथ तीन गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को कुल 17.77 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीटी बिलासपुर, थाना भराड़ी और घुमारवीं पुलिस की टीमों ने नाकाबंदी और गश्त के दौरान यह कार्रवाई की। 21 सितंबर को गरा फोरलेन के पास बस की तलाशी में कुल्लू निवासी चंद्रवीर से 12.58 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं, 22 सितंबर को भराड़ी में बस की जांच के दौरान मंडी निवासी अभिषेक शर्मा से 2.59 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। तीसरी कार्रवाई 19 सितंबर को घुमारवीं में ट्रेजरी कार्यालय के पास हुई, जहां पुलिस ने स्थानीय निवासी ओम दत्त से 2.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब नशे की खेप के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा

6 अक्तूबर को नयना देवी मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छह अक्तूबर को बिलासपुर दौरा प्रस्तावित है। दौरे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है।

इसी कड़ी में बचत भवन में उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एम्स बिलासपुर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। डीसी ने कहा कि राष्ट्रपति का दौरा जिले के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति छह अक्तूबर को श्री नयना देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल होंगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रपति के प्रस्तावित मार्गों का बारीकी से निरीक्षण करने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। श्री नयना देवी मंदिर में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और विद्युत आपूर्ति समेत अन्य व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत योजना तैयार करने के साथ यातायात प्रबंधन, आवश्यक यातायात बदलाव, पार्किंग और विशिष्ट आवागमन को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दौरे के दौरान तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने को कहा गया।

बैठक में सुरक्षा, रूट निरीक्षण, यातायात, संचार, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति, पार्किंग और स्वच्छता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान, अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि एम्स बिलासपुर के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े।

दिव्यांश का राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन



◆जवाली ब्लॉक से राज्य स्तर तक पहुंचने वाला एकमात्र खिलाड़ी

भारतेन्दु संवाददाता, जवाली। तृप्ता पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चलवाड़ा के छात्र दिव्यांश ने कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हासिल किया है।

दिव्यांश पूरे जवाली क्षेत्र से राज्य स्तर के लिए चयनित होने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। उसकी इस उपलब्धि से विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। दिव्यांश ने राज्य स्तर तक पहुंचने के लिए जोनल और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले उसने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरा में आयोजित जोनल स्तरीय अंडर-14 प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल दिखाकर जिला स्तर के लिए स्थान बनाया। इसके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहरा में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उसने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शानदार प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ, अब दिव्यांश जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर-14 कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करेगा। राज्य स्तर पर चयन होने के बाद विद्यालय पहुंचने पर दिव्यांश का स्कूल प्रबंधन और सहपाठियों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। विद्यालय के चेयरमैन वीरेंद्र नरियाल और प्रधानाचार्य राकेश राणा ने दिव्यांश को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थी की मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने सफलता का श्रेय विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों रमेश कुमार और संदीप सिंह को भी दिया। उन्होंने कहा कि दोनों शिक्षकों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निरंतर मेहनत से दिव्यांश ने अपनी खेल प्रतिभा को निखारा और राज्य स्तर तक पहुंचने में सफलता हासिल की। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

धृति ने प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट अंग्रेजी परीक्षा की उत्तीर्ण



भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की पूर्व छात्रा व एनसीसी की पूर्व कैडेट धृति शर्मा ने प्रथम प्रयास में यूजीसी-नेट अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बिना किसी कोचिंग के स्व-अध्ययन से मिली इस उपलब्धि से महाविद्यालय, परिवार और एनसीसी समुदाय में खुशी है।

फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. चमन ने बताया कि धृति शर्मा ने नौकरी, स्नातकोत्तर की अंतिम परीक्षाओं, घरेलू जिम्मेदारियों और यूजीसी-नेट की तैयारी को एक साथ संभालते हुए प्रतिदिन करीब 10 से 13 घंटे अध्ययन किया। उस दौरान वह 1 हिमाचल प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी, सोलन में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के रूप में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक जिम्मेदारी निभा रही थीं। धृति ने बताया कि सफलता में एनसीसी प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैडेट जीवन में उन्होंने सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने दोनों प्रश्नपत्रों के पिछले करीब दस वर्षों के प्रश्नपत्रों का अध्ययन कर नोट्स तैयार किए और नियमित पुनरावर्तन किया। जून में आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 15 दिन मिले, फिर भी उन्होंने लक्ष्य नहीं छोड़ा। उन्होंने सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों, भाई-बहनों और एनसीसी बटालियन को दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास बनाए रखने और लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने का आह्वान किया।

सात दिन में दिल्ली से बरामद हुए ऊना के दो नाबालिग

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। जिला ऊना पुलिस ने घर से लापता हुए दो नाबालिगों को सात दिन के भीतर दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया। इनमें 14 वर्षीय बालिका और 10 वर्षीय बालक शामिल हैं। दोनों 14 सितंबर की शाम करीब छह बजे घर से लापता हुए थे। परिजनों की शिकायत पर 15 सितंबर को थाना बंगाणा में मामला दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की। थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानव स्रोतों की मदद से विभिन्न स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान दोनों के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 सितंबर को उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के बाद दोनों को ऊना लाया जा रहा है। एसपी ऊना सचिन हीरेमठ ने लोगों से अपील की कि बच्चा लापता होने पर बिना देरी पुलिस को सूचना दें। समय पर सूचना मिलने से सुरक्षित बरामदगी में मदद मिलती है।

निर्देश नेशनल हाईवे, अन्य सड़कों और संपर्क मार्गों के जंक्शनों पर आवश्यक प्रबंध करें

सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को दी जा रही कैशलैस इलाज की सुविधा



अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए डेढ़ लाख रुपए तक के कैशलैस इलाज का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी तथा सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के संचालक इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अस्पतालों में पर्याप्त प्रबंध करें, ताकि सड़क दुर्घटना का कोई भी घायल इस सुविधा से वंचित न रहे। पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी भी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डाटा तुरंत संबंधित अस्पतालों के साथ साझा करें। मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए गंधर्वा राठौड़ ने ये निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में अभी हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल 14 लोगों को कैशलैस इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। जिला में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा के दौरान उपायुक्त ने सभी एसडीएम, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, नेशनल हाईवे और परिवहन विभाग के अधिकारियों को दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों को चिह्नित करने तथा इन स्थानों पर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है तो उसकी डिमांड भी भेजें। डीसी ने कहा कि नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों के जंक्शनों एवं चौक-चौराहों पर रोड की सही मार्किंग, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगे होने चाहिए। क्योंकि, इन जगहों पर दुर्घटनाओं की हर समय आशंका रहती है। उन्होंने नेशनल हाईवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नादौन, जलाड़ी, चील बाहल, लाहड़ और कोहली में नए हाईवे और विभिन्न संपर्क मार्गों पर विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि अगस्त महीने में जिला में 6 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 11 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हुई।

इस साल 31 अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं के 62 मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 43 था। उन्होंने बताया कि जिला में यातायात के नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए चालान भी किए जा रहे हैं। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

एनएसएस युवाओं के व्यक्तित्व विकास और प्रतिभा निखारने का प्रभावी मंच



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस परेड के लिए जिला स्तरीय पूर्व चयन (प्री-आरडी) शिविर आयोजित किया गया। 21 सितंबर को हुए शिविर में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और चयन प्रक्रिया में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने किया। उन्होंने विभिन्न महाविद्यालयों से पहुंचे एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और चयन समिति के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने स्वयंसेवियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि एनएसएस युवाओं के व्यक्तित्व विकास और प्रतिभा निखारने का प्रभावी मंच है। उन्होंने प्रतिभागियों से निष्ठा और अनुशासन के साथ प्रदर्शन कर जिला स्तर से राज्य स्तर और नॉर्थ जोन शिविर के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। एनएसएस सलाहकार समिति के समन्वयक डॉ. रवि प्रकाश भी मौजूद रहे। शिविर में राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं से नौ, शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से छह, राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से पांच, जुखाला से चार, श्री नयना देवी महाविद्यालय से तीन तथा झंडूता और गड़ालवीं से दो-दो स्वयंसेवी शामिल हुए। चयन प्रक्रिया में स्वयंसेवियों को शारीरिक दक्षता, अनुशासन, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और अन्य निर्धारित मापदंडों पर परखा गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

जूलिया ग्विन का दिलकश अंदाज

जूलिया ग्विन जर्मनी की एक मशहूर महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 2 जुलाई 1999 को जर्मनी में हुआ था। वह अपनी तेज रफ्तार, बेहतरीन तकनीक और मैदान पर शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। जूलिया ने जर्मन राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है।



स्पोर्ट्स विंडो

श्रेयस अय्यर बोले- गेंद के ज्यादा टर्न होने से बल्लेबाजी मुश्किल थी

एजेंसी, सानो। जापान के खिलाफ पांच-पांच ओवर के रोमांचक मुकाबले में दो रन से जीत हासिल करने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की पिच को



बल्लेबाजी के लिए मुश्किल बताया। बारिश के कारण मुकाबला पांच ओवर प्रति पारी का कर दिया गया था। अय्यर ने कहा कि पिच पर गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी और भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन की गति समझने में परेशानी हुई। भारत ने चार विकेट पर 32 रन बनाए, जिसमें अय्यर ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने जापान को 30 रन पर रोककर मैच अपने नाम किया। अय्यर ने कहा कि ऐसे छोटे मुकाबलों में कोई भी टीम जीत सकती है। उन्होंने जापानी टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उसने आखिरी गेंद तक शानदार मुकाबला किया। जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग ने भी टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि जापान दुनिया की मजबूत टीम को आखिरी गेंद तक चुनौती देने में सफल रहा।

'तिरंगे को ऊंचा उठते देखना सबसे बड़ा एहसास': शेफाली वर्मा

एजेंसी, निशिन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार



स्वर्ण पदक जीतने के बाद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा लहराते देखना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा एहसास है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शेफाली ने जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने 29 गेंदों पर 48 रन बनाने के साथ दो ओवर में सिर्फ तीन रन देकर दो विकेट भी लिए। भारत ने 216 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 69 रन पर सिमट गई। शेफाली ने कहा कि टीम जीत का जश्न डिनर के साथ मनाएगी और घर लौटने के बाद परिवार के साथ भी खुशी साझा करेगी। उन्होंने बताया कि इस बार टीम एथलीट विलेज के बजाय होटल में ठहरी थी, इसलिए अन्य भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा मुलाकात नहीं हो सकी।

एशियाई खेल: जय मीणा सॉफ्ट टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

एजेंसी, नागोया। भारत के जय मीणा ने मंगलवार को एशियाई खेलों की सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना



ली। जय ने ग्रुप डी मुकाबले में पाकिस्तान के अराइन हुसैन को 4-0 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना फिलीपींस के शेरविन नुगुइट से होगा। भारत के एक अन्य खिलाड़ी आर्यन ठाकुर ने मंगोलिया के अल्टांगेरेल बोल्ड-एर्डेने को 4-0 से हराया, लेकिन अगले मुकाबले में चीनी ताइपे के चेन पो-यी से 0-4 से हार गए। महिला एकल में आध्या तिवारी ने पाकिस्तान की कायनात शलवानी को 4-0 से शिकस्त दी। हालांकि, इससे पहले ग्रुप डी के शुरुआती मुकाबले में उन्हें थाईलैंड की अलीशा जिग्लर के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। अब जय मीणा से भारत को क्वार्टर फाइनल में पदक की उम्मीदें हैं।

एशियाई खेल: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने पदक किया पक्का

एजेंसी, नागोया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने मंगलवार को एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में जापान को 3-0 से



हराकर अपना पदक पक्का कर लिया। भारत ने पिछले चरण में रजत पदक जीता था। अब बुधवार को सेमीफाइनल में उसका सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। लक्ष्य सेन ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। उन्होंने दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी कोडाई नाराओका को 11-21, 21-5, 21-19 से हराया। सेन निर्णायक गेम में 14-19 से पिछड़ रहे थे, लेकिन लगातार सात अंक हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। इसके बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा आयुष शेट्टी ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर भारत को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिलाई। वहीं, भारतीय महिला टीम को क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा और उसका एशियाई खेलों का अभियान समाप्त हो गया।

जापान से हारते-हारते बची टीम इंडिया, सिर्फ 2 रन से मिली जीत

बारिश से 5-5 ओवर का हुआ मुकाबला, भारत ने 32 रन बनाए और जापान 30 रन तक ही पहुंच सका

एजेंसी, सानो (जापान)

लगातार दो बार की टी-20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया मंगलवार को 41वीं रैंकिंग वाले जापान के खिलाफ हारते-हारते बची। एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट मुकाबले शुरू होने से पहले भारत और जापान के बीच यह मुकाबला रखा गया था।

जापान के सानो इंटरनेशनल ग्राउंड पर बारिश के कारण मुकाबला 5-5 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 32 रन बनाए। जवाब में जापान 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 30 रन ही बना सका। जापानी टीम को आखिरी ओवर में 8 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने 5 रन ही दिए। इस जीत के साथ भारत आईसीसी टी-20 टीम रैंकिंग में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर फिर से नंबर-1 बन गया है।

बारिश के कारण मैच ढाई घंटे की देरी से शुरू हुआ। इसलिए ओवर्स में कटौती की गई। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 16 रन बनाए। ओपनर अभिषेक शर्मा जीरो, संजू सैमसन 9 रन और ईशान किशन 3 रन पर आउट हुए। इस मुकाबले का आयोजन दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है।

यह टीम इंडिया का 5-5 ओवर का पहला मैच है। आमतौर पर बारिश के कारण मैच के ओवर कम किए जाते हैं। हालांकि, टी-20 इंटरनेशनल में 5-5 ओवर से कम का मैच नहीं खेला जा सकता। इससे पहले भारत 9-9 और 11-11 ओवर के मैच खेल चुका है।



भारत की टी-20 इंटरनेशनल में 200वीं जीत

भारत टी-20 इंटरनेशनल में 200 जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है। इसमें सुपर ओवर से मिली जीत भी शामिल हैं। भारत ने यह उपलब्धि जापान के खिलाफ सानो में 2 रन की जीत के साथ हासिल की।

संभावित टीमें

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह।

जापान: लचलान यामामोटो-लेक, रियो सकुरानो-थॉमस, केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), बेंजामिन इटो-डेविस, वातरू मियाउची (विकेटकीपर), एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर), चार्ली हारा-हिंज, इब्राहिम ताकाहाशी, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, मकोतो तानियामा और शोमा सुगाया-स्लेटर।

मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, चोटों के कारण लिया संन्यास

एजेंसी, लंदन



इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने चोटों की लगातार समस्या के चलते मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 36 वर्षीय वुड ने 11 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में इंग्लैंड के लिए कई यादगार प्रदर्शन किए और 2019 वनडे विश्व कप तथा 2022 टी20 विश्व कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। वह चार एशेज श्रृंखलाओं में भी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

वुड को हाल के वर्षों में लगातार चोटों से जूझना पड़ा। पिछले साल बाएं घुटने की सर्जरी के बाद उन्हें करीब आठ महीने तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज श्रृंखला में वापसी की। हालांकि, पहले टेस्ट में केवल 11 ओवर गेंदबाजी करने के बाद उनके उसी घुटने में सूजन आ गई। इसके चलते उन्हें इलाज के लिए स्वदेश लौटना पड़ा और उसके बाद वह इंग्लैंड की टीम में वापसी नहीं कर सके।

संन्यास की घोषणा करते हुए वुड ने कहा कि उन्होंने हमेशा मजबूती से वापसी करने, चोटों को पीछे छोड़ने और अपनी क्षमता साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इस बार वह यह लड़ाई हार गए। वुड ने टेस्ट क्रिकेट में 38 मैच खेलकर 119 विकेट हासिल किए। वनडे में उन्होंने 70 मैचों में 80 विकेट लिए, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 38 मैचों में उनके नाम 54 विकेट रहे। उनकी तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम की महत्वपूर्ण ताकत रही।

वुड के संन्यास के साथ इंग्लैंड क्रिकेट ने एक ऐसे तेज गेंदबाज को खो दिया है, जिसने अपनी रफ्तार और जुझारू अंदाज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई। चोटों के बावजूद उन्होंने कई बार मैदान पर वापसी की और टीम की अहम जीतों में योगदान दिया।

भारत का एथलेटिक्स अभियान आज से शुरू

अविनाश, तजिंदरपाल व पारुल चौधरी समेत कई भारतीय पदक दावेदार मैदान में उतरेंगे

एजेंसी, आइची-नगोया



भारत एशियाई खेलों में बुधवार से अपने एथलेटिक्स अभियान की शुरुआत करेगा। 23 से 29 सितंबर तक चलने वाली एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह तूर, पारुल चौधरी और गुलवीर सिंह समेत कई भारतीय पदक दावेदार मैदान में उतरेंगे। नीरज चोपड़ा के चोट के कारण बाहर होने से पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत की चुनौती कुछ अलग होगी। उनकी जगह रोहित यादव और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता यश वीर सिंह भारतीय चुनौती संभालेंगे। रोहित ने इस सत्र में 87 मीटर से अधिक के दो शानदार थ्रो किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगस्त में भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट में आया, जहां उन्होंने 87.68 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था।

अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज में अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। घुटने की सर्जरी के कारण वह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले सके थे। वहीं, तजिंदरपाल सिंह तूर की नजरें एशियाई खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने पर होंगी।

पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करेंगी। वह 1500 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज में भी हिस्सा लेंगी। 2022 हांगझोऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की 4म400 मीटर रिले टीम का हिस्सा रहे राजेश रमेश को भी टीम में जगह मिली है। बाधा दौड़ की धाविका ज्योति याराजी भी लंबे समय तक चोट से बाहर रहने के बाद प्रतियोगिता में वापसी करेंगी। उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। लंबी कूद के स्टार मुरली श्रीशंकर भी मजबूत लय के साथ एशियाई खेलों में उतरेंगे। उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दूसरा रजत पदक जीता था। तेजस्विन शंकर, गुलवीर सिंह, अंसी सोजन, प्रवीण चित्रवेल और विथ्या रामराज भी भारतीय टीम के प्रमुख नामों में शामिल हैं। गुलवीर सिंह ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में दो पदक जीते थे। अंसी सोजन लंबी कूद की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं, जबकि प्रवीण चित्रवेल और विथ्या रामराज भी हांगझोऊ में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। भारत एथलेटिक्स की 50 पदक स्पर्धाओं में से 41 में हिस्सा लेगा।

एशियाई खेल: 11 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं स्मृति मंधाना

एजेंसी, आइची-नगोया



श्रीलंका के खिलाफ 79 रन की पारी के दौरान हासिल की उपलब्धि

भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। श्रीलंका के खिलाफ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक मुकाबले में 79 रन की शानदार पारी के दौरान मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं।

मंधाना ने 45 गेंदों पर पांच चौकों और सात छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 175.56 रहा। उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई और दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 29 गेंदों पर तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 48 रन बनाए।

मंधाना महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 179 मैचों की 172 पारियों में 31.00 की औसत और 127.47 के स्ट्राइक रेट से 4,867 रन बनाए हैं। उनके नाम दो शतक और 37 अर्धशतक हैं तथा उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन है।

महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मंधाना 5,411 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 120 मैचों में 47.88 की औसत से ये रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन है। मंधाना ने नौ टेस्ट मैचों में 52.53 की औसत से 788 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम दो शतक और पांच अर्धशतक हैं तथा उनका सर्वोच्च स्कोर 149 रन है।

कुल मिलाकर मंधाना ने 308 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 11,066 रन बनाए हैं, जिसमें 18 शतक शामिल हैं। वह महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन और सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मंधाना व शेफाली की 99 रन की साझेदारी के बाद हरमनप्रीत कौर 17 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ऋचा घोष ने 22 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन की तेज पारी खेलकर भारत को 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

चांदी 2,412 व सोना 1,205 रुपए सस्ता

दो दिनों में चांदी के दाम 4 हजार रुपए से ज्यादा घटे, 2.33 लाख पहुंची

एजेंसी, मुंबई

सोने-चांदी के दाम में मंगलवार यानी 22 सितंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,205 रुपए घटकर 1.52 लाख रुपए पर आ गया है।

एक किलो चांदी की कीमत 2,412 रुपए कम होकर 2.33 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले कल भी चांदी 1,916 रुपए और सोना 390 रुपए सस्ता हुआ था। चांदी दो दिन में 4 हजार से ज्यादा और सोना 1,500 रुपए सस्ता हुआ है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' ने 3 साल में पहली बार बढ़ाई ब्याज दरें बढ़ाई है। इससे सोने के दाम में गिरावट है। हालांकि भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने को सपोर्ट मिल सकता है, जिससे निवेशक इसे सुरक्षित निवेश के रूप में फिर से चुन सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बाजार में अभी भी कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़ी गिरावट पर खरीदारी का अवसर भी बन सकता है।

इस साल सोना 19 हजार रुपए हुआ महंगा



इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 20 हजार रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10द्द सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.52 लाख रुपए पर है। वहीं चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.33 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था।

सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 74,529 पर हुआ बंद और निफ्टी भी 85 अंक फिसला

एजेंसी, मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 22 सितंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 329 अंक टूटकर 74,529 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 85 अंक गिरकर 23,329 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में एफएमसीजी, आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बना रहा। निवेशकों के बीच बिकवाली के चलते कई प्रमुख शेयरों में कमजोरी रही। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दबाव बना रहा और अंत में दोनों सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। इसी बीच वरमोरा ग्रैनिटो का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार से खुल गया है। निवेशक इस आईपीओ में 24 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी आईपीओ के माध्यम से करीब 708.02 करोड़ रुपये जुटाने की योजना लेकर बाजार में उतरी है। बाजार विशेषज्ञों की नजर अब आगामी कारोबारी सत्रों में वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन पर रहेगी।

होंडा क्यूसी3, सीबी500 और सीबी350 की कीमतें घोषित

एजेंसी, मुंबई

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने मंगलवार को क्यूसी3, सीबी500 और नई सीबी350 रेंज की कीमतों की घोषणा की। कंपनी के अनुसार, होंडा क्यूसी3 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1.35 लाख रुपये रखी गई है। यह फिलहाल दिल्ली के अलावा आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में चुनिंदा होंडा रेडविंग डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। क्यूसी3 को स्मार्ट फैमिली इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में विकसित किया गया है।

कंपनी के मुताबिक, पूरी तरह चार्ज होने पर इसकी रेंज 145 किलोमीटर है और इसमें 32 लीटर का स्टोरेज दिया गया है। इसे मैट फोटोन ग्रे मेटैलिक, पर्ल प्रिसियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल साइरेन ब्लू रंगों में पेश किया गया है।

होंडा सीबी500 को तीन वेरिएंट में उतारा गया है। इसकी बेंगलुरु में एक्स-शोरूम कीमत 2.75 लाख से 3.01 लाख रुपये तक है। इसमें 501 सीसी का इंजन दिया गया है। यह पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, पर्ल इग्नियस ब्लैक, मैट स्टील मेटैलिक और रिबेल रेड मेटैलिक रंगों में उपलब्ध होगी। वहीं, सीबी350 को सीबी350, सीबी350आरएस और सीबी350सी तीन संस्करणों में पेश किया गया है। इनकी बेंगलुरु में एक्स-शोरूम कीमत 1,95,200 से 2,04,700 रुपये तक है। ये मॉडल होंडा के बिगविंग डीलरशिप पर उपलब्ध होंगे।

तमिलनाडु में अब कक्षा 6-8 के छात्रों को भी मिलेगा मुफ्त नाश्ता

एजेंसी, चेन्नई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को चेन्नई में विस्तारित पेरुंथलैवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की। उन्होंने छात्रों को नाश्ता परोसा। उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट भी किया। यह कार्यक्रम चेन्नई के तिरुवन्मियूर स्थित गांधी ग्रामम के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में शुरू किया गया। विजय ने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। पहले इस योजना का लाभ कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मिलता था। अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्र भी इसके दायरे में आ गए हैं।

इससे राज्य के 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के विस्तार के लिए 217.63 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए हैं। इसके साथ योजना का कुल बजट 724 करोड़ रुपए हो गया है।

इस योजना का नाम पहले चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम था। अब इसका नाम बदलकर पेरुंथलैवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम कर दिया गया है। यह नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में रखा गया है।



2 जिलों में पेरुंथलैवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम नहीं होगी लागू

पेरुंथलैवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम योजना मंगलवार से पूरे राज्य में लागू हो रही है। हालांकि, चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में इसे अभी लागू नहीं किया गया है। आगामी विधानसभा उपचुनावों के कारण इन दोनों जिलों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसी वजह से वहां योजना लागू नहीं की जा रही है।

पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ जांच के आदेश

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिपोर्ट और कानूनी सलाह के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ सीएमआरएल मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने पुलिस और अपराध शाखा को मामले में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला कोच्चि स्थित खनिज कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीणा की बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक के बीच वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि सीएमआरएल ने एक्सालॉजिक को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि कथित तौर पर इसके बदले कोई सेवा नहीं दी गई। ईडी ने विजयन पर कंपनी को लाभ पहुंचाने के बदले 3.28 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने राज्य के डीजीपी से मामला दर्ज करने की मांग भी की थी।

हूतियों के खिलाफ सऊदी की मदद करेगा ब्रिटेन

हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरेगा; जंग से 1.2 लाख यमन के लोग बेघर

एजेंसी, लंदन/रियाद



यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इस बीच ब्रिटेन ने सऊदी को मदद देने का फैसला किया है। सोमवार को न्यूयॉर्क जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम ने कहा ब्रिटेन एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर देगा। यानी हवा में उड़ते सऊदी लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जा सकेगा। इधर लड़ाई का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। यूएन के मुताबिक, लड़ाई बढ़ने से अब तक 1.2 लाख से ज्यादा यमन के लोग बेघर हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से ज्यादा यमनी शरणार्थी लाल सागर पार कर जिबूती पहुंचे हैं।

ब्रिटेन सऊदी अरब की मदद के लिए एक ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) का वॉयजर टैंकर विमान भेज सकता है। यह विमान साइप्रस में मौजूद आरएएफ अक्रोटिरी एयरबेस से काम करेगा। वॉयजर विमान का काम हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरना है। इससे लड़ाकू विमान बिना नीचे उतरे ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं।

ब्रिटेन की वायुसेना के पास ऐसे 9 वॉयजर विमान हैं। इनमें 8 सैन्य इस्तेमाल के लिए हैं व एक विमान सामान्य यानी सिविलियन रजिस्ट्रेशन वाला है। जरूरत पड़ने पर उसे भी सैन्य काम में लगाया जा सकता है। सऊदी अरब को दी जा रही यह मदद कुछ हफ्तों के लिए होगी। ब्रिटेन इस साल पहले ही सऊदी अरब में स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन व मिसाइल जैसे हवाई हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है।

लाल सागर के तट के पास अहम द्वीपों पर कब्जा

यमन के हूतियों ने इस महीने लाल सागर के तट की ओर तेजी से बढ़ते हुए बाब-अल-मंदब स्ट्रेट के पास के इलाकों पर कब्जा किया है। यह स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसलिए इस इलाके में लड़ाई का असर समुद्री रास्तों पर भी पड़ सकता है। हूतियों की इस बढ़त के बाद सऊदी अरब ने तटीय इलाकों में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ हूतियों ने सऊदी अरब के शहरों और बुनियादी ढांचे पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया है।